भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट आकलन के साथ वास्तविक	1.1.3	6
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट	1.1.4	7
राज्य के संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.2.2	11
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	12
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	15
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.3.2	18
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	19
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग	1.3.4	19
त्यक्त राजस्व	1.3.5	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	20
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1.4.1	21
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	22
भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	22
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	22
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	23
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	23
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	24
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	26
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	29
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	1.6.5	30
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण	1.6.6	30
व्यय की गुणवत्ता	1.7	33
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	34
व्यय के इस्तेमाल की दक्षता	1.7.2	35
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	38
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	38

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	38
निवेश एवं वापसी	1.8.3	39
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	40
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	41
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	41
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	41
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	42
ऋणों एवं अग्रिमों के वापसी का संदेहास्पद होने के कारण राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति	1.9.3	44
संरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन	1.9.4	44
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.9.5	45
ऋण प्रबंधन	1.10	45
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	45
ऋण धारणीयता	1.10.2	46
राजकोषीय असंतुलन	1.11	47
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	48
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय पोषण का स्वरूप	1.11.2	49
घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता	1.11.3	50
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	51
अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	53
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	53
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	54
वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.4	55
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	55
सतत् बचत	2.4.2	56
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.4.3	60
वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.4	61
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	61
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	62
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	62
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.8	63
व्यय का वेग	2.5	63
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	63
अनुदान संख्या 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव	2.7	64

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निर्धारित अनुसूची का अनुसरण नहीं किया जाना	2.7.1	64
बढ़ा हुआ बजट आकलन	2.7.2	65
अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान	2.7.3	66
निधियों का विलम्ब से विमुक्त किया जाना	2.7.4	67
व्यय का वेग	2.7.5	67
विभागीय व्यय के आँकडों का असमाशोधन	2.7.6	68
निधि आहरित कर बैंक खाते तथा व्यक्तिगत बही खाते में रखना	2.7.7	68
विस्तृत आकस्मिक विपत्र का अप्रस्तुतीकरण	2.7.8	69
निधि का अनियमित आहरण	2.7.9	69
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.8	70
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	73
परिचय	3.1.1	73
पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग और शहरी विकास विभाग में बकाये उ.प्र.प. की स्थिति	3.1.2	74
अनुदानों को निर्गत करने में विलम्ब	3.1.3	75
अनुदान का अनुचित संवितरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण	3.1.4	76
अनुदान का अवरूद्धिकरण एवं अनुपयोग	3.1.5	77
कल्याण विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा	3.2	81
परिचय	3.2.1	81
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण की प्रवृति	3.2.2	82
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के जमा करने में विलम्ब	3.2.3	84
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से योजना निधि का आहरण	3.2.4	85
वित्तीय वर्ष के अन्त में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण	3.2.5	86
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से बार-बार निधियों का आहरण	3.2.6	87
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खाते में रखना	3.2.7	88
लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव	3.2.8	89
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा	3.3	89
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.3.1	89
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.3.2	90
दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	91
निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना	3.5	91
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.6	92

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-ए	झारखण्ड का परिचय	97
परिशिष्ट 1.1 भाग-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	98
परिशिष्ट 1.1 भाग-सी	वित्त लेखे का अभिन्यास	98
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	99
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़ें	100
परिशिष्ट 1.4 भाग-ए	वर्ष 2013-14 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	103
परिशिष्ट 1.4 भाग-बी	31 मार्च 2014 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	106
परिशिष्ट 1.5	तेरहवें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे	108
परिशिष्ट 1.6 भाग-ए	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	113
परिशिष्ट 1.6 भाग-बी	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण	114
परिशिष्ट 2.1	₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी	115
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2013-14 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	117
परिशिष्ट 2.3	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	122
परिशिष्ट 2.4	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	124
परिशिष्ट 2.5	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	126
परिशिष्ट 2.6	₹ एक करोड़ एवं उससे ज्यादा की बचत, जो अभ्यर्पित नहीं की गई, की विवरणी	127
परिशिष्ट 2.7	30 और 31 मार्च 2014 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक अभ्यर्पित की गई राशि	130
परिशिष्ट2.8	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	131
परिशिष्ट 2.9	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2013-14 के दौरान असमाशोधित रह गई	132
परिशिष्ट 2.10	बढ़ा हुआ बजट आकलन	134
परिशिष्ट 2.11	सतत् बचत	136
परिशिष्ट 2.12	रिक्त पदों के लिये परिहार्य बजट प्रावधान	136
परिशिष्ट 2.13	अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान	137

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 2.14	व्यय का वेग (राज्य स्तरीय)	138
परिशिष्ट 2.15	व्यय का वेग (क्षेत्रीय इकाईयों)	139
परिशिष्ट 2.16	विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	140
परिशिष्ट 2.17	डी.सी. विपत्र के अप्रस्तुतीकरण का सारांश	141
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2014 तक वर्ष 2006-2013 के दौरान वितरित किये गये सहायता अनुदान से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के ब्यौरे	143
परिशिष्ट 3.2	कल्याण विभाग में बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	145
परिशिष्ट 3.3	नि.म.ले.प. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	146
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची	149

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमश: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच में पायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है। आवश्यकतानुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से प्राप्त की गयी है।

3. अध्याय 3 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में लेन-देन लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2007, वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में यथासंशोधित, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त अन्य वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2014 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों से राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (भा.स.) से सीधे अंतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करती है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आवंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में '***परिशिष्ट 4.1***' प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013-14 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में वृद्धि तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) मानदंड 14.5 *प्रतिशत* के विरूद्ध 13.9 *प्रतिशत* रहा।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 2,665 करोड़ था। स.रा.घ.उ. से राजस्व अधिशेष की प्रतिशतता 'मध्यावधि राजकोषीय योजना' लक्ष्य के 1.8 के विरूद्ध 1.5 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2013-14 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 2,256 करोड़) स.रा.घ.उ. का 1.3 *प्रतिशत* था जो एफ.आर.बी.एम. एवं तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तीन *प्रतिशत* के अन्दर था।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण

- भारत सरकार ने राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को वर्ष 2012-13 के ₹ 2,621.91 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,601.80 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अंतरण किया। अत: वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रस्तुत नहीं करते हैं। राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हक.), झारखण्ड को ससमय व्यय प्रतिवेदित करने हेतु मापदण्ड के अभाव में इन अभिकरणों द्वारा समरूप लेखांकन पद्धति का अनुकरण नहीं किया जाता है।

संसाधन का संचरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 26,137 करोड़) में पिछले वर्ष से 5.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि, बजट आकलन की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,462 करोड़ कम थी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* केन्द्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ जबकि शेष राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2013-14 के दौरान, पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 4,218 करोड़ के सापेक्ष बढ़कर ₹ 4,722 करोड़ हो गई। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 15 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान 17 *प्रतिशत* रही। वर्ष 2013-14 के दौरान, स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2.7 थी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय सामान्य कोटि के राज्यों के औसत से कम

था। सामान्य कोटि के राज्यों की तुलना में राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दिया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय (₹ 28,416 करोड़) कुल व्यय का 83 *प्रतिशत* तथा स.रा.घ.उ. का 13.6 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 33 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 27 *प्रतिशत* हो गई। वर्ष 2013-14 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹ 17,184 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष 10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह राजस्व व्यय का 73 *प्रतिशत* रही।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा स्थायीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2012-13 के ₹ 6,950.32 करोड़ से घटकर ₹ 6,421.85 करोड़ हो गयी।

विकास व्यय पर जोर

- वर्ष 2013-14 के दौरान, विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष पाँच *प्रतिशत* की कमी हुई। वर्ष के दौरान, कुल व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 48 *प्रतिशत* थी और कुल व्यय में विकासात्मक पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी 17 *प्रतिशत* थी।

अर्पूण परियोजनाएँ

- मार्च 2014 तक निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं होने वाले 328 परियोजनायें थी जिसमें कुल ₹ 760.11 करोड़ अवरूद्ध थे।

सरकारी निवेशों की समीक्षा

- 31 मार्च 2014 को झारखण्ड सरकार ने सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों इत्यादि में ₹ 231.97 करोड़ का निवेश किया। निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2012-13 के ₹ 15 करोड़ (7.99 *प्रतिशत*) के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में ₹ 18 करोड़ (7.76 *प्रतिशत*) था।

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 37,594 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 7.8 *प्रतिशत* बढ़ा। इस वर्ष के ते.वि.आ. की सिफारिश 27.3 *प्रतिशत* के सापेक्ष राजकोषीय

दायित्व, स.रा.घ.उ. का 21.8 *प्रतिशत* था। सरकार ने सभी ऋणों की विमुक्ति के लिए निक्षेप निधि स्थापित नहीं किया।

ऋण प्रबंधन

- गैर-ऋण प्राप्तियों की बढ़ोतरी (संसाधन अंतराल) की पर्याप्तता वर्ष 2012-13 के (-) ₹ 39 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,275 करोड़ हो गई जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का सूचक था। ऋणगत राशि की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2012-13 के ₹ 1,814 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 110 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के दौरान स्थिर (10 *प्रतिशत*) रहा।

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट आकलन के कारण विशाल बचत

- वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 13,130.13 करोड़ की विशाल बचत हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत विशाल बचत राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में कार्यरत 15 विभागों में विगत पाँच वर्षों में सतत बचत भी देखी गई।

आकस्मिक निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 के दौरान 45 अवसरों पर आकस्मिक निधि से ₹ 336.33 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में वैसे व्यय करने हेतु आहरित किये गये जो न तो अप्रत्याशित और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 694.05 करोड़ की राशि बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किये गये जिसे भारत के संविधान की अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-13 के दौरान किये गये ₹ 9,803.97 करोड़ के अधिक व्यय को भी विनियमित किया जाना शेष था।

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2013-14 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों ने विभागों के कुल व्यय (₹ 30,463.22 करोड़) के 58.91 *प्रतिशत* एवं कुल प्राप्तियों (₹ 30,863.02 करोड़) के 41.55 *प्रतिशत* का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही से नहीं किया।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव हुआ।

अध्याय 3 वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

- 31 मार्च 2014 को वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आहरित सहायक अनुदान विपत्रों के विरूद्ध ₹ 6,543.82 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे जो निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के ससमय उपयोग को सुनिश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता के सूचक थे।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निधि का आहरण

- विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-14 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र पर आहरित ₹ 5,162 करोड़ की विशाल राशि जून 2014 तक बकाया रहा। योजना निधि, यद्यपि अविलम्ब भुगतान हेतु आवश्यक नही थी, बजट आवंटन की राशि को विपगत होने से बचाने के लिये वित्तीय वर्ष के अन्त में ए.सी. विपत्र पर आहरित किये गये।

स्वायत निकायों, प्राधिकरणों और अनुदानग्राही संस्थानों की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- सरकारी विभागों ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुदानग्राही निकायों के लेखे को ससमय प्रस्तुत नहीं किया।

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

- मार्च 2014 के अंत तक व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 2,597.50 करोड़ की एक विशाल राशि थी। विधान मंडल द्वारा पारित चालू वर्ष के बजट निधियों को अगामी वर्षों में व्यय करने के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण करना वित्तीय नियमों के विरूद्ध था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् किया गया था, 79714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, यह देश का 16वाँ सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1 भाग-ए*** में दर्शाया गया है। अंतिम दस वर्षों (वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14) के दौरान राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 13.69 *प्रतिशत* थी। सम्पूर्ण-भारत औसत के 21.92 *प्रतिशत* की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 40.4 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2013-14 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,72,773 करोड़ थी। राज्य की साक्षरता दर 44 *प्रतिशत* (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.63 *प्रतिशत* (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 46,524 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निर्धारित समय में राज्य के भीतर सरकारी तौर पर स्वीकृत उत्पादित समस्त सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक वृद्धि की प्रवृति को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	15.2	18.7	15.8	11.9	11.5
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,00,621	1,27,281	1,35,618	1,51,655	1,72,773
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर(*प्रतिशत*)	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9

स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के वेब साइट से।

झारखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के 14.5 *प्रतिशत* के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान 13.9 *प्रतिशत* की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, वर्ष 2009-14 के दौरान, झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) (14.5 *प्रतिशत*) सम्पूर्ण भारत के स.घ.उ. के सी.ए.जी.आर. (14.4 *प्रतिशत*) के लगभग बराबर था।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2013-14 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा को ***परिशिष्ट 1.1 भाग-बी*** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को ***परिशिष्ट 1.1 भाग-सी*** में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति को ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े ***परिशिष्ट 1.3*** में दिये गये हैं।

1.1.1 वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2012-13) के साथ-साथ चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4 भाग-ए*** वर्ष 2013-14 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
खण्ड क: राजस्व					**गैर योजना**	**योजना**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	**24769.56**	**26136.80**	राजस्व व्यय	**23399.87**	17184.41	6287.48	**23471.89**
कर राजस्व	8223.58	9379.79	सामान्य सेवायें	8696.49	9691.69	267.67	9959.36
गैर कर राजस्व	3535.63	3752.71	सामाजिक सेवायें	8308.59	4299.54	3915.80	8215.34
संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	8188.14	8939.32	आर्थिक सेवायें	6394.79	3193.18	2104.01	5297.19
भारत सरकार से अनुदान	4822.21	4064.98	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड क: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	4218.43	15.81	4706.69	4722.50
ऋण एवं अग्रिमो की वसूली	43.11	23.32	संवितरित की गई ऋण एवं अग्रिम	600.81	29.92	191.99	221.91
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	100.00	50.00	0.00	50.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	5199.00	4702.90	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2183.06	1996.92	0.00	1996.92
आकस्मिक निधि में स्थानांतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	14494.71	14275.26	लोक लेखा संवितरण #	13416.31	14094.33	0.00	14094.33
आरंभिक रोकड़ शेष	116.85	704.75	रोकड़ अंत शेष	704.75	1285.48	0.00	1285.48
कुल	**44623.23**	**45843.03**	**कुल**	**44623.23**	**34656.87**	**11186.16**	**45843.03**

स्रोत: वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे

**अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर*

#आँकड़े अन्य खाते जैसे कि विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन को शामिल नहीं करते है

पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये है:

- पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 1,367 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: कर राजस्व में ₹ 1,156 करोड़ (14 *प्रतिशत*), कर-भिन्न राजस्व में ₹ 217 करोड़ (छः *प्रतिशत*) तथा संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश

में ₹ 751 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी के कारण हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 757 करोड़ (16 *प्रतिशत*) से समायोजित हुआ।

- ते.वि.आ. द्वारा नियत किए गए स्वयं के कर-राजस्व (₹ 11,137.16 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,068.30 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरूद्ध राज्य का वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ क्रमश: ₹ 9,379.79 करोड़ (84 *प्रतिशत*) एवं ₹ 3,752.71 करोड़ (92 *प्रतिशत*) था। इस प्रकार, स्वयं के कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व़ ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक अनुमान से कम था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) वर्ष 2012-13 के राजस्व व्यय के लगभग समान रहा। तथापि, यह बजट आकलन के ₹ 30,435 करोड़ से 23 *प्रतिशत* कम था। वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,263 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में क्रमश: ₹ 94 करोड़ एवं ₹ 1,098 करोड़ की कमी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में पूँजीगत व्यय में ₹ 505 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी हुई। वृद्धि मुख्यत: परिवहन विभाग (₹ 492 करोड़) एवं ग्रामीण विकास (₹ 262 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली वर्ष 2012-13 के ₹ 43 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 23 करोड़ हुई।
- लोक ऋण की प्राप्तियों एवं इसके पुनर्भुगतान पिछले वर्ष से घटकर क्रमश: ₹ 496 करोड़ (10 *प्रतिशत*) एवं ₹ 186 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) हो गया।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ घटकर ₹ 220 करोड़ (दो *प्रतिशत*) हो गयी जबकि संवितरण बढ़कर ₹ 677 करोड़ (पाँच *प्रतिशत*) हो गया।
- उपरोक्त लेन-देन का निवल प्रभाव पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 580.73 करोड़ की वृद्धि थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ. आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन *प्रतिशत* तक

सीमित करना था। ते.वि.आ. ने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को सम्बद्ध करते हुए राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की।

तदुनसार, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के साथ-साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) में कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संशोधित लक्ष्य के अनुसार (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना था, (ii) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन *प्रतिशत* करना था तथा (iii) वर्ष 2013-14 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 27.3 *प्रतिशत* करना था।

तालिका 1.2 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, एम.टी.एफ.पी., ते.वि.आ. एवं राज्य के बजटीय दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2013-।4 के दौरान प्रमुख राजकोषीय चर से संबंधित लक्ष्य को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2013-14				
	राज्य के लिए ते. वि. आ. का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. के तहत लक्ष्य	बजट के तहत लक्ष्य	एम.टी.एफ. पी. के अनुमान	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व हानि(-)/राजस्व आधिक्य(+)	शून्य	शून्य	+1.83	+1.80	+1.5
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	3.00	3.00	2.36	2.60	1.3
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	27.3	27.3	बजट में उपलब्ध नहीं	25.0	21.8

राज्य ने राजस्व घाटे से पृथक होकर वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को राजस्व आधिक्य (₹ 946 करोड़) में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटा को छोड़कर निरन्तर सुधार करते हुए वर्ष 2013-14 में राजस्व आधिक्य ₹ 2,665 करोड़ प्राप्त किया।

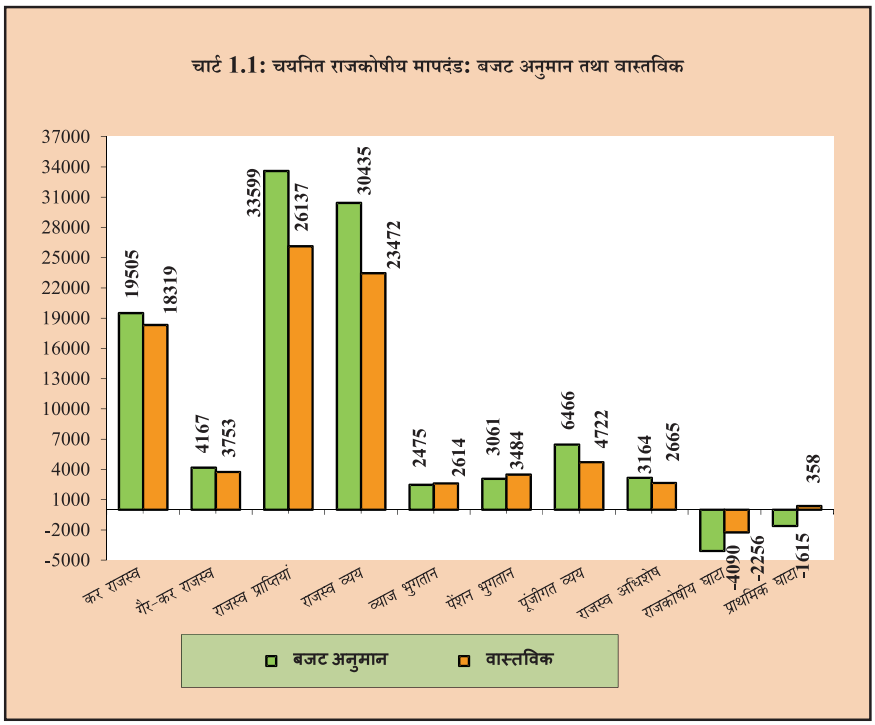
वर्ष 2013-14 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे (₹ 2,256 करोड़) की प्रतिशतता 1.3 था जो ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुमानित सीमा तीन *प्रतिशत* के भीतर था। यह एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 2.60 *प्रतिशत* के सन्निकट था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 21.8 *प्रतिशत* था जो ते.वि.आ. तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 27.3 *प्रतिशत* के अनुमान के काफी भीतर था। इस वर्ष ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात भी एम.टी.एफ.पी. के 25 *प्रतिशत* के लक्ष्य के काफी भीतर था।

1.1.3 बजट अनुमान के साथ वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों में विचलन इच्छित राजकोषीय लक्ष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य नहीं करने को संकेतिक करते हैं जो कई कारणों से होते हैं, जिसमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में तथा कुछ सरकार के नियंत्रण में नहीं होते।

चार्ट 1.1 वर्ष 2013-14 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड के बजट अनुमान तथा वास्तविक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय, ब्याज एवं पेंशन भुगतान को छोड़कर, वर्ष 2013-14 के राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान से कम थी। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 7,462 करोड़) का मुख्य कारण राज्य

बजट आकलनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में अपेक्षाकृत कम राशि की प्राप्ति (₹ 5,862 करोड़) थी। वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 6,963 करोड़) में कमी का कारण सामाजिक सेवाओं (₹ 4,191 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 2,862 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में ह्रास होना था।

निर्धारित बजट से सामाजिक सेवाओं (₹ 454 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1,227 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 1,744 करोड़ कम था जो राज्य के किये ध्यान देने की बात है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजट को राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के राज्य बजट में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए प्रावधान किया है जिसके ब्यौरे नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: बजट प्रस्ताव तथा महिलाओं के लिए व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम	बजट आकलन	व्यय	अभ्यर्पण
किशोरी शक्ति योजना	2.20	0.30	1.90
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम	57.54	25.14	32.40
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	9.00	3.19	5.81
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15.00	12.79	2.21
महिलाओं एवं किशोरी कन्या के दक्षता विकास की योजना	3.00	0.00	3.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि:

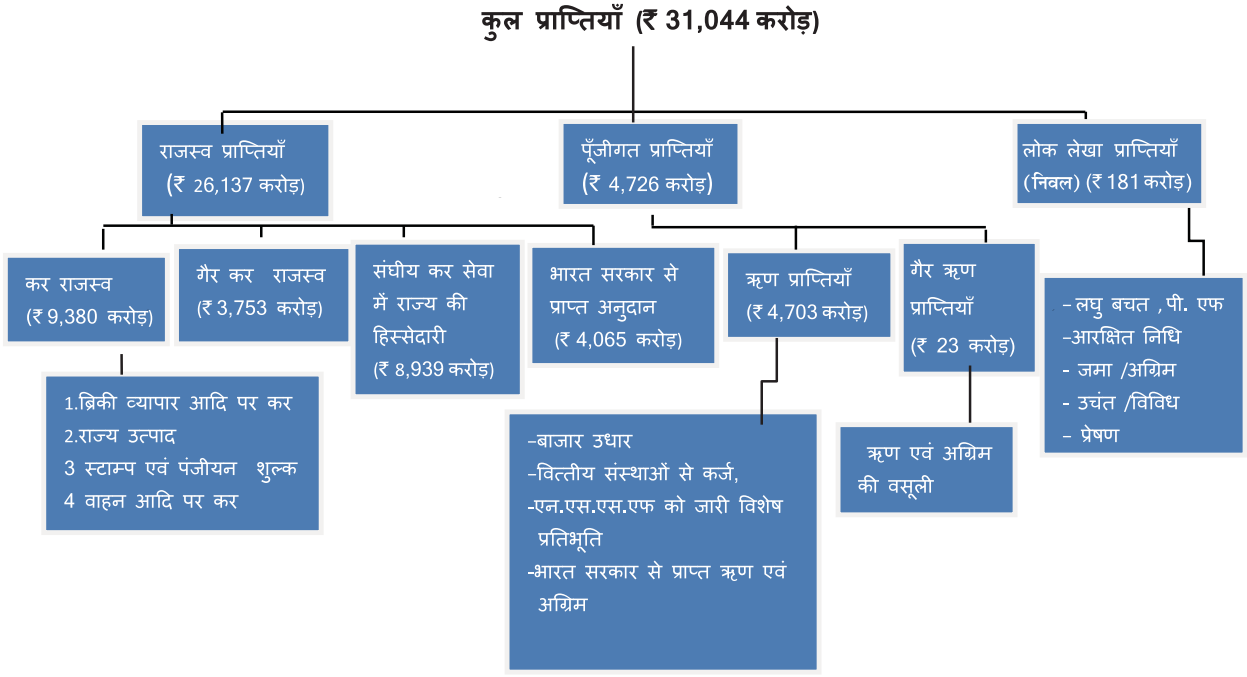
- वर्ष 2013-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना की ₹ 2.20 करोड़ में से केवल ₹ 0.30 करोड़ व्यय किया गया जिसके कारण ₹ 1.90 करोड़ (86 *प्रतिशत*) की बचत हुई।
- इसी प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम के अन्तर्गत प्रावधानित ₹ 57.54 करोड़ में से केवल ₹ 25.14 करोड़ व्यय किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 32.40 करोड़ (56 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

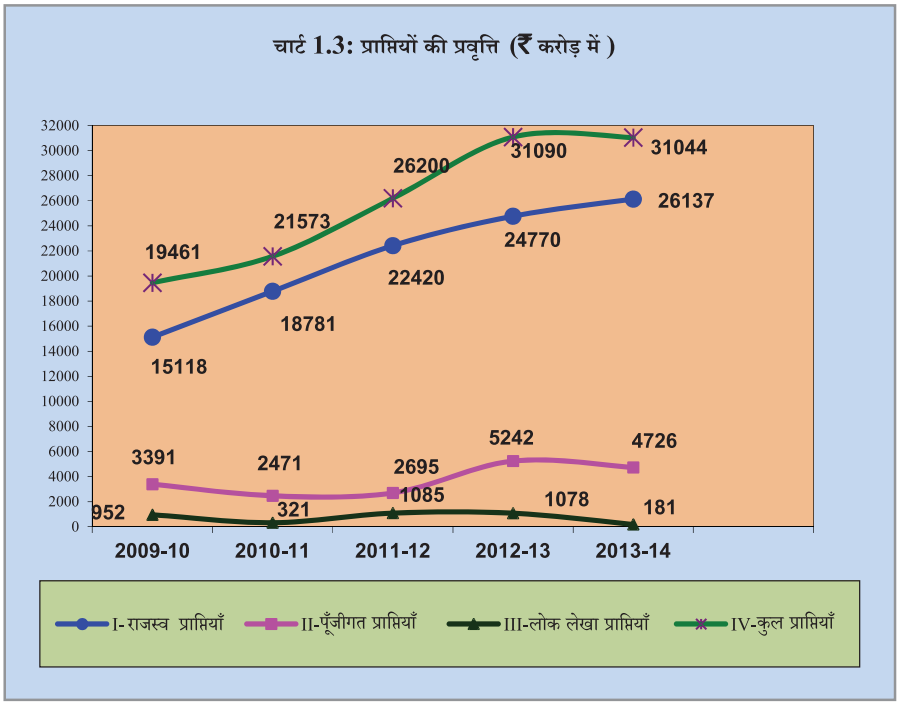
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

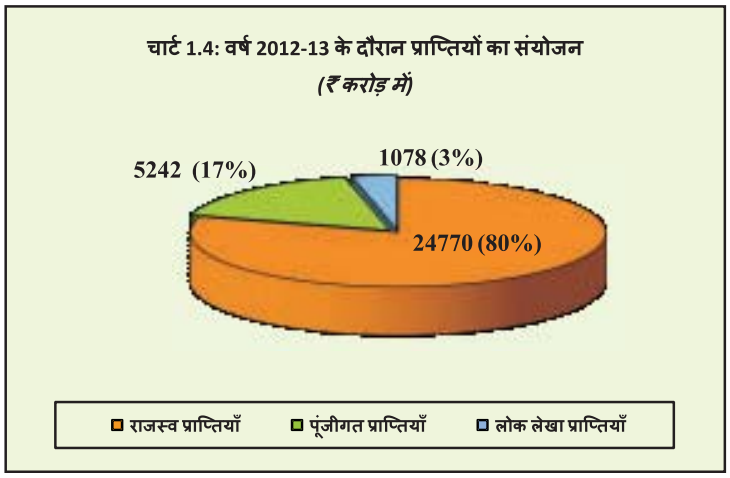
राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएँ हैं जो राज्य सरकार के संसाधन है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात् लोक खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण, जैसा कि वार्षिक वित्त लेखे में वर्णित है, को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान संसाधनों के घटक तथा उप-घटक को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट को **चार्ट 1.2** में दिया गया है। **चार्ट 1.3** वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है।

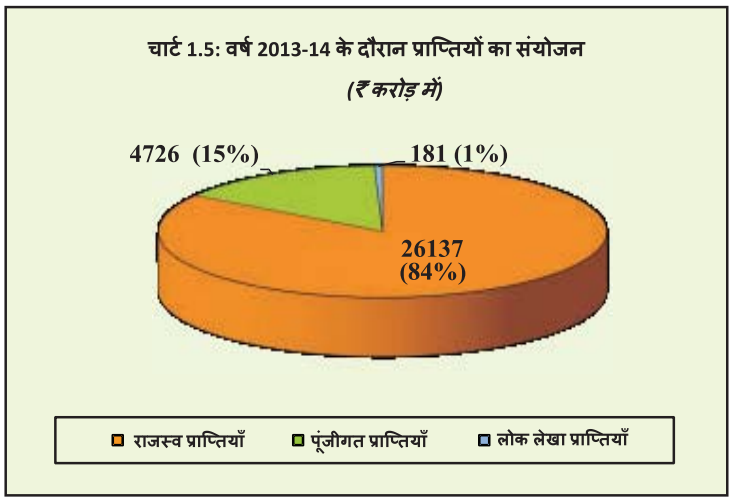
चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





चार्ट 1.4 एवं **चार्ट 1.5** क्रमश: वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते है।





चार्ट 1.2 एवं **चार्ट 1.5** से देखा जा सकता है कि

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 के ₹ 19,461 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 31,044 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष के सापेक्ष कुल प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 46 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 78 *प्रतिशत* से 87 *प्रतिशत* के बीच दोलित रही। पूँजीगत प्राप्तियों में तुलनात्मक उच्चतर वृद्धि के कारण यह वर्ष 2010-11 के 87 *प्रतिशत से* घटकर वर्ष 2011-12 में 86 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2012-13 में 80 *प्रतिशत* हो

गई। तथापि, वर्ष 2013-14 में ऋण एवं लोक लेखा प्राप्तियों में कमी के कारण यह बढ़कर 84 *प्रतिशत* हो गई।

- पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण में कमी के कारण वर्ष 2013-14 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 10 *प्रतिशत* घटी। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 8.65 *प्रतिशत* था।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 1,078 करोड़ (कुल प्राप्तियों का तीन *प्रतिशत*) से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 181 करोड़ (कुल प्राप्तियों का एक *प्रतिशत*) हो गयी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के वैसे विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिसकी स्थिति दयनीय के रूप में पहचान की गई है, के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[1] को बड़ी मात्रा में निधियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करती रही है। वर्तमान प्रक्रिया में, यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है। इस प्रकार, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं लिया गया है। अत: वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता का संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशि को **तालिका 1.4** में दिखाया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,601.80 करोड़ की केन्द्रीय राशि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित किया गया। भारत सरकार द्वारा सहयोग प्राप्त योजनाएँ जिसकी राशि हस्तांतरित की गई एवं संबंधित राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को **तालिका 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

[1] राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में गैर-सरकारी संगठन सहित वैसे संगठन/संस्था शामिल है जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से प्राधिकृत है जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की निधि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणो को सीधे हस्तांतरित राशि	
		2012-13	2013-14
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	809.17	621.43
इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	138.27	352.69
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम ए.ए.जे.ई.ई.वी.आई.के.ए.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	10.23	48.44
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	561.84	450.11
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार के लिए मानव संसाधन	(i) झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन नियंत्रण संस्था (ii) झारखण्ड एड्स नियंत्रण संस्था	281.32	317.27
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	307.23	243.29
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	88.50	97.50
गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ	गैर सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संस्थाएँ	425.35	471.07
कुल		**2621.91**	**2601.80**

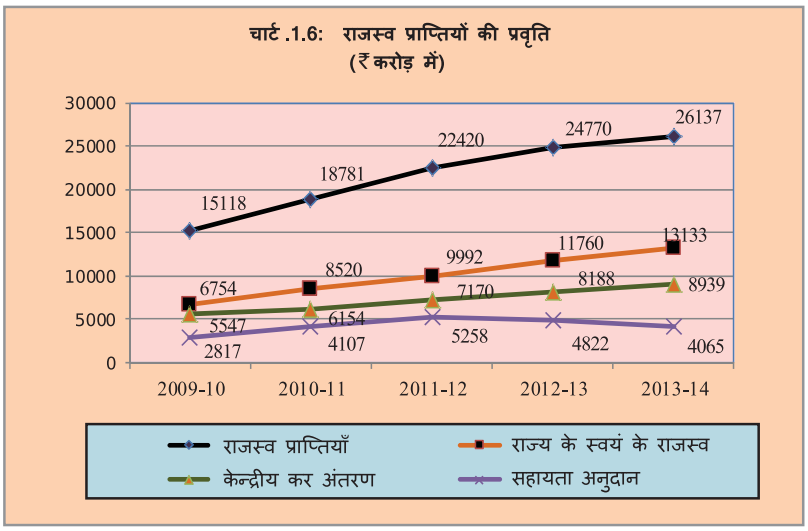
स्रोत: वित्त लेखे का परिशिष्ट VII

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से राशियों का प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण होने के कारण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के अनुचित उपयोग का जोखिम था। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को व्यय का ससमय प्रतिवेदन एवं उचित दस्तावेज के साथ समरूप रेखांकन पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित ऐसी राशियों के पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के

संघटन और प्रवृत्तियों को ***परिशिष्ट 1.3*** में दिखाया गया है एवं **चार्ट 1.6** में भी चित्रित किया गया है।



राज्य राजस्व प्राप्तियों की विवेचना से उजागर हुआ कि:

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 2012-13 के दौरान 10.5 *प्रतिशत* की वृद्धि के बदले पिछले वर्ष के सापेक्ष 5.5 *प्रतिशत* बढ़ी। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 7,462 करोड़ कम थी। वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व प्प्तियों का सी.ए.जी.आर. 14.67 *प्रतिशत* था।

- वर्ष 2009-10 के दौरान स्वयं का कर, कर-भिन्न राजस्व से दोगुना था जो वर्ष 2013-14 के दौरान बढ़कर 2.5 गुना हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान से कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* था जबकि शेष राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान रहा।

- वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 26,137 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) ₹ 9,380 करोड़ (36 *प्रतिशत*), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 3,753 करोड़ (14 *प्रतिशत*), केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) ₹ 8,939 करोड़ (34 *प्रतिशत*) और भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 4,065 (16 *प्रतिशत*) सम्मिलित था। पिछले वर्ष की अपेक्षा ओ.टी.आर., एन.टी.आर. तथा सी.टी.टी. के तहत प्राप्तियों में क्रमश: 14 *प्रतिशत*, छ: *प्रतिशत*, तथा नौ *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान के तहत प्राप्त राशि पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान घटकर 16 *प्रतिशत* कम हो गई।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	15118	18781	22420	24770	26137
आर.आर. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	14.4	24.2	19.4	10.5	5.5
आर.आर./स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	15.0	14.8	16.5	16.3	15.1
राज्य के स्वयं के कर/स.रा.घ.उ.	4.5	4.5	5.1	5.4	5.4
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9
उत्प्लावकता अनुपात[2]					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.99	0.91	2.94	0.89	0.40
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	1.36	1.02	3.27	1.55	1.01
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.72	0.90	0.90	0.57	0.37

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वर्ष 2009-10 के 14.4 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में 24.2 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान घटकर 5.5 *प्रतिशत* हो गई।

- स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की उत्प्लावकता में भारी उतार-चढ़ाव दिखा जो वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 0.40 तथा 2.94 के बीच था। वर्ष 2011-12 के दौरान उच्च राजस्व प्राप्तियॉ (19.4 *प्रतिशत)* एवं निम्न स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (6.6 *प्रतिशत)* के कारण यह सर्वोच्च (2.94 *प्रतिशत)* था। 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.5 *प्रतिशत* थी जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 13.9 *प्रतिशत* थी। फलस्वरूप राजस्व उत्प्लावकता घटकर 0.40 हो गया।

- स.रा.घ.उ. एवं राज्य के स्वयं के कर के वृद्धि दर में काफी उतार चढ़ाव के कारण वर्ष 2009-14 के दौरान स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) का उत्प्लावकता में काफी भिन्नता दिखा जो 1.01 से 3.27

[2] आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे- राजस्व उत्प्लवकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 *प्रतिशत* तक बढ़ेगा।

के बीच था। उत्प्लावकता वर्ष 2012-13 के 1.55 से घटकर वर्ष 2013-14 के दौरान 1.01 हो गया।

- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 6.6 *प्रतिशत* से 26.5 *प्रतिशत* तक का वृहत अन्तर दर्ज किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान स.रा.घ.उ. 13.9 *प्रतिशत* बढ़ा। तथापि वर्ष 2009-14 में स.रा.घ.उ. का सी.ए.जी.आर. 14.47 *प्रतिशत* था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चुँकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने हेतु राज्य के निष्पादन को राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल है के रूप में मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के मूल्यांकन को **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
कर राजस्व	11137.16	10117.90	9379.79
कर भिन्न राजस्व	4068.30	4167.13	3752.71

स्रोत:- ते.वि.आ. रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ तथा वित्त लेखे 2013-14

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर का संग्रहण तेरहवें वित्त आयोग के मानक अनुमान के ₹ 11,137.16 करोड़ एवं बजट के ₹ 10,117.90 करोड़ के सापेक्ष ₹ 9,379.79 करोड़ था। प्राप्ति में कमी का प्रमुख कारण बिक्री कर एवं वाहनों कर के संग्रहण में बजट अनुमान से कमी था। वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक संग्रहण बजट आकलन के ₹ 7,875 करोड़ एवं ₹ 639 करोड़ के सापेक्ष क्रमश: ₹ 7,305 करोड़ एवं ₹ 495 करोड़ था।

वर्ष 2013-14 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (6.63 *प्रतिशत*) महत्वपूर्ण रूप से ते.वि.आ. के अनुमान 6.63 *प्रतिशत* तथा एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 5.4 *प्रतिशत* से कम था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का कर-भिन्न राजस्व (₹ 3,752.71 करोड़) ते.वि.आ. के अनुमान ₹ 4,068.30 करोड़ से कम था।

1.3.1.1 कर राजस्व

तालिका 1.7 में मुख्य करों तथा शुल्कों के कुल संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3597	4473	5522	6422	7305	13.74
राज्य उत्पाद	323	388	457	578	628	8.65
वाहनों पर कर	234	312	392	465	495	6.45
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	238	328	401	492	502	2.03
भूमि राजस्व	41	131	53	96	203	139.58
यात्रियों तथा सामाग्री पर कर	13	21	41	1	1	0.00
अन्य कर	54	64	88	170	219	28.82
कुल कर राजस्व	**4500**	**5717**	**6954**	**8224**	**9380**	**14.06**

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2009-10 के ₹ 4,500 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 9,380 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में इसमें 14.06 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2009-14 के दौरान 20.16 *प्रतिशत* रहा। वर्ष 2013-14 में कुल स्वयं कर राजस्व में बिक्री कर का योगदान 78 *प्रतिशत* रहा, जिसके बाद राज्य उत्पाद कर (सात *प्रतिशत)* स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क (पाँच *प्रतिशत)* तथा वाहन कर (पाँच *प्रतिशत)* का योगदान रहा।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान मूल्य वर्द्धित कर/बिक्री कर से कर राजस्व में वृद्धि का श्रेय बेहतर प्रशासन के साथ-साथ ₹ 72.52 करोड़ की विशाल बकाया की वापसी को दिया गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2013-14 के दौरान भूमि कर में वृद्धि के कारण इस अवधि के दौरान ₹ 129 करोड़ की बकाया जमा को बताया गया। वर्ष 2013-I4 के दौरान अन्य करों में वृद्धि मुख्यत: बिजली पर कर एवं ड्यूटी में वृद्धि के कारण हुआ। इस अवधि के दौरान बिजली पर करों एवं ड्यूटी में वृद्धि का श्रेय विभाग द्वारा बेहतर कर प्रशासन को दिया गया।

1.3.1.2 कर भिन्न राजस्व

ते.वि.आ. के मानक ₹ 4,068 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व ₹ 3,753 करोड़ था।

वर्ष 2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति को **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: कर भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्तियाँ	153.20	98.74	44.16	72.23	69.48
लाभांश एवं लाभ*	0.00	0.40	1.17	15.00	18.00
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2100.95	2703.75	2992.89	3448.40	3665.23
कुल	**2254.15**	**2802.89**	**3038.22**	**3535.63**	**3752.71**

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

**लाभांश एवं लाभ वर्ष 2009-10 के दौरान शून्य था।*

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का हिस्सा दोनों वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 14 *प्रतिशत* रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान एन.टी.आर. में पिछले वर्ष की अपेक्षा छः *प्रतिशत* की वृद्धि मुख्यत: खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 88 करोड़ से) एवं अन्य प्राप्तियाँ (₹ 146 करोड़ से) के अन्तर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुआ। वर्ष 2009-14 के दौरान कर भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 13.59 *प्रतिशत* था।

1.3.1.3 कर संग्रहण का मूल्य

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख करों का सकल संग्रहण एवं उनके संग्रहण पर व्यय **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर संग्रहण का मूल्य

क्रमांक	लेखा शीर्ष	2013-14 के दौरान सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	2012-13 के दौरान सकल संग्रहण के सापेक्ष व्यय प्रतिशतता	2013-14 के दौरान सकल संग्रहण के सापेक्ष व्यय प्रतिशतता	राष्ट्रीय औसत
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	7305.08	47.29	0.57	0.65	0.73
2	वाहनों पर कर	494.79	5.16	0.97	1.04	4.17
3	राज्य उत्पाद शुल्क	627.93	14.79	2.58	2.36	2.96
4	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	502.61	12.37	2.28	2.46	3.25

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे ।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2013-14 के दौरान राज्य उत्पाद को छोड़कर, जो 2.58 *प्रतिशत* से घटकर 2.36 *प्रतिशत* हो गया, सभी प्रमुख करों के संग्रहण पर व्यय में वृद्धि हुआ। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य का कर संग्रहण पर व्यय[3] सम्पूर्ण भारत के लिए **तालिका 1.9** में वर्णित करों के सापेक्ष कम था।

[3] वर्ष 2012-13 के लिए

1.3.2 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृति **तालिका 1.10** में दर्शायी गई हैं:

तालिका 1.10: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजना अनुदान	1145.33	1281.40	1550.77	1483.41	1319.91
राज्य योजना के लिए अनुदान	982.97	1826.99	2404.61	2393.94	1565.83
केन्द्रीय योजना के तहत अनुदान	55.05	8.62	66.87	30.81	28.28
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	633.28	990.24	1235.16	914.05	1150.96
कुल	**2816.63**	**4107.25**	**5257.41**	**4822.21**	**4064.98**
पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	33	46	28	(-)8	(-)16
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	18.63	21.87	23.45	19.47	15.55

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 4,064.98 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2012-13 के ₹ 4,822.21 करोड़ से (16 *प्रतिशत*) कम था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार से गैर योजना अनुदान ₹ 1,483.41 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,319.91 करोड़ हो गया, क्योंकि वर्ष 2012-13 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिक अनुदान प्राप्त हुआ था।
- त्वरित सिंचाई लाभ योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं आर.के.भी.वाई. के तहत राज्य योजना के लिए अतिरिक्ति केंद्रीय सहायता के लिए राज्य योजना अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य योजना अनुदान भी ₹ 2,393.94 करोड़ से व्यापक रूप से घटकर ₹ 1,565.83 करोड़ हो गया।
- ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के तहत वर्ष 2013-14 में राज्य को कोई ऋण राहत प्राप्त नहीं हुआ।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2012-13 के ₹ 8,188 करोड़ के विरूद्ध केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) वर्ष 2013-14 में ₹ 8,939 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2013-14 में राज्य के सी.टी.टी. में ₹ 751 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यत: सेवा कर (₹ 260 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 219 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 106 करोड़) तथा सीमा शुल्क (97 करोड़) के अंतर्गत हुई। सी.टी.टी. वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 34 *प्रतिशत* थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने झारखण्ड सरकार को अपने विभिन्न विभागों के कार्यों में सुधार हेतु अनुदान की सिफारिश की। उन अनुदानों में से 2013-I4 के दौरान प्राप्त कुछ अनुदानों की स्थिति **तालिका 1.11** में दी गयी है:

तालिका 1.11: तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अन्तरण	ते.वि.आ. के सिफारिश से प्राप्त राशि	संबद्ध लेखा शीर्ष के तहत व्यय	अप्रयुक्त राशि
1	वन एवं पर्यावरण विभाग	48.12	30.38	17.74
2	गृह विभाग	74.50	74.50	0.00
3	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	52.75	43.55	9.20
4	कानून विभाग	21.43	7.07	14.36
5	योजना एवं विकास विभाग	4.80	0.00	4.80
6	आपदा प्रबंधन विभाग	5.00	0.00	5.00
7	ग्रामीण विकास विभाग	67.49	62.75	4.74
8	सूचना एवं प्रौवैद्यिकी विभाग	57 .91	57.90	0.01
9	शहरी विकास विभाग	121.86	47.43	74.45
10	जल संसाधन विभाग	24.67	0.00	24.67
11	लघु सिंचाई विभाग	2.33	0.00	2.33
12	कल्याण विभाग	31.25	0.00	31.25
13	खेल, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग	25.00	22.00	3.00
14	ग्रामीण कार्य विभाग	84.09	17.41	66.68
15	पंचायती राज	256.33	78.94	177.39
16	प्राथमिक एवं लोक शिक्षा	216.83	0.00	216.83
17	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	54.00	48.62	5.38
	कुल	**1148.36**	**490.55**	**657.81**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे 2013-14

इस प्रकार उपरोक्त **तालिका 1.11** से देखा जा सकता है कि ते.वि.आ. की सिफारिशों के तहत झारखण्ड सरकार को प्राप्त अनुदान की कुल बजटीय राशि (₹ 1,148.36 करोड़) में से वर्ष 2013-14 के अन्त तक 43 *प्रतिशत* (₹ 490.55 वृद्धि) खर्च की गई तथा 57 *प्रतिशत* (₹ 657.81 करोड़) अप्रयुक्त रही। योजना-वार ब्यौरे ***परिशिष्ट 1.5*** में दिये गये हैं।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों की कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री, व्यापार कर इत्यादि, राज्य उत्पाद कर, भू-राजस्व, वाहन कर, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क तथा खनन प्राप्तियों पर शुल्क एवं कर की 131 इकाईयों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान, हमने ₹ 2,313.83 करोड़ से संबंधित कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण के 20,230 मामले पाये। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 16,296 मामलों में ₹ 542.57 करोड़ को स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान विभाग ने 377 मामलों में ₹ 8.47 करोड़ की वसूली को प्रभावित किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2014 तक चार विभागों (वाणिज्य कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद, तथा खनन एवं भू-विज्ञान विभाग) में राजस्व बकाये ₹ 3,016.16 करोड़ में से ₹ 1,368.51 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वाणिज्यिक कर विभाग (₹ 1,704.67 करोड़) और खनन तथा भू-विज्ञान विभाग (₹ 1,024.74 करोड़) से संबंधित था। अन्य विभागों के बकाया राजस्व की सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी (अगस्त 2014)।

31 मार्च 2014 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के कुल राजस्व का आठ *प्रतिशत* तथा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधन का 15 *प्रतिशत* था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्रप्तियों के अलावे, राज्य पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त करता है जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम की वसूली, वित्तीय संस्थाओं से सरकार का आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2009-14 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की संरचना तथा वृद्धि की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ (*सी.आर.*)	3391	2471	2695	5242	4726
विविध पूँजीगत प्राप्तियॉ	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22	24	24	43	23
लोक ऋण प्राप्तियाँ	3369	2447	2671	5199	4703
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर *प्रतिशत*)	38.2	(-)27.4	9.2	94.6	-9.5
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	15.6	9.1	0.0	79.2	-46.51
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9
पूँजीगत प्राप्तियों का वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	38.1	(-)27.1	9.1	94.5	-9.8

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में कमी के कारण वर्ष 2012-13 के ₹ 5,242 करोड़ के सापेक्ष पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 4,726 करोड़ की कमी हुई। आगे, बाजार ऋण में महत्वपूर्ण कमी के कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 3,600 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,950 करोड़ हो गई।

वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान विनिवेश से आय 'शून्य' था।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम की वसूली

दिए गए ऋण एवं अग्रिम की तुलना में वसूली काफी कम रही। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वसूली एवं दिए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.13: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋणों का आरंभिक शेष	6415	6713	6997	7190	7748
दिया गया ऋण	320	308	21	601	222
की गई वसूली	22	24	24	43	23
ऋणों का अंतिम शेष	6713	6997	7190	7748	7947

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने वाला मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु, उस प्राप्ति के विरूद्ध कोई पुनर्भुगतान नहीं की गई जिससे जे.एस.ई.बी. के विरूद्ध बकाया की राशि ₹ 7,300.55 करोड़ हो गई। पुनर्भुगतान प्राप्ति मुख्यत: सरकारी सेवकों के ऋण एवं अग्रिमों के विरूद्ध था। वर्ष 2009-14 दौरान दिये गये ऋण तथा ऋण के अंतिम शेष का सी.ए.जी.आर. क्रमश: (-)8.74 *प्रतिशत* एवं 4.31 *प्रतिशत* था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर को भरने तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ने आंतरिक बाजार से निधि प्राप्त की। आंतरिक बाजार उधार वर्ष 2009-10 के ₹ 3,379 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,597 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक कर्ज में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 2,950 करोड़) तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त ऋण (₹ 750 करोड़) का था। वर्ष के दौरान ₹ 316 करोड़ का अर्थोपाय अग्रिम लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2009-14 के दौरान भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में काफी उतार-चढ़ाव हुआ। यह वर्ष 2009-10 के (-) ₹ 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 239 करोड़ हो गया। तथापि वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से ऋण घटकर ₹ 106 करोड़ हो गया। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम राज्य के योजनाओं के लिए प्राप्त किया गया। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई नया ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा - लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते हैं, के संदर्भ में प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ सरकार बैंकर का कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् सरकार के पास उपलब्ध शेष निधि सरकार के उपयोग के लिए होती है। **तालिका 1.14** में लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृतियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के तहत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**8242**	**7721**	**10813**	**14495**	**14275**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	687	572	613	668	760
आरक्षित निधि	489	शून्य	138	280	293
जमा तथा अग्रिम	4150	3670	5236	8706	7204
उचंत तथा विविध	204	181	306	199	-59
प्रेषण	2612	3298	4520	4642	6077

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्तियों में जमा तथा अग्रिम वर्ष 2009-10 के ₹ 4,150 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8,706 करोड़ हो गया जो आगे वर्ष 2013-14 में मुख्यत: बाजार ऋण के जमा में ₹ 650 करोड़, लोक निर्माण जमा में ₹ 487 करोड़ एवं राज्य बिजली बोर्ड निर्माण निधि में ₹ 310 करोड़ की कमी के कारण ₹ 7,204 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 14.72 *प्रतिशत* था।

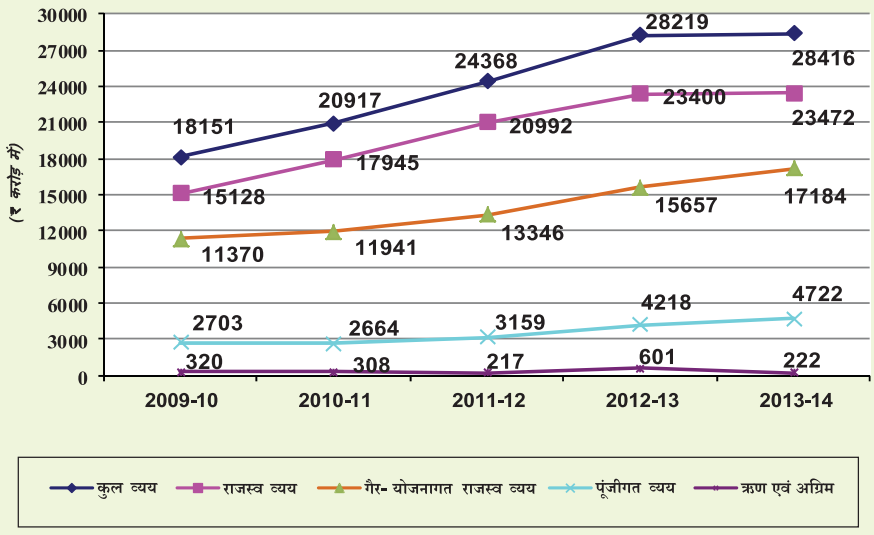
1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन्हें वृहत व्यय करने का कार्यभार सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बढ़ाने में बजटीय बाध्यता होती है। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया लागत व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये निर्देशित व्यय पर नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2009-14) के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटकों को दर्शाता है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय : संघटक तथा प्रवृति



- विगत पाँच वर्षो से कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. वृद्धि दर 11.86 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष 2012-13 की तुलना में कुल व्यय में मामूली वृद्धि (₹ 197 करोड़) हुई थी।
- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 83 *प्रतिशत* था जबकि पूँजीगत व्यय 16 *प्रतिशत* था। ऋण एवं अग्रिम का वितरण कुल व्यय का केवल एक *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमश: 56 *प्रतिशत* तथा 44 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय कुल व्यय का क्रमश: 60 *प्रतिशत* तथा 40 *प्रतिशत* था।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

- वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 4,218 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,722 करोड़ हो गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 15 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 17 *प्रतिशत* हो गयी। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 2.8 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2013-14 में 2.7 *प्रतिशत* रही।
- शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 90.76 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 मे ₹ 145.21 करोड़ हो गया। तथापि, शिक्षा पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के बजटीय राशि ₹ 269.41 करोड़ से काफी कम था।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के संदर्भ में, पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 146.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 166.18 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय, बजटीय राशि ₹ 291.80 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 487.43 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 342.07 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के बजट ₹ 1,035.20 करोड़ के विरूद्ध जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास के लिए चालू वर्ष का बजट ₹ 380.50 करोड़ था।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) कुल व्यय (₹ 28,416 करोड़) का 83 *प्रतिशत* था। रा. व्य. वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 15,128 करोड़ से बढ़कर (55 *प्रतिशत* से) वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 23,472 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान रा.व्य. का सी.ए.जी.आर. 11.61 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 13.6 *प्रतिशत* था। जबकि, राजस्व व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 11.5 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 0.3 *प्रतिशत* तथा स.रा.घ.उ. वर्ष 2012-13 में बढकर 11.8 *प्रतिशत* एवं वर्ष 2013-14 में 13.9 *प्रतिशत* हो जाने के कारण स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावकता वर्ष 2012-13 में 0.97 से घटकर वर्ष 2013-14 में 0.02 हो गया।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय बजट आकलन ₹ 11,926 करोड़ की तुलना में ₹ 6,288 करोड़ था। पी.आर.ई. वर्ष 2012-13 के ₹ 7,743 करोड़ से 19 *प्रतिशत* घटा। राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2012-13 के 33 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 27 *प्रतिशत* हो गया। सामाजिक सेवाओं में कमी (₹ 154 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवाओं में कमी (₹ 1,347 करोड़ से) का सामान्य सेवाओं में आंशिक वृद्धि (₹ 46 करोड़ से) से समायोजित होने के कारण योजनागत राजस्व व्यय में कमी हुई। वर्ष 2009-14 के दौरान योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 13.73 *प्रतिशत* था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिश ₹ 16,819.45 करोड़ तथा बजट अनुमान ₹ 18,509 करोड़ के विरूद्ध गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 17,184 करोड़ था। गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 17 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 10 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2009-14 के दौरान कुल राजस्व व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता 64 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत* के बीच दोलित रही। वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 73 *प्रतिशत* रहा। राज्य के गैर-योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2009-14 के दौरान 10.88 *प्रतिशत* रहा।

वर्ष 2013-14 के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यत: शिक्षा (₹ 2,876.19 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 604.47 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 318.72 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹ 300.97 करोड़) पर किया गया। आर्थिक सेवाओं के तहत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यत: ऊर्जा (₹ 1,502.36 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 610.13 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 418.62 करोड़) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 303.39 करोड़) पर किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। **तालिका 1.15** तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2009-14 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृति को दर्शाता है।

तालिका 1.15: वेतन और मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतान पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन* और मजदूरी, जिसमें	5342(35)	5642(30)	6352(28)	6446(26)	8668	6934(27)
गैर योजना शीर्ष	5154(34)	5434(29)	6150(27)	6270(25)	8153	6766(26)
योजना शीर्ष	188(1)	208(1)	202(1)	176(1)	515	168(1)
ब्याज भुगतान	2307(15)	2228(12)	2267(10)	2391(10)	2475	2614(10)
पेंशन पर व्यय	1681(11)	2081(11)	2297(10)	2931(12)	3061	3484(13)
सब्सिडी	41(0.3)	80	286(2)	270(1)	¥	187(1)
कुल	**9371(62)**	**10031(53)**	**11202(50)**	**12054(49)**	**14204**	**13219(51)**

स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे

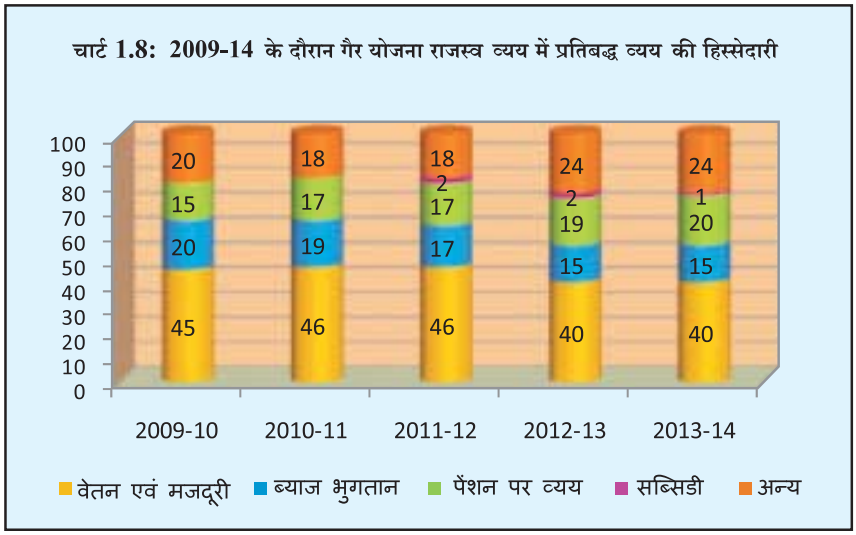
कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

** इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।*

बजट अनुमान के सकल आँकड़ें जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़ें हैं।

¥ बजट उपलब्ध नहीं है।

चार्ट 1.8: 2009-14 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी



वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय के सापेक्ष सब्सिडी की प्रतिशतता लगभग नगण्य रही।

वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 6,934 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,614 करोड़) और पेंशन (₹ 3,484 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 55 *प्रतिशत* लेखापित था तथा राजस्व प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* था। वर्ष 2013-14 के

दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल गैर-योजना व्यय सम्मिलित रूप से गैर-योजना राजस्व व्यय का 75 *प्रतिशत* लेखापित था।

- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में वेतन एंव मजदूरी व्यय 28 *प्रतिशत* से 35 *प्रतिशत* किया गया। राजस्व व्यय से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 28 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 30 *प्रतिशत* हो गयी। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता भी वर्ष 2012-13 के 26 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 27 *प्रतिशत* हो गयी। वेतन एंव मजदूरी का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2009-14 के दौरान 6.74 *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन पर व्यय (₹ 6,766 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 496 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक अनुमान (₹ 5,881 करोड़) से ₹ 885 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 19.99 *प्रतिशत* के सी.ए.जी.आर. के साथ वर्ष 2009-10 के ₹ 1,681 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3,484 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान वृद्धि दर भी पिछले वर्ष के सापेक्ष 19 *प्रतिशत* था। यह वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान (₹ 3,061 करोड़) ₹ 423 करोड़ (14 *प्रतिशत*) अधिक था।
- भविष्य में पेंशन तथा पेंशन संबंधी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है। राज्य ने नयी पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ. के ₹ 3,394 करोड़ के मानक अनुमान के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2,614 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर नौ *प्रतिशत* थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2013-14 के दौरान 10 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 3.17 *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2012-I3 तथा वर्ष 2013-I4 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक **तालिका 1.16** में दिए गये हैं:

तालिका 1.16: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2012-13	औसत ब्याज दर	2013-14	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	2018.33	8.50	2229.18	8.39
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	185.95	8.18	147.37	6.99
लघु बचत भविष्य निधि	186.23	12.09	235.96	15.18
अन्य	0.74	0.00	1.93	0.03
कुल	**2391.25**	**8.67**	**2614.44**	**7.22**

सब्सिडी

- वर्ष 2013-14 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 187 करोड़[4] का भुगतान सब्सिडी के रूप में शीर्ष 2401-फसल उत्पादन (₹ 152.97 करोड़), 2403-डेयरी विकास (₹ 12.68 करोड़) तथा शीर्ष 2852-उद्योग (₹ 17.01 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2012-13 के ₹ 270 करोड़ की सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान सब्सिडी की राशि ₹ 187 करोड़ थी।
- वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे के परिशिष्ट III के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।
- सब्सिडी न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु लोगों को सब्सिडी वाली लोक सेवा प्रदान करने हेतु परोक्ष रूप से भी दी जाती है। वर्ष 2013-14 के लेखाओं की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि विद्यार्थियों को ₹ 60.94 करोड़ (अनुदान सं. 51 एवं 58) साइकिल वितरण के लिए दिए गये जिसमें से ₹ 55.94 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। पुन: जे.एस.ई.बी. को उसके संसाधन अंतर को पाटने हेतु सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,499.96 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

[4] वित्त लेखे के *परिशिष्ट* III

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके लिए बजट में राज्य योजना (रा.यो.) तथा केन्द्रीय योजना (के.यो.) के तहत निधियाँ प्रदान की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 16,016 करोड़ का बजट बनाया गया, जिसमें से ₹ 11,169 करोड़ का उपयोग किया गया जबकि केन्द्रीय योजना हेतु किये गये बजट ₹ 2,352 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,233.96 करोड़ का उपयोग किया गया। इसमें इस प्रतिवेदन के कंडिका 1.2.2 में वर्णित, ₹ 2,601.80 करोड़ की राशि जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण को सीधा अंतरित किया गया जैसा कि शामिल नहीं है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ वृहत कार्यक्रमों पर रा.यो. तथा के.यो. के अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को **तालिका 1.17** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.17 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	मुख्य सड़क	1295.00	1210.84
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	556.00	502.23
3.	स्वर्ण रेखा परियोजना	1375.00	373.32
4.	मुख्य मंत्री ग्रामीण पुल योजना	477.90	370.72
5.	मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना	360.74	313.76
केन्द्रीय योजना			
1.	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम	738.48	461.66
2.	समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम	224.84	143.82
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	111.55	67.75

जैसा कि **तालिका 1.17** से स्पष्ट है कि सुवर्ण रेखा योजना पर व्यय (₹ 373.32 करोड़) इस योजना के लिए उपलब्ध कराई गई कुल बजट (₹ 1,375 करोड़) का केवल 27 *प्रतिशत* था। मध्यान भोजन (एम.डी.एम.) योजना के विभिन्न अवयवों पर कम व्यय के कारण, प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पर व्यय (₹ 461.66 करोड़) भी बजट आकलन के ₹ 738.48 करोड़ के साक्षेप काफी कम था।

1.6.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.18** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.18 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वितीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पंचायती राज्य संस्थाऐं (पी.आर.आई.)	-	875.69	581.06	3078.86	910.68
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	485.14	246.15	25.34	330.54	88.38
सार्वजनिक उपक्रम	602.64	491.55	777.00	450.02	1528.89
स्वायत्त निकाय	678.31	607.55	677.85	1837.02	2451.34
गैर-सरकारी संस्थाऐं	17.87	192.43	209.68	199.40	106.65
अन्य	548.98	708.34	2259.30	1054.48	1335.91
कुल	**2332.94**	**3121.71**	**4530.23**	**6950.32**	**6421.85**
राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में	15.42	17.31	21.58	29.70	27.36

स्रोत: वित्त लेखे के विवरणी आठ

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता भी वर्ष 2009-10 के ₹ 2,332.94 करोड़ से निरन्तर बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6,950.32 करोड़ हो गया जो वर्ष 2013-14 में घटकर ₹ 6,421.85 करोड़ हो गया। 2009-14 के दौरान वित्तीय सहायता की वृद्धि दर (-) आठ *प्रतिशत* एवं 53 *प्रतिशत* के बीच दोलित रहा। यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता इस उद्धेश्य के लिए विनिर्दिष्ट शीर्ष 3604 - यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया पी.आर.आई. एवं यू.एल.बी. को दी गई सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय के लेखों के अंतर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराई गई राशि (₹ 597 करोड़) शामिल नहीं है।

1.6.6 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यों यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था।

पुन: ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को अनुदान, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को अनुदान और 193-नगर पंचायतों को अनुदान के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम, 2011 में समाविष्ट सभी 18 कार्यों को फरवरी 2012 में सौंपा जिसे ***परिशिष्ट 1.6 भाग ए*** में दर्शाया गया है। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगर परिषद-14, नगर पंचायत-19, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.19 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान यू.एल.बी. को ₹ 1,175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 2009-12 के दौरान यू.एल.बी. के वित्तीय सहायता में अनवरत कमी आई। तथापि, यह वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 331 करोड़ बढा जो पुन: 2013-14 में घटकर ₹ 88 करोड़ हो गया। यह मुख्यत: कौशल विकास एवं क्षमता वर्धन हेतु यू.एल.बी. को नागरिक सुविधाएँ, शहरी यातायात संयंत्र इत्यादि के लिए सहायता का विमुक्त नहीं होने के कारण हुआ।

यू.एल.बी को उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1.19: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	15118	18781	22420	24770	26137	107226
राज्य का राजस्व व्यय (रा. व्यय)	15128	17945	20992	23400	23472	100937
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	485	246	25	331	88	1175
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का *प्रतिशत*	3.21	1.31	0.11	1.34	0.34	1.10
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	3.21	1.37	0.12	1.41	0.37	1.16
स्वयं के संग्रह[5]	-	3.23	18.84	-	-	22.07

[5] अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग को नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों (वर्ष 2010-11 : नगर पंचायतें - वासुकीनाथ, चास, गुमला, खूँटी, सिमडेगा और नगरपालिका परिषद् लोहरदगा तथा वर्ष 2011-12 नगर पंचायतें - विश्रामपुर, चकुलिया, कोडरमा, राजमहल, नगरपालिका - जुगसलाई और रॉची नगर निगम) के लेखापरीक्षा के दौरान उदभेदित हुआ कि इस अवधि के दौरान ₹ 22.07 करोड़ एकत्रित किए गए।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2014 तक स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुन: स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2013)। सरकार का जवाब अप्राप्त है (अक्टूबर 2014)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन का कार्यभार (टी.जी.एस.) अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत् राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान अंतर्निहित है जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिया जाना था। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) किया परन्तु डी.एल.एफ.ए. को अभी तक परिचालित नहीं किया गया है और लेखापरीक्षक- स्थानीय लेखा (ई.एल.ए.) द्वारा अप्रैल 2012 से तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश के अनुसार जाँच परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, लघु-शीर्षों 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4,706 पंचायती राज संस्थाएँ[6] है। **तालिका 1.20** के अनुसार, वर्ष 2009-10 तक सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को कोई अनुदान नहीं दिया। विदित हो कि पी.आर.आई का गठन दिसम्बर 2010 में चुनाव के पश्चात हुआ। वर्ष 2010-14 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 5,447 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

[6] 24 जिला परिषद, 259 पंचायत समिति, 4423 ग्राम पंचायत

तालिका 1.20 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	15118	18781	22420	24770	26137	107226
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्यय)	15128	17945	20992	23400	23472	100937
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता*	-	876	581	3079	911	5447
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	4.66	2.59	1.96	3.49	5.08
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	4.88	2.77	2.08	3.88	5.40
स्वयं संग्रह **	–	–	–	–	--	--

**पी.आर.आई. का चुनाव दिसम्बर 2010 में हुआ था।*

***राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।*

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2014 तक पी.आर.आई. निधि प्रदान करने संबंधी कोई सुझाव नहीं दिया था। राज्य सरकार पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश अक्टूबर 2012 में जारी किया। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.6 भाग बी*** में वर्णित है, पी.आर.आई. को कुल अनुबद्ध 29 कार्यों में से अक्टूबर 2014 तक 10 कार्य सम्पूर्ण रुप से सुपुर्द किया गया एवं पाँच कार्य आंशिक रुप सुपुर्द किए गए है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2010 अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा तदनुसार पंचायती राज संस्थानों का लेखांकन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है (अक्टूबर 2014)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यत: तीन पहलू यथा-पर्याप्तता (अर्थात लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

राज्य के कुल व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान 15.8 *प्रतिशत* एवं वर्ष 2013-14 के दौरान 0.7 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 64 *प्रतिशत* था, जबकि गैर-विकास व्यय 36 *प्रतिशत* था। वर्ष 2013-14 के दौरान विकास व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष पाँच *प्रतिशत* घटी, जबकि गैर-विकास व्यय

में पिछले वर्ष के सापेक्ष 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्ष 2010-11 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में **तालिका 1.21** राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.21: वर्ष 2010-11 और वर्ष 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-2011	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2010-2011	16.43	65.53	31.03	12.74	18.12	5.09
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2013-14	16.45	64.31	32.23	16.62	13.42	4.02

** स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में*

ए.ई.: सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई.:विकास पर व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी.ई.:पूँजीगत व्यय

विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आँकड़े सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।

सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2013-14 में झारखण्ड सरकार ने सकल व्यय पर अपने स.रा.घ.उ. का एक बड़ा भाग खर्च किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात में विकास परक व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से वर्ष 2010-11 के दौरान अधिक एवं 2013-14 के दौरान कम था जबकि पूँजीगत व्यय से सकल व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से वर्ष 2010-11 के दौरान कम एवं वर्ष 2013-14 के दौरान अधिक था।

वर्ष 2013-14 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी गयी।

1.7.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स[7] के प्रावधान पर जोर दिया जाय।

विकास व्यय[8] हेतु आबंटन के अलावा कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय के उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी।

तालिका 1.22 वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.22: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास पर राजस्व व्यय	8523(47)	10954(52)	13146(54)	14704(52)	20564	13512(48)
विकास पर पूँजीगत व्यय	2591(14)	2544(12)	3003(12)	4042(14)	6234	4554(16)
विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	308(2)	296(1)	199(1)	582(2)	813	209(1)
कुल	**11422**	**13794**	**16348**	**19328**	**27611**	**18275**
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य.+पू. व्य+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़े है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

---

7 कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्त्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि।

8 व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चयित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए है। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर विकासात्मक व्यय है।

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। मुख्यत: राजस्व शीर्ष के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति और ग्रामीण विकास तथा पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास मद में कम व्यय के कारण वर्ष 2013-14 में विकास परक व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा पॉच *प्रतिशत* घट गया।
- उपरोक्त **तालिका 1.22** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से काफी कम था। सामान्य सेवाओं (गैर-विकास) पर व्यय इस वर्ष के ₹ 10,103 करोड़ के बजट के सापेक्ष ₹ 10,141 करोड़ था।
- वर्ष 2009-14 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 48 *प्रतिशत* एवं 54 *प्रतिशत* के बीच थी। वर्ष 2009-14 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 12.21 *प्रतिशत* था।
- कुल व्यय में विकासपरक पूँजीगत व्यय (विकासपरक ऋण एवं अग्रिम सहित) का हिस्सा वर्ष 2012-13 के दौरान 16 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 17 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2009-14 के दौरान विकासपरक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 15.14 *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक विकासपरक पूँजीगत व्यय एवं विकासपरक ऋण एवं अग्रिम बजट आकलन के ₹ 6,234 करोड़ एवं ₹ 813 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4,554 करोड़ एवं ₹ 209 करोड़ था।
- वर्ष 2013-14 दौरान कुल विकासपरक व्यय (₹ 18,275 करोड़) में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9,159 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9,116 करोड़) प्रत्येक 50 *प्रतिशत* था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

तालिका 1.23 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हुए पूँजीगत व्यय के ब्यौरे तथा राजस्व व्यय के घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

समाजिक/आर्थिक ढाँचा	2012-13			2013-14		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी.इ. का अनुपात	आर. ई में, हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस. एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.86	47.35	0.00	2.05	54.98	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.38	57.50	0.02	14.52	51.89	0.13
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	43.14	19.16	3.66	32.51	18.03	2.82
कुल (एस.एस)	**11.03**	**34.49**	**0.35**	**10.09**	**35.92**	**0.52**
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	1.59	32.92	0.03	1.52	37.74	0.31
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.78	97.76	0.00	59.89	98.03	0.00
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	67.43	12.83	35.41	88.78	39.68	51.98
कुल (ई.एस.)	**32.02**	**16.34**	**3.24**	**39.82**	**22.14**	**4.34**
कुल (एस.एस.+ई.एस.)	**23.93**	**26.60**	**1.60**	**24.92**	**30.52**	**2.02**

टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर. ई.: राजस्व व्यय;
एस. और डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ.और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मति के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- कुल विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के 23.93 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में 24.92 *प्रतिशत* हो गया।
- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन घटक वर्ष 2012-13 के 34.49 *प्रतिशत* एवं 16.34 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2013-14 में क्रमश: 35.92 *प्रतिशत* एवं 22.14 *प्रतिशत* हो गया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष '05-सार्वजनिक सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मति' के अन्तर्गत ₹ 324.60 करोड़ का व्यय किया।
- सामाजिक सेवाओं में, राजस्व व्यय के अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास मद के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 3.66 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 2.82 *प्रतिशत* हुआ।

- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिवहन मद के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 35.41 *प्रतिशत* से बढकर वर्ष 2013-14 में 51.98 *प्रतिशत* हुआ।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न हीं केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2013-14 के परिशिष्ट-IX (i) के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार सूचना **तालिका 1.24** में दी गयी है।

तालिका 1.24 : अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.	आरंभिक अनुमानित लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	31.3.2014 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	119	548.90	97.32	255.27
पेयजल एवं स्वच्छता	9	33.06	6.16	32.97
जल संसाधन	13	183.57	5.50	211.49
लघु सिंचाई	26	47.72	11.17	69.56
भवन निर्माण	161	437.25	94.91	190.82
कुल	**328**	**1250.50**	**215.06**	**760.11**

स्रोत: वित्त लेखे 2013-14 की परिशिष्ट X

अपूर्ण कार्य पर निधियों को अवरोधित करना व्यय के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपरोक्त तालिका के सभी अपूर्ण 328 परियोजनायें (अनुमानित खर्च ₹ 12,50.50 करोड़) 31 मार्च 2014 तक समाप्त किये जाने थे, जो नहीं किये जा सके। फलत: ₹ 760.11 करोड़ अवरोधित रहा। परियोजना कार्यो के निष्पादन में विलम्ब से खर्च बढ़ने का डर रहता है। साथ ही, इन परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के कारण उनसे इच्छित फल भी प्राप्त नहीं हो पाता। अत: परियोजना कार्यों को समय से निष्पादित किया जाना आवश्यक है ताकी खर्च के अधिभार से बचा जा सके।

1.8.3 निवेश एवं वापसी

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2014 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 11 सरकारी कम्पनियाँ (₹ 75.30 करोड़) एवं 17 सहकारी, कॉरपोरेशन एवं समितियों में (₹ 110.94 करोड़) कुल ₹ 231.97 करोड़ का निवेश किया (**तालिका 1.25**)। निवेश से वापसी (लाभांश) वर्ष 2012-13 के ₹ 15 करोड़ (7.99 *प्रतिशत*) के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में ₹ 18 करोड़ (7.76 *प्रतिशत*) था। सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान 7.22 *प्रतिशत* के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.25: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अंत में निवेश *(₹ करोड़ में)*	128.73	135.18	182.57	187.82	231.97
लाभांश *(₹ करोड़ में)*	शून्य	0.40	1.17	15.00	18.00
लाभांश *(प्रतिशत में)*	शून्य	0.3	0.64	7.99	7.76
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर *(प्रतिशत में)*	8.03	7.98	7.64	8.76	7.22
ब्याज दर और लाभ में अन्तर *(प्रतिशत में)*	8.03	7.68	7.00	0.77	0.54

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 14

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 44.15 करोड़ (23 *प्रतिशत*) का निवेश मुख्यत: सरकारी कम्पनियों में (₹ 43.75 करोड़) किया गया।

पुन: 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2014 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को **तालिका 1.26** प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26 : राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(*₹ करोड़ में*)

अग्रिम /ब्याज प्राप्ति /उधार की लागतों की प्रमात्रा	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋणों का आरंभिक शेष	6415	6713	6997	7190	7748
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	320	308	217	601	222
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि	22	24	24	43	23
बकाया ऋण एवं अग्रिम का *प्रतिशत* के रूप में पुनर्भुगतान	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3
अंतशेष	**6713**	**6997**	**7190**	**7748**	**7947**
निवल योग	298	284	193	558	199
कुल ब्याज प्राप्तियाँ	7.64	7.26	2.12	0.95	2.74
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	0.12	0.12	*	0.01	0.03

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

**नगन्य*

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2009-10 के ₹ 320 करोड़ से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गयी तथापि वर्ष 2013-14 में मुख्यत: उर्जा परियोजनाओं के अन्तर्गत कम ऋण मुक्त करने के कारण (₹ 366 करोड़) बढ़कर ₹ 222 करोड़ हो गयी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में 2.57 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। मार्च 2014 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 7,947 करोड़ में से प्रमुख बकाया राशि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 565 करोड़) के पास था।
- 31 मार्च 2014 तक कुल ₹ 1,158.70 करोड़ (₹ 360.98 करोड़ मूलधन एवं ₹ 797.72 करोड़ का ब्याज) के ऋण एवं अग्रिम की वसूली किया जाना अतिदेय था।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण **तालिका 1.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2014 को
रोकड़ शेष	704.75*	1285.49
रोकड़ शेष से निवेश (अ से स)	746.57	851.84
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	742.16	847.43
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	4.41
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	71.27	66.74
रिजर्व बैंक में जमा	(-)56.50	428.21
विभागीय रोकड़ शेष	14.68	5.44

**31 मार्च 2013 तक भा. रि. बै. के पास ऋणात्मक शेष होने के कारण रोकड़ शेष निवेश से कम था।*

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के ₹ 704.75 करोड़ के रोकड़ शेष के सापेक्ष 31 मार्च 2014 के अंत तक राज्य का रोकड़ शेष ₹ 1,285.49 करोड़ था।

मार्च 2013 के अंत में ₹ 746.57 करोड़ के रोकड़ शेष निवेश के सापेक्ष मार्च 2014 के अंत में सरकार का रोकड़ शेष निवेश ₹ 851.84 करोड़ था। कुल रोकड़ शेष निवेश ₹ 851.84 करोड़ में से वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 847.43 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2014 तक का तैयार लेखा के आधार पर भा.रि.बै. के पास ₹ 428.21 करोड़ (डेबिट) का रोकड़ शेष उपलब्ध था। तथापि, भा.रि.बै. द्वारा सूचित 31 मार्च 2014 तक का रोकड़ शेष ₹ 358.25 करोड़ (क्रेडिट) था।

वर्ष 2013-14 के दौरान भा.रि.बै. में न्यूनतम शेष बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को आठ दिनों का सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा।

1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पतियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

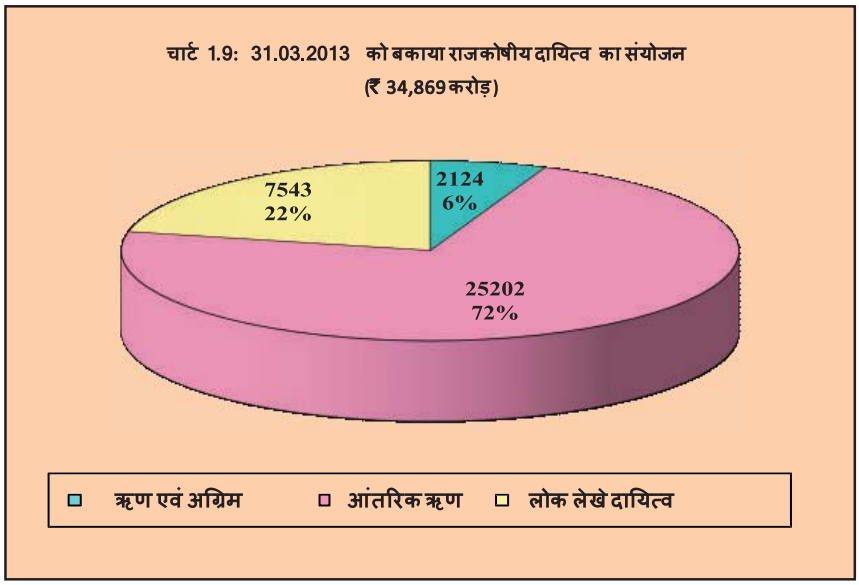
सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित

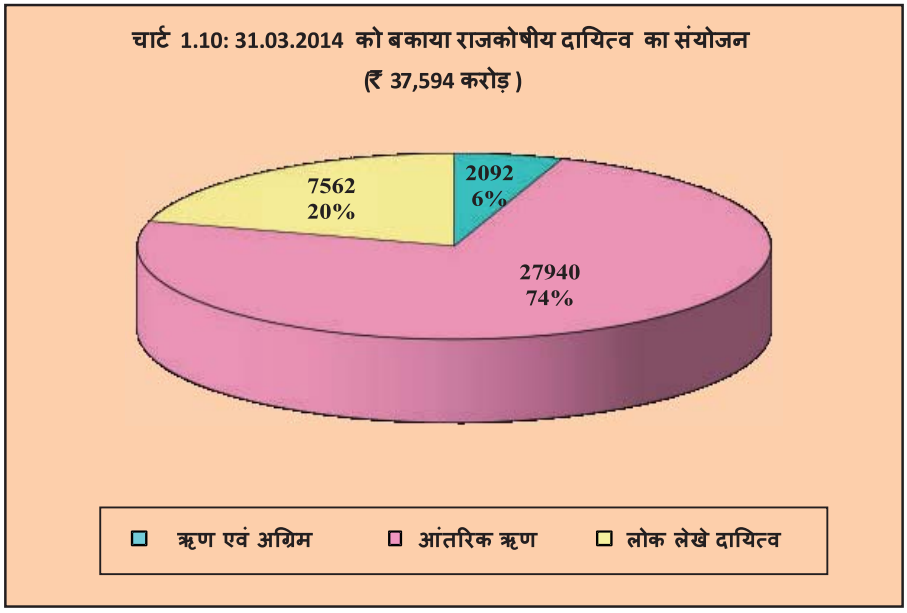
करते हैं। ***परिशिष्ट 1.4 भाग-बी*** 31 मार्च 2014 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2013 की तदनुरूपी स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यत: आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यत: पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृति ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमश: **चार्ट 1.9** एवं **चार्ट 1.10** में प्रस्तुत किया गया है।





तालिका 1.28 : राजकोषीय दायित्व की प्रवृति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आंतरिक ऋण	19880	21131	22286	25202	27940
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2272	2167	2024	2124	2092
लोक लेखे दायित्व	5013	5357	6354	7543	7562
कुल राजकोषीय दायित्व	**27165**	**28655**	**30664**	**34869**	**37594**
कुल दायित्वों में वृद्धि	12.8	5.5	7.0	13.7	7.8
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व	27.0	22.5	22.6	23.0	21.8

- जैसा कि **तालिका 1.28** दर्शाया गया है, वर्ष 2009-10 के ₹ 27,165 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व (रा.दा.) 38.39 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में ₹ 37,594 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 13.7 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013-14 में 7.8 *प्रतिशत* था। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व का सी.ए.जी.आर. 8.46 *प्रतिशत* था।

- राज्य के राजकोषीय दायित्व में ₹ 591.56 करोड़ का आरक्षित निधि (राज्य आपदा आरक्षित निधि) के रूप में शामिल था।

- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2009-10 के 27 *प्रतिशत* से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2013-14 में 21.8 *प्रतिशत* हो गया।

- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से अलग सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु एक ह्रास निधि, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, सितम्बर 2014 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (अक्टूबर 2014) नहीं किया गया।

1.9.3 ऋणों एवं अग्रिमों के वापसी का संदेहास्पद होने के कारण राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति

31 मार्च 2014 तक सरकार द्वारा दिये गए कुल ऋण एवं अग्रिमों की राशि ₹ 7,946.44 करोड़ में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) के विरूद्ध बकाया ₹ 7,239.75 करोड़ भी शामिल था।

हमने देखा कि 31 मार्च 2014 तक कुल ऋण एवं अग्रिमों की शेष राशि ₹ 7,946.44 करोड़ थी जिसमें बकाया पुनर्भुगतान ₹ 1,158.70 करोड़ था। बकाया पुनर्भुगतान में ₹ 812.07 करोड़ झारखण्ड राज्य विधुत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) से संबंधित था। जे.एस.ई.बी. स्थापना के वर्ष से घाटे में था तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किये गए अंतिम लेखे के अनुसार, उसका संचित घाटा ₹ 10,165 करोड़ था। आगे, जे.एस.ई.बी. को जनवरी 2014 में चार पावर कम्पनियों के समूह में बाँट दिया गया। जबकि, झारखण्ड राज्य सुधार स्थानांतरण योजना 2013 के अनुसार जे.एस.ई.बी. से वसूली योग्य राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं अग्रिम को राज्य सरकार के खाते में जे.एस.ई.बी. द्वारा वसूली योग्य दर्शाया जाएगा।

चुँकि जे.एस.ई.बी. ने ऋण आदायगी में चूक किया है एवं जनवरी 2014 में विभाजन के पूर्व भारी घाटे में चल रहा था, इसलिए राज्य की परिसम्पत्तियों में जे.एस.ई.बी. को दिये गए ऋण के कारण ₹ 7,239.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

इस विषय को सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2014) लेकिन अक्टूबर 2014 तक कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ।

1.9.4 संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया तत्पश्चात् प्राकृतिक आपदा राहत निधि से शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में अंतरित कर दी गई।

वर्ष 2013-।4 के दौरान एस.डी.आर.एफ. में प्रारंभिक शेष ₹ 316.20 करोड़ था। वर्ष के दौरान निधि से प्राप्ति एवं संवितरण क्रमश: ₹ 296.66 करोड़ एवं ₹ 21.29 करोड़ था जिससे मार्च 2014 तक अंतिम शेष ₹ 591.56 करोड़ हो गया।

1.9.5 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति दिया गया है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान में प्रावधान है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार मार्च 2014 तक ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था। वर्ष 2013-14 के दौरान कोई प्रत्याभूति न ही दी गई और न ही वापस ली गई।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता[9] को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण[10],

---

[9] समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के ननिर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

[10] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर व्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण*दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवत: सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात संभवत: गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[11], उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता[12], ब्याज भुगतान का भार (के साथ राजस्व प्राप्ति अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूप रेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.29 वर्ष 2009-10 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.29 : ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्रथामिक घाटा)*	(+)647	(+)5145	(+)30	(+)373	(+)2698
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रर्याप्तता (संसाधन अंतराल) *	103	899	188	(-)39	1275
उधार निधि की निवल उपलब्धता	773	(-)737	(-)238	1814	110
ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	27.0	22.5	22.6	23.0	21.8
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	15	12	10	10	10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	1183(5)	1868(8)	1449(6)	1381(5)	1453(5)
1 - 3	2885(13)	2977(13)	3080(13)	3031(11)	2916(10)
3 - 5	3263(15)	2872(12)	2623(11)	3358(12)	4373(14)
5 - 7	2569(12)	3284(14)	4302(17)	5009(19)	4160(14)
7 और आगे	12252(55)	12298(53)	12856(53)	14547(53)	17131(57)
कुल	**22152**	**23299**	**24310**	**27326**	**30033**

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

** फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।*

- जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर 6.55 *प्रतिशत* से 14.61 *प्रतिशत* के बीच दोलित रहने के कारण वर्ष 2009-14 के दौरन प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार ₹ 30 करोड़ से ₹ 5,145 करोड़ के बीच दोलित था।

---

[11] बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेख्नीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

[12] कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 21.8 *प्रतिशत* था जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (25 *प्रतिशत*) एवं ते.वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक (27.8 *प्रतिशत*) से कम था। वर्ष 2012-13 के ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 23 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान यह कम था।

- गैर ऋण प्राप्तियों में बढ़ोतरी की उपलब्धता (संसांधन अंतराल) में वर्ष 2009-14 के दौरान अंतर-वर्षीय दोलन हुआ। यहाँ 2012-13 में (-) ₹ 39 करोड़ से वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹ 1,275 करोड़ हो गयी जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का घोतक है।

- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2012-13 के ₹ 1,814 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 110 करोड़ रह गया। तथापि, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान संसाधन अंतराल ऋणात्मक (क्रमश: ₹ 737 करोड़ एवं ₹ 238 करोड़) था।

- राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2009-10 के 15 *प्रतिशत* से स्थिरतार्पूवक घटकर वर्ष 2011-12 में 10 *प्रतिशत* हो गयी। तथापि, वर्ष 2012-13 से 2013-।4 के दौरान यह स्थिर रहा।

- राज्य-ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा के अनुसार ऋण दायित्व प्रत्येक अवधि खंड के लिए बढ़ रही थी।

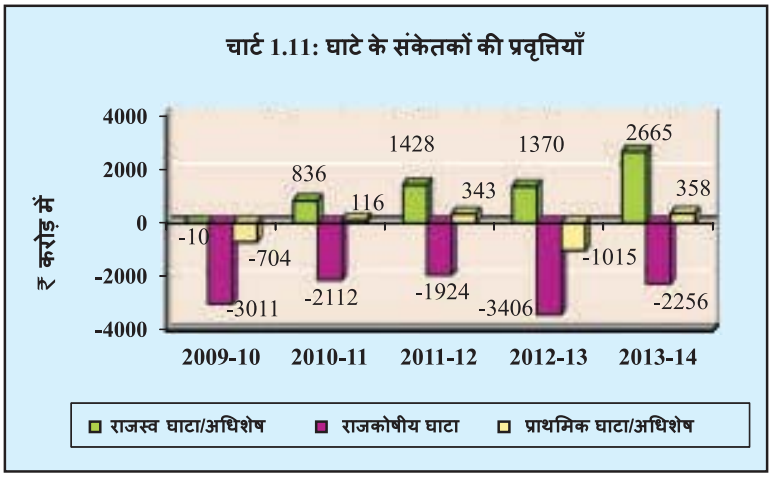
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बतलाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण व तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

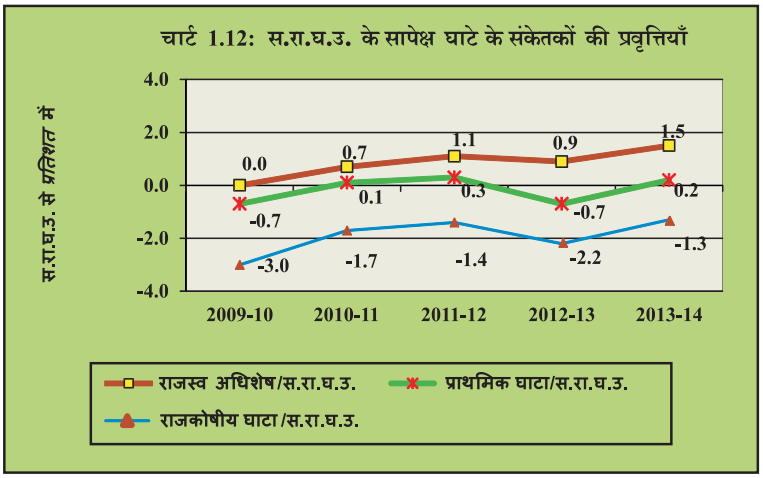
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12, वर्ष 2009-14 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.11: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.12: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



- वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटे को छोड़कर, वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। तथापि राजस्व अधिशेष वर्ष 2010-11 में ₹ 836 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2009-10 राजस्व घाटा ₹ 10 करोड़ को छोड़कर राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं ते.वि.आ. द्वारा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2009-14 के अन्त तक पूरा कर लिया था। तथापि, 2013-14 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजस्व अधिशेष का अनुपात एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये लक्ष्य 1.80 *प्रतिशत* के सापेक्ष 1.5 *प्रतिशत* था।

- वर्ष 2009-14 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,924 करोड़ एवं ₹ 3,406 करोड़ के बीच दोलीत था। तथापि राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-13 के ₹ 3,406 करोड़ से क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,256 करोड़ हो गया।
- अन्तरवर्षीय दोलन के उपरान्त स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता मार्च 2010 के अंत तक तीन *प्रतिशत* से घटकर मार्च 2014 के अंत तक 1.3 *प्रतिशत* हो गया। स.रा.घ.उ. से राजस्व घाटा की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के लिए एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये 1.3 *प्रतिशत* के अनुमान के समतुल्य थी। यह ते.वि.आ. के तीन *प्रतिशत* की सिफारिश के भी अंदर था।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2009-14 के दौरान प्राथमिक घाटा में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2009-10 में ₹ 704 करोड़ से बदलकर 2013-14 में ₹ 358 करोड़ प्राथमिक अधिशेष हो गया।
- वर्ष 2013-14 के एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 0.50 *प्रतिशत* के सापेक्ष प्राथमिक अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.20 *प्रतिशत* था।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप

वित्तीय घाटे के वित्त पोषण का स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा की **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.30: वित्तीय घाटे के अवयव एवं वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
वित्तीय घाटे का बिखराव		**3011**	**2112**	**1924**	**3406**	**2256**		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)10	836	1428	1370	2665		
2	निवल पूँजीगत व्यय	2703	2664	3159	4218	4722		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	298	284	193	558	199		
राजकोषीय घाटे वित्त पोषण का स्वरूप*						**प्राप्तियाँ**	**संवितरण**	**निवल**
1	बाजार उधार	1674	198	785	3145	2950	414	2535
2	भारत सरकार से ऋण	(-)133	(-)104	(-)122	100	106	139	-33
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	670	957	(-)73	(-)200	300	429	129
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)32	96	442	(-)30	1331	876	455
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	273	104	70	22	760	751	9
6	आरक्षित निधि	313	(-)223	(-)105	(-)123	293	21	271
7	जमा एवं अग्रिम	273	464	1030	1290	7204	7458	-254
8	उचंत एंव विविध	132	(-)27	74	31	-59	-58	-1

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
9	प्रेषण	(-)39	6	(-)17	(-)141	6077	5920	157
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0	0	(-)76	(-)100	0	50	-50
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/कमी(-)	120	(-)641	117	588	705	1285	580
* *वर्ष 2013-14 को छोड़कर ये सभी अंक सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।*								

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,256 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यत: बाजार उधार (₹ 2,535 करोड़) एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 455 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) को पूर्ण करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुन: यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय[13] का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तथ्यों का विभाजन **तालिका 1.31** में दिया गया है।

तालिका 1.31: राज्य में प्राथमिक घाटा/अधिशेष - तथ्यों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एंव अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(-)/ अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015
2013-14	26160	20858	4722	222	25802	(+)5302	(+)358

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के विरूद्ध राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 15,140 करोड़ से

[13] ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम।

बढ़कर ₹ 26,160 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय वर्ष 2009 के दौरान ₹ 2,703 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 4,722 करोड़ हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से पॉच *प्रतिशत* बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 लगभग बराबर रहा जिसके कारण 2012-13 के प्राथमिक घाटा ₹ 1,015 करोड़ के विरूद्ध 2013-14 में ₹ 358 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष हो गया।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013-।4 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि उस वर्ष के तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 14.5 *प्रतिशत* के विरूद्ध 13.9 *प्रतिशत* था।

  सरकार को ते.वि.आ. के मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

- राज्य के पास वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,665 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। वर्त्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 2,256 करोड़ था। यह स.रा.घ.उ. 1.3 *प्रतिशत* था, जो ते.वि.आ. द्वारा की गई अनुशंसित की सीमा (तीन *प्रतिशत*) के भीतर था। आगे राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. के अनुपात 2012-13 में 2.2 से सुधरते हुए 2013-14 में 1.3 *प्रतिशत* हो गया।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 2,601.80 करोड़ की केन्द्रीय निधि राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधा अंतरित कर दिया गया। बजट के बाहर भारत सरकार से निधियों का राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधा अंतरण के कारण वार्षिक लेखे राज्य के साधनों का सम्पूर्ण परिदृश्य उपलब्ध नहीं कराता है।

  राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशियों के अनुप्रयोग के उचित लेखांकन एवं अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

संसाधनों का संचरण

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 26,137 करोड़) वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 5.5 *प्रतिशत* बढ़ी, वहाँ यह बजट आकलन (₹ 7,462 करोड़) से कम था।

  सरकार के बजट दस्तावेजों में प्राप्तियों हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के सकल व्यय से सामाजिक क्षेत्र के व्यय का अनुपात सामान्य कोटि के राज्यों के औसत से कम था।
- पूँजीगत व्यय (पूं.व्य.) वर्ष 2012-13 में ₹ 4,218 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में ₹ 4,722 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में कमी आई। राज्य सरकार ने अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दिया।

  सरकार को शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए सामाजिक क्षेत्र के व्यय को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। जिससे यह सामान्य कोटि के राज्यों के समतुल्य हो सके।

- प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी जाती है लेकिन इसकी वापसी नगन्य रहती है जिसके कारण मार्च 2014 तक ₹ 1,158.70 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान बकाया था।

  सरकार से प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले संस्थाओं/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 37,594 करोड़) पिछले वर्ष से 7.8 *प्रतिशत* बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 21.8 *प्रतिशत* था जो ते.वि.आ.की अनुशंसा 27.3 *प्रतिशत* के अंदर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए ह्रास निधि (सिकिंग फण्ड) का गठन नहीं किया है।

  सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए ह्रास निधि का गठन करना चाहिए।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उदेश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के भारित और दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अत: विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को आसान बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखा परीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और जब कभी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 52 के अनुसार, राज्य के बजट प्राक्कलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया जाना हैं। बजट नियमावली के नियम 79 के अनुसार, विभिन्न विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन प्राक्कलनों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण उपस्थापन हेतु संकलित किया जाना है। व्यय पर नियंत्रण करने से संबंधित नियम झारखण्ड वित्तीय नियमावली में समाहित है। राज्य के बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, समस्त अनुमानित बचतों को सरकार को अविलम्ब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के अधिकाई व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित अधिकाई हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 117 के अनुसार, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित अधिकाई को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए।

वर्ष 2013-14 के दौरान अनेक अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्यों को देखा गया जो बजट प्रबंधन में त्रुटियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 2.1** में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2013-14 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)
दत्तमत	I राजस्व	27899.81	2114.18	30013.99	20823.17	(-)9190.82
	II पूँजीगत	6466.40	1394.26	7860.66	4923.59	(-)2937.07
	III ऋण एवं अग्रिम	838.40	54.16	892.56	271.91	(-)620.65
कुल दत्तमत		**35204.61**	**3562.60**	**38767.21**	**26018.67**	**(-)12748.54**
भारित	IV राजस्व	2535.26	3.87	2539.13	2670.01	(+)130.88
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	1809.02	6.32	1815.34	1996.92	(+)181.58
कुल भारित		**4344.28**	**10.19**	**4354.47**	**4666.93**	**(+)312.46**
सकल योग		**39548.89**	**3572.79**	**43121.68**	**30685.60**	**(-)12436.08**

(स्त्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2013-14)

**व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 21.29 करोड़) तथा पूँजीगत दत्तमत व्यय (₹ 201.09 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।*

नोट- वर्ष 2013-14 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 560.00 करोड़ का व्यय अधिवर्णित था जिनके विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 30 जून 2014 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल मिलाकर ₹ 12,436.08 करोड़ का बचत, ₹ 13,130.13 करोड़ के बचत (राजस्व संभाग के अन्तर्गत 55 अनुदानों एवं दो विनियोगों में कुल ₹ 9,572.41 करोड़ तथा पूँजीगत संभाग के अधीन 30 अनुदानों में ₹ 3,557.73 करोड़) तथा एक अनुदान एवं दो विनियोगों में ₹ 694.05 करोड़ आधिक्य के प्रतितुलन का परिणाम था।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा राज्य सरकार को शीर्ष-वार व्यय की स्थिति मासिक सिविल लेखा एवं विनियोग लेखा के माध्यम से प्रति माह उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, अत्यधिक बचत एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकारी विभागों द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2013-14 में वर्णित कुल 1,433 उप-शीर्षों में से 1,310 उप-शीर्षों में बचत के कारण एवं 53 उप-शीर्षों में आधिक्य के कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि 45 मामलों (35 अनुदानों) में कुल ₹ 12,037.60 करोड़, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* या उससे अधिक, की बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाया गया है। ₹ 13,130.13 करोड़ की कुल बचत में, 23 अनुदानों से संबंधित 26 मामलों में ₹ 11,876.80 (90 *प्रतिशत*)[1] की बचत हुई जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व दत्तमत						
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	939.41	43.34	982.75	416.22	566.53
2	10- ऊर्जा विभाग	1753.65	501.31	2254.96	1536.82	718.14
3	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	994.33	149.87	1144.20	573.65	570.55
4	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1133.20	4.56	1137.76	966.63	171.13
5	21-उच्च शिक्षा	662.98	0.00	662.98	491.78	171.20
6	22-गृह विभाग	2786.70	99.67	2886.37	2684.80	201.57
7	23-उद्योग विभाग	290.94	1.04	291.98	171.18	120.80
8	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	996.20	22.05	1018.25	710.13	308.12
9	35-योजना एवं विकास विभाग	642.46	0.43	642.89	109.28	533.61
10	39-आपदा प्रबंधन विभाग	458.76	5.30	464.06	316.07	147.99
11	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	397.17	0.28	397.45	271.78	125.67
12	42-ग्रामीण विकास विभाग	756.60	0.27	756.87	538.76	218.11
13	48-नगर विकास विभाग	1287.35	107.66	1395.01	493.84	901.17
14	51-कल्याण विभाग	810.64	65.24	875.88	627.92	247.96
15	56-पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम(विशेष प्रमंडल) विभाग	1627.28	665.65	2337.93	869.88	1468.05
16	58-माध्यमिक शिक्षा	740.97	58.96	799.93	582.89	217.04
17	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	4369.24	0.00	4369.24	2628.97	1740.27
18	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	1233.96	2.42	1236.38	841.05	395.33

[1] प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से आधिक्य

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
पूँजी-दत्तमत						
19	8-नागरिक विमानन विभाग	0.00	279.99	279.99	110.00	169.99
20	10-ऊर्जा विभाग	766.88	0.00	766.88	175.34	591.54
21	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	291.80	26.75	318.55	166.18	152.37
22	41-पथ निर्माण विभाग	1775.94	450.00	2225.94	1877.26	348.68
23	42-ग्रामीण विकास विभाग	599.00	0.00	599.00	249.42	349.58
24	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	170.15	0.00	170.15	52.56	117.59
25	49-जल संसाधन विभाग	1640.00	20.00	1660.00	529.04	1130.96
26	50-लघु सिचाई विभाग	298.60	20.30	318.90	126.05	192.85
कुल		**27469.21**	**2525.09**	**29994.30**	**18117.50**	**11876.80**

स्त्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, उपरोक्त अनुदानों के अंतर्गत 117 उप-शीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 9,527.28 करोड़ (कुल बचत का 73 *प्रतिशत*) की बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ एवं उससे अधिक) हुई। विनियोग लेखे 2013-14 में प्रदर्शित बचत के कारण सहित बचत के ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है। अत्यधिक बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

2.4.2 सतत बचत

16 मामलों में (15 विभागों) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामलों में कुल अनुदान का 10 *प्रतिशत* या उससे अधिक की सतत बचत थी (**तालिका 2.3**)।

तालिका 2.3 : वर्ष 2009-14 के दौरान सतत बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व - दत्तमत						
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	178.10(44)	181.21(39)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)
2	2-पशुपालन विभाग	54.21(27)	46.11(22)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)
3	17-वित्त (व्यावसायिक कर) विभाग	3.79(11)	8.27(17)	11.24(18)	27.17(38)	8.18(13)
4	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	98.68(28)	84.27(13)	168.00(15)	307.90(28)	570.55(50)
5	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	61.60(23)	68.35(23)	52.20(19)	48.17(15)	60.50(18)
6	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	480.56(45)	178.41(21)	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)
7	23-उद्योग विभाग	73.27(32)	31.89(18)	157.41(45)	82.94(29)	120.80(41)
8	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	162.39(23)	148.44(19)	193.07(23)	232.43(25)	308.12(30)
9	35-योजना एवं विकास विभाग	72.02(82)	14.00(46)	291.78(58)	594.38(88)	533.61(83)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
10	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	47.00(17)	27.94(11)	79.15(24)	77.17(23)	125.67(32)
11	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	66.06(59)	51.83(41)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)
12	49-जल संसाधन विभाग	57.85(22)	30.98(13)	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)
13	51-कल्याण विभाग	304.76(28)	208.83(16)	309.14(33)	250.26(31)	247.96(28)
पूँजीगत - दत्तमत						
14	10-ऊर्जा विभाग	383.67(61)	132.56(32)	1130.05(87)	252.30 (32)	591.54(77)
15	41-पथ निर्माण विभाग	230.19(31)	146.70(18)	899.94(53)	174.55(10)	348.68(16)
16	49-जल संसाधन विभाग	277.49(56)	153.71(40)	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)

(कोष्ठक के आँकड़े कुल अनुदान के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)
स्रोत: विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अत्यधिक बचत वर्षों से जारी रही जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती है। आगे, उपरोक्त तालिका में वर्णित चार विभागों जो आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से संबद्ध है, के कुछ मुख्य स्कीमों में बचत के ब्यौरों की चर्चा नीचे की गई है:

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य के 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री दाल-भात योजना', 'गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.) योजना' तथा 'कम्प्यूटराईजेशन योजना' के अन्तर्गत अत्यधिक बचत हुआ जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (3456-00-102-13)	0.00	0.00	235.83	84.47 (36)	126.23	22.03(17)
2	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (3456-00-789-13)	0.00	0.00	84.49	24.49 (29)	54.10	9.58(18)
3	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (3456-00-796-13)	0.00	0.00	335.36	88.52 (26)	206.06	41.02(20)
4	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (3456-00-102-23)	2.75	1.16(42)	4.45	0.93(21)	7.83	4.12(53)
5	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (3456-00-789-23)	1.08	0.41(38)	1.67	0.44(26)	1.97	1.09(55)
6	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (3456-00-796-23)	4.28	1.44(34)	6.83	2.70(40)	8.05	3.64(45)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
7	ए.पी.एल. योजना(3456-00-102-16)	8.62	7.93 (92)	9.24	9.09 (98)	16.60	16.44 (99)
8	ए.पी.एल. योजना(3456-00-789-16)	2.11	2.06 (98)	2.40	2.39 (99)	1.22	1.20 (98)
9	ए.पी.एल. योजना(3456-00-796-16)	5.74	4.71 (82)	6.81	6.34 (93)	4.57	3.79 (83)
10	कम्प्यूटराईजेशन योजना (3456-00-102-27)	0.00	0.00	13.82	12.60 (91)	34.86	34.62 (99)
11	कम्प्यूटराईजेशन योजना(3456-00-789-27)	0.00	0.00	4.76	4.74 (99)	3.96	3.87 (98)
12	कम्प्यूटराईजेशन योजना(3456-00-796-27)	0.00	0.00	18.00	16.86 (94)	22.13	19.74 (89)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)
स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के विनियोग लेखे।

वर्ष 2012-13 के दौरान 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री दाल-भात योजना', 'गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.) योजना' तथा 'कम्प्यूटराईजेशन योजना' के अन्तर्गत क्रमश: केन्द्र सरकार से आवंटित निधि की अप्राप्ति, खाद्यान्न का कम उठाव तथा केन्द्र सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियों का कम अनुमोदन के कारण बचत हुआ। विगत दो/तीन वर्षों के दौरान दूसरे मामलों में बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

विगत तीन वर्षों के दौरान 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना' एवं 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचत हुई। ब्यौरे नीचे तालिका में दिये गये है-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2230-01-103-10)	12.00	7.74(66)	10.00	8.30(83)	8.00	4.02(50)
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2230-01-789-10)	6.00	4.11(69)	5.00	2.35(47)	4.00	2.04(51)
3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2230-01-796-10)	12.00	5.17(43)	10.00	8.25(83)	0.00	0.00
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (2235-03-101-06)	6.96	3.12(45)	4.83	1.00(21)	7.42	2.11(28)
5	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (2235-03-789-06)	4.26	2.99(70)	2.35	1.08(46)	3.09	1.40(45)
6	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (2235-03-796-06)	11.22	8.21(73)	6.18	3.53(57)	8.65	5.08(59)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)
स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के विनियोग लेखे।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बचत का कारण स्मार्ट कार्ड का तैयार नहीं होना दिया गया। अन्य मामलों में विभाग द्वारा बचत का कारण नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 35 - योजना एवं विकास विभाग

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में महत्वपूर्ण बचत हुई जो नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (2235-02-102-01)	54.44	43.80(80)	143.87	118.01(82)	75.63	39.70(52)
2	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (2235-02-796-01)	54.00	40.94(76)	144.00	118.35(82)	75.71	42.70(56)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)
स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के विनियोग लेखे।

उपरोक्त मामलों में बचत के कारण विभाग द्वारा नहीं बताये गये।

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग

वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम के साथ-साथ वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान आदर्श ग्राम योजना में महत्वपूर्ण बचत पाया गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-789-05)	19.08	9.89(52)	20.40	14.90(73)	13.95	8.74(63)
2	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-796-05)	25.30	6.91(27)	26.64	16.92(64)	28.80	19.89(69)
3	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-800-05)	19.80	9.04(46)	36.26	36.26(100)	39.20	21.24(54)
4	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-796-01)	34.43	22.08(64)	29.42	18.99(65)	11.78	4.21(36)
5	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-800-01)	21.39	15.68(73)	35.78	28.26(79)	11.77	8.91(76)
6	सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम (2505-01-796-02)	69.00	24.78(36)	54.00	12.83(24)	59.40	8.05(14)
7	सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम (2505-01-702-02)	54.00	12.48(23)	73.50	35.02(48)	80.85	38.77(48)
8	आदर्श ग्राम योजना (2515-00-102-28)	0.00	0.00	29.40	12.09(41)	22.05	18.38(83)
9	आदर्श ग्राम योजना (2515-00-789-28)	0.00	0.00	9.00	3.65(41)	6.75	5.37(80)
10	आदर्श ग्राम योजना (2515-00-796-28)	0.00	0.00	21.60	8.59(40)	16.20	11.89(73)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)
स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के विनियोग लेखे।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

2.4.3 आकस्मिक निधि से अग्रिम

राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 की धारा 4 के अधीन की गई है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जिनका निरस्तीकरण विधान मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने तक अनैच्छिक होगा, को पूरा करने हेतु ही दिया जाना है। राज्य में इस निधि की धनराशि ₹ 150 करोड़ है।

संगत अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि आकस्मिक निधि से अग्रिम का आहरण उन व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। वर्ष 2013-14 के दौरान, 45 अवसरों पर ₹ 336.33 करोड़ आहरित किए गए। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान इस निधि से आहरित कुल राशि की प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान की गई। कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
1	2011-02-101-06	विपक्षी दल के नेता का वेतन एवं भत्ता	50.00
2	2011-02-103-01	नये मोटर वाहन की खरीद	23.00
3	2045-00-103-03	वेतन एवं भत्ता	10.52
4	2051-00-103-01	वेतन एवं भत्ता	15.55
5	2052-00-090-07	वेतन एवं भत्ता	32.00
6	2059-80-001-01	वेतन एवं भत्ता	7.21
7	2070-00-104-01	निविदा भत्ता	13.92
8	2071-01-117-03	अंशदान पेंशन स्कीम हेतु सहायता अनुदान	3000.00
9	2406-01-105-38	नये मोटर वाहन की खरीद	110.89
10	2406-01-796-13	मजदूरी (आपूर्ति एवं सामग्री)	352.17
11	2515-00-001-79	सहायता अनुदान (गैर-वेतन)	4500.00
12	2515-00-796-79	सहायता अनुदान (गैर-वेतन)	9000.00
13	2515-00-789-79	सहायता अनुदान (गैर-वेतन)	1500.00
14	2851-00-001-01	वेतन एवं भत्ता	39.34
15	3451-00-090-07	पेशेवर सेवा	500.00
16	3451-00-090-01	वेतन एवं भत्ता	65.00
कुल			**19219.60**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

उपरोक्त वर्णित व्यय आकस्मिक निधि से आहरण के मापदण्डों को पूरा नहीं करता क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित हैं और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के हैं। अतएव, ये व्यय राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे।

2.4.4 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदानों/ विनियोगों से आधिक्य को राज्य विधायिका द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

तालिका 2.5 में वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा राज्य के संचित निधि से अनुमोदन के विरूद्ध दो विनियोग एवं एक अनुदान में कुल ₹ 694.05 करोड़ के आधिक्य का सारांश अन्तर्विष्ट है जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 2.5 : वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग के नाम व संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	13- ब्याज का भुगतान	2475.02	2614.44	139.42
2	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	1815.34	1996.92	181.58
दत्तमत अनुदान				
3	15-पेंशन	3111.26	3484.31	373.05
कुल		**7401.62**	**8095.67**	**694.05**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे

उपरोक्त अनुदानों में कुल ₹ 694.05 करोड़ का आधिक्य व्यय अनुदान के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान से अधिक व्यय के कारण हुआ।

2.4.5 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2012-13 तक प्रावधान से अधिक व्यय की गई ₹ 9,803.97 करोड़ की राशि को संविधान को अनुच्छेद 205 के अनुसार विनियमित किया जाना अभी भी (अक्टूबर 2014) शेष है जिसे ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। अनुदानों/विनियोगों हेतु विनियमित की जाने वाली लंबित वर्ष-वार आधिक्य व्यय की राशि **तालिका 2.6** में सारांशीकृत है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का विनियमित नहीं होना विनियोगों पर वित्त-विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.6: विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	3, 25, 32		0.04
2002-03	10, 32	13,14	1241.49
2003-04	10, 39,46	13,14	937.25
2004-05	23,39,40	13,14	576.07
2005-06	10, 29	13	3121.47
2006-07	38	13,14	1245.87
2007-08	15	14	334.44
2008-09	12	14	228.89
2009-10		14	116.71
2010-11	15	13,32	318.40
2011-12	15,25	14	420.16
2012-13	7, 15, 42	14	1263.18
कुल			**9803.97**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 47 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख अधिक) प्राप्त कुल ₹ 1,907.43 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल आवंटन खत्म नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक बचत हुई।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोजन है। वर्ष 2013-14 के दौरान 26 उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है, अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। 24 योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 15.70 करोड़ की बचत के बावजूद उक्त योजनाओं/ उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.36 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गयी जबकि दो योजनाओं/उप-शीर्षों की ₹ 0.56 करोड़ की राशि अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई यद्यपि वर्ष के अन्त तक इन योजनाओं में ₹ 5.66 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ था।

2.4.8 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी बचत प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग का अभ्यर्पण वित्त विभाग को किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 13,130.13 करोड़ के कुल बचत में से 42 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत कुल ₹ 11,505.90 करोड़ का महत्वपूर्ण बचत (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ और अधिक) हुआ। इनमें से कुल ₹ 8,731.52 करोड़ (कुल बचत का 66 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किये गये, जिसके ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.6*** में दिये गये है।

इसके अलावा, 26 मामलों, जहाँ अभ्यर्पण की राशि प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ से अधिक थी, ₹ 1,519.89 करोड़ की राशि मार्च 2014 के अंतिम दो कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई (***परिशिष्ट 2.7***), जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों में इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं मिला। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.5 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का रख-रखाव किया जाता है। विपरीत, ***परिशिष्ट 2.8*** में सूचीबद्ध 20 लेखा-शीर्षों में वर्ष 2013-14 के अंतिम तिमाही में किया गया व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था।

यह देखा गया कि मुख्य शीर्षों '2810-नये एवं नवीकरण ऊर्जा के लिए ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत' (₹ 11.87 करोड़) तथा '4404'-डेयरी विकास के अधीन पूँजीगत हिस्सा' (₹ 10.00 करोड़) के सम्पूर्ण निधियों का व्यय मार्च 2014 में किया गया।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बही से नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन को नियमित रूप से हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किये गये, तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान विसंगतियाँ सतत् रूप से जारी रहीं। वर्ष 2013-14 के दौरान यह देखा गया कि कुल प्राप्तियाँ ₹ 30,863.02 करोड़ के विरूद्ध कुल ₹ 12,792.03 करोड़ (41.45 *प्रतिशत*) की राशि का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल व्यय ₹ 30,463.22 करोड़ में से ₹ 17,947.18 करोड़ (58.91 *प्रतिशत*) के व्यय का समाशोधन 15 जून 2014 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के कुल ₹ 17,380.93 करोड़ का असमाशोधित व्यय ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बही से विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन के कारण, प्राप्तियों एवं व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की संभावनाओं से इन्कार नहीं जा सकता है।

2.7 अनुदान संख्या 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के बजटीय प्रक्रिया का समीक्षा किया गया। इस अनुदान में तीन[2] राजस्व मुख्य लेखा-शीर्ष एवं एक पूँजीगत[3] मुख्य लेखा-शीर्ष हैं। लेखापरीक्षा दल ने इस अनुदान के अन्तर्गत शामिल 31 इकाईयों के अभिलेखों का संवीक्षा किया।

महत्वपूर्ण अवलोकनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

2.7.1 निर्धारित अनुसूची का अनुसरण नहीं किया जाना

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 62 बजट आकलन तैयार करने के लिए अनुसूची उपलब्ध कराता है। अनुदान संख्या 20 के समीक्षा के दौरान हम लोगों ने पाया कि यद्यपि वित्त विभाग ने 16 नवम्बर 2012 को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को वर्ष 2013-14 का बजट आकलन एवं बजटीय लेनदेनों के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) की प्रति 24 दिसम्बर 2012 तक वित्त विभाग को भेजने संबंधी निर्देश जारी किया, तथापि, यह 38 दिनों के विलम्ब से एक फरवरी 2013 को वित्त विभाग को भेजा गया। 31 इकाईयों[4] के संवीक्षा से उजागर हुआ कि इनमें से 11 इकाईयों ने विभाग को बजट आकलन दो से 26 दिनों के विलम्ब से जमा किया, जबकि विभाग को बजट आकलन जमा करने में छः इकाईयाँ विफल रही, छः इकाईयों ने लेखापरीक्षा दल को बजट आकलन की उपलब्ध नहीं करायी एवं केवल आठ इकाईयों ने बजट आकलन समय से प्रस्तुत किया। अतएव, विभाग ने बजट आकलन सौंपने के निर्धारित अनुसूची का अनुसरण नहीं किया।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बजट आकलन के आधार पर सी.ओ.बी.टी. तैयार किया गया था।

---

[2] मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2211 - परिवार कल्याण एवं 2251-सचिवालय - सामाजिक सेवा

[3] मुख्य शीर्ष 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की पूँजीगत संरचना

[4] **कार्यालय:** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (झारखण्ड), निदेशक प्रमुख, निदेशक औषधि, निदेशक खाद्य, निदेशक आयुष, निदेशक रिम्स, निदेशक-रिनपास एवं जे.एम.एच.आई.डी.पी.सी.एल।
स्वाथ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रमण्डल: कार्यपालक अभियंता (का.अ.) कोल्हान (चाईबासा) का.अ., उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग) एवं का.अ., दक्षिणी छोटानागपुर (राँची)।
असैन्य शल्य चिकित्सक कार्यालय- राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और चाईबासा।
अधीक्षक का कार्यालय- धनबाद (पी.एम.सी.एच.), जमशेदपुर (एम.जी.एम.एम.सी.एच.), राँची, हजारीबाग और चाईबासा। **अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय-** राँची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद और चाईबासा। **आर.सी.एच. का कार्यालय:** राँची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद और चाईबासा

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि छः नमूना-जाँचित क्षेत्रीय इकाईयों ने वर्ष 2013-14 (योजना) के लिए बजट आकलन प्रस्तुत ही नहीं किये थे।

2.7.2 बढ़ा हुआ बजट आकलन

बजट नियमावली का नियम 131 बतलाता है कि आकलन अधिकारियों को बजट में सभी आवश्यक मदों को अपेक्षित/पूर्वानुमानित सीमा तक प्रदान करनी चाहिए। आगे, नियम 132 बतलाता है कि सामान्य व्यय का बजट प्रावधान की राशि से वृहत अन्तर होने की संभावना कम से कम होनी चाहिए।

- यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1,456.31 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से, ₹ 1,132.81 करोड़ (77.79 *प्रतिशत*) का व्यय विभाग द्वारा किया गया। ₹ 323.50 (22.21 *प्रतिशत*) करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 287.99 करोड़ व्यपगत हो गई एवं ₹ 35.51 करोड़ अभ्यर्पित कर दी गई। विनियोग लेखे 2013-14 के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 34 उप-शीर्षों (136 में से) के अन्तर्गत सम्पूर्ण बजट प्रावधान ₹ 47.76 करोड़ अप्रयुक्त रही (***परिशिष्ट 2.10***) एवं अन्ततः अभ्यर्पित या व्यपगत हो गई।

  हमलोगों ने यह भी पाया कि वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान विभाग को बजट प्रावधान के विरूद्ध क्रमशः ₹ 265.01 करोड़ (24.72 *प्रतिशत*), ₹ 455.65 करोड़ (31.74 *प्रतिशत*) एवं ₹ 586.65 करोड़ (38.27 *प्रतिशत*) का सतत् बचत हुआ जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में है।

  संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि 2013-14 के दौरान लोक सभा चुनाव के परिपेक्ष्य में महत्वपूर्ण निर्णयों पर रोक के कारण निधियों को अभ्यर्पित किया गया। वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए विभाग द्वारा कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया।

  पुनः 31 इकाईयों के लेखापरीक्षा संवीक्षा से बजट आकलन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी-

- **रिक्त पदों के लिए परिहार्य बजट प्रावधानः** बजट नियमावली के नियम 55 (1) के अनुसार बजट केवल कार्यरत व्यक्तियों के लिए ही बनाये जाने चाहिए।

  वर्ष 2013-14 के लिए 31 नमूना-जाँचित क्षेत्रीय इकाईयों (***परिशिष्ट 2.12)*** में से पाँच इकाईयों के बजट संचिका के अवलोकन से प्रकट हुआ कि 225 पदों के लिए ₹ 7.47 करोड़ का बजट प्रावधान तैयार किया गया जो अप्रयुक्त रहा एवं अन्ततः ₹ 7.47 करोड़ के बचत के रूप में प्रतिफलित हुआ।

  उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण ने कहा (अक्टूबर 2014) कि भविष्य में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- **माँग के विरूद्ध अत्यधिक आवंटन:** वर्ष 2013-14 के बजट आकलन में, अधीक्षक, सदर अस्पताल, राँची; पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पी.एम.सी.एच.), धनबाद तथा अधीक्षक, महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (एम.जी.एम.एम.सी.एच.), जमशेदपुर के कार्यालयों द्वारा किये गए माँग क्रमश: ₹ 3.60 लाख, ₹ 16.38 लाख एवं ₹ शून्य की राशि के विरूद्ध विभाग द्वारा विस्तृत शीर्ष "50-स्टाइपेंड" के अन्तर्गत क्रमश: ₹ 20.00 लाख, ₹ 40.00 लाख एवं ₹ 40.00 लाख आवंटित किए गए। अतएव, विभाग द्वारा इकाईयों को किये गए अत्यधिक आवंटन के फलस्वरूप ₹ 80.02 लाख का अभ्यर्पण हुआ।

  इस तथ्य को स्वीकारते हुए संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि भविष्य में इस विषय पर ध्यान दिया जायेगा।

- **पूर्व निर्मित स्वास्थ्य उप-केन्द्रों एवं पंचकर्म थेरेपी केन्द्रों के निर्माण के लिए परिहार्य/अनियमित विषम बजट प्रावधान:**

  - कार्यपालक अभियंता, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रत्यार्पण प्रतिवेदन के विश्लेषण में उजागर हुआ कि यद्यपि संबंधित इकाई द्वारा कोई माँग नहीं किया गया था, पूर्व निर्मित चार स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹ 1.06 करोड़ का प्रावधान विभाग द्वारा बजट में किया गया। आवश्यक निर्धारण एवं माँग के बिना की गई अनियमित आवंटन के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण राशि अनुपयोगित रही एवं अभ्यर्पित कर दी गयी।

  - आवंटन पत्र की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 12 जिलों में पंचकर्म थेरेपी केन्द्र स्थापित करने के लिए 15 फरवरी 2014 को ₹ 2.04 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई एवं 20 फरवरी 2014 को निदेशक, आयुष को यह राशि विमुक्त की गई। आवंटन पत्र के माध्यम से मशीनों, उपकरणों, दवाओं इत्यादि की आवश्यकताओं से संबंधित निर्णय के लिए समिति का गठन करने हेतु निदेशक, आयुष को निर्देशित किया गया था। अक्टूबर 2013 से जून 2014 तक निदेशक, आयुष का पद रिक्त होने के कारण उक्त निधि अप्रयुक्त रही। इस प्रकार, विभाग आवंटन से पूर्व योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन नहीं कर सका, परिणामस्वरूप राशि अंतिम रूप से अभ्यर्पित कर दी गई।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि (अक्टूबर 2014) कि मामले को भविष्य के लिए अंकित कर लिया गया है।

2.7.3 अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 115 के अनुसार, अनुपूरक माँग सैद्धान्तिक रूप से अवांछनीय है तथा इसका स्वतंत्र आश्रय निश्चित रूप से बजटीय नियंत्रण में कमी को इंगित करती

है। निधि के वास्तविक प्रावधान के प्रश्न के अलावे, उनकी अनुमान्यता की गंभीरता पूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए। अनुपूरक माँग की प्रमाणिकता उन परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए जो अपवादस्वरूप हो।

हमलोगों ने पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय के पूर्वानुमान के आधार पर अनुपूरक अनुदान के माध्यम से ₹ 31.31 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी। कुल अनुपूरक अनुदानों में से 16 उप-शीर्षों (***परिशिष्ट 2.13***) के अन्तर्गत किया गया ₹ 14.39 करोड़ का प्रावधान अनुचित साबित हुआ, चूँकि इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्यय बजट आकलन के मूल प्रावधानों से भी कम था।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि भविष्य में इन तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.7.4 निधियों का विलम्ब से विमुक्त किया जाना

विभाग द्वारा 12 जनवरी 2013 को मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए ₹ 6.78 लाख की स्वीकृति दी गई तथा 29 मार्च 2014 को कार्यपालक अभियंता, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को आवंटित की गई राशि संबंधित इकाई द्वारा 31 मार्च 2014 को प्राप्त की गई। निधि की विलंब से विमुक्ति तथा प्राप्ति के कारण संपूर्ण आवंटन अप्रयुक्त रही।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

2.7.5 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अन्तर्गत, जैसा कि कंडिका 2.5 में वर्णित है, व्यय के वेग से, विशेषकर अन्तिम माह में, बचा जाना चाहिए।

हमलोगों ने पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान 26 उप-शीर्षों (कुल 136 में से) के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 187.52 करोड़ में से ₹ 141.24 करोड़ (76 *प्रतिशत*) का व्यय मार्च 2014 में किया गया (***परिशिष्ट 2.14***)।

आगे, 11 ईकाईयों[5] के मासिक लेखे तथा बजट नियंत्रण पंजी की जाँच से यह उजागर हुआ कि वर्ष 2013-14 के दौरान इन इकाईयों में ₹ 98.21 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 38.07 करोड़ (27 से 100 *प्रतिशत* तक) का व्यय मार्च 2014 में किया गया (***परिशिष्ट 2.15***)। वर्ष के अंतिम माह में इतना विशाल व्यय बजट नियमावली के नियम 113 के प्रावधान के प्रतिकूल है।

---

[5] (i) का.अ. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, (ii) का.अ., उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, (iii) का.अ., कोल्हान प्रमण्डल, (iv) रिनपास, (v) अधीक्षक, सदर अस्पताल, राँची, (vi) सी.एस. सह सी.एम.ओ, राँची, (vii) रिम्स, (viii) अधीक्षक, सदर अस्पताल, हजारीबाग (ix) सी.एस. सह सी.एम.ओ, जमशेदपुर, (x) एम.जी.एम.एम.सी.एच., जमशेदपुर, (xi) सी.एस. सह सी.एम.ओ, चाईबासा।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया जा रहा है।

2.7.6 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावना से बचने के लिए बजट नियमावली के नियम 134 के अन्तर्गत मासिक आधार पर महालेखाकार के बही से विभागीय लेखाओं के समाशोधन करने की आवश्यकता होती है।

हमलोगों ने पाया कि विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,132.81 करोड़ के कुल व्यय में से केवल ₹ 9.81 करोड़ (0.86 *प्रतिशत*) की राशि का समाशोधन अगस्त 2014 तक किया। इस प्रकार, उपर्युक्त नियम के प्रतिकूल ₹ 1,123.00 करोड़ का व्यय असमाशोधित रही (***परिशिष्ट 2.16***)।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि इस संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया जा रहा है।

2.7.7 निधि आहरित कर बैंक खाते तथा व्यक्तिगत बही खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता यथा राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत, का नियम 300 बतलाता है कि जब तक तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से राशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। कार्यों के कार्यान्वयन, जिसके पूर्ण होने में समय लगने की संभावना हो, के माँग की प्रत्याशा में अथवा निधि के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से अग्रिम राशि आहरित करना अनुमान्य नहीं है। आगे, नियम यह दर्शाता है कि अगर राशि अग्रिम के रूप में आहरित कर ली गई हो तो, अप्रयुक्त शेष राशि यथाशीघ्र चालान के माध्यम से अथवा अगले विपत्र में कम आहरण के माध्यम से तथा किसी भी परिस्थिति में, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें राशि का आहरण किया गया है, कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए।

- वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभागीय स्वीकृति/आवंटन आदेश के विरूद्ध, निदेशक प्रमुख ने ए.सी. विपत्र के माध्यम से ₹ 27.00 करोड़ की राशि आहरित की, तथा झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास एवं प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जे.एम.एच.आई.डी.पी.सी.एल.) को दवाओं, उपकरणों इत्यादि की खरीद के लिए अंतरित किया गया (दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 के बीच)। जे.एम.एच.आई.डी.पी.सी.एल. ने राशि को चार बैंक खाते में रखा तथा जुलाई 2014 तक खर्च नहीं किया। इस प्रकार, पूरी राशि ₹ 27.00 करोड़ को तत्काल भुगतान के उद्देश्य से आहरित नहीं किया गया तथा इसे सरकारी खाते के बाहर रखा गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को राज्य योजना बजट के माध्यम से विकास कार्य के लिए अनुदान के रूप में ₹ 20.00 करोड़ प्राप्त हुआ (27 मार्च 2014)। सम्पूर्ण राशि व्यक्तिगत बही खाते में जमा की गई (28 मार्च 2014) तथा जुलाई 2014 तक अप्रयुक्त रही।

  इस प्रकार उपरोक्त मामलों में, ₹ 47.00 करोड़ के प्रावधान की तत्काल आवश्यकता नहीं थी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन कर राशि को बैंक खाते/व्यक्तिगत बही खाते में रखा गया जो विभाग द्वारा बजटीय नियंत्रण के अभाव को प्रदर्शित किया।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि क्रय प्रक्रियाधीन है तथा निदेशक, रिम्स को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है।

2.7.8 विस्तृत आकस्मिक विपत्र का अप्रस्तुतीकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता का नियम 320 यह बतलाता है कि नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और समर्थित उप-अभिश्रवों सहित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39 में) को अगले माह की 25$^{वीं}$ तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है।

हमलोगों ने पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग में ए.सी. विपत्र के माध्यम से ₹ 50.24 करोड़ की राशि आहरित की गई जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 62.18 लाख का डी.सी. विपत्र सितम्बर 2014 तक जमा किया गया जिसके फलस्वरूप शेष राशि ₹ 49.61 करोड़ (***परिशिष्ट 2.17***) असमायोजित रही। छः नमूना-जाँचित इकाईयों में हमलोगों ने पाया कि निधियों के अप्रयुक्त रहने तथा विभिन्न लाभुक अस्पतालों द्वारा अभिश्रवों को जमा नहीं करने के कारण डी.सी. विपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

झारखण्ड कोषागार संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल, समय पर डी.सी विपत्र जमा नहीं करना, विभाग द्वारा बजटीय नियंत्रण के अभाव तथा कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है।

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को डी.सी. विपत्र जमा करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है।

2.7.9 निधि का अनियमित आहरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 318 के अन्तर्गत, भुगतान के पश्चात नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता वाले आकस्मिक प्रभारों को बिना किसी समर्थित अभिश्रवों के ए.सी. विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 38 में) पर कोषागार से अग्रिम का आहरण किया जा सकता है। व्यय तत्संबंधी सेवा-शीर्ष के नामे लिखा जाएगा। नियम 320 एवं 322 के अन्तर्गत, डी.सी. विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39 में) नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं समर्थित उप-अभिश्रवों के साथ आगामी माह की 25$^{वीं}$ तारीख तक

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास जमा कराना आवश्यक है। विभाग की स्वीकृत्यादेश के अनुसार, बी.पी.एल. परिवारों के लिए असाध्य रोग योजना के तहत चिकित्सा सहायता निधि को ए.सी. विपत्र से आहरित किया जाना था।

संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमलोगों ने पाया कि स्वीकृत्यादेश के निर्देशों के आधार पर ₹ 9.46 करोड़ के आवंटन में से, टी.सी. प्रपत्र 38 के बदले टी.सी. प्रपत्र 37 तथा टी.सी. प्रपत्र 76 (क्रमश: पूर्ण अभिश्रव सहित आकस्मिक विपत्र तथा ऋण एवं अग्रिम की निकासी में प्रयुक्त होने वाले) में तैयार किये गये विपत्र के माध्यम से चार इकाईयों द्वारा कोषागार से ₹ 2.98 करोड़ की निकासी की गई। इस प्रकार टी.सी. प्रपत्र 37 तथा टी.सी. प्रपत्र 76 से निधि की निकासी अनियमित थी क्योंकि निधि की निकासी न तो पूर्ण अभिश्रव सहित आकस्मिक विपत्र से थी और न ही अग्रिम, तथा यह नियम 318 के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की भी उपेक्षा थी। इस प्रकार व्यवस्था के दुर्विनियोजन को अनुरक्षित बनाया गया, क्योंकि टी.सी. प्रपत्र 37 तथा टी.सी. प्रपत्र 76 पर आहरित की गई राशि के विरूद्ध नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उप-अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि मामलों को भविष्य के लिए अंकित कर लिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित प्रपत्र में ए.सी. विपत्र आहरण करने एवं तत्पश्चात डी.सी. विपत्र जमा करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है।

2.8 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट आकलन के कारण बड़ी बचत

- वर्ष 2013-14 के दौरान अनुचित बजट आकलन को दर्शाते हुए कुल बचत प्रावधान ₹ 43,121.68 करोड़ के विरूद्ध ₹ 13,130.13 करोड़ (30 *प्रतिशत*) की अत्यधिक बचत थी। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के तहत अत्यधिक बचत राज्य में विकास योजनाओं के अनुपालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। समाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में कार्यरत 15 विभागों में भी विगत पाँच वर्षों से सतत् बचत देखा गया।

  सरकारी विभागों में अत्यधिक बचत को रोकने के लिए बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया को सशक्त करनी चाहिए, विशेष रूप से जहाँ निरंतर बचत की गई तथा अनुपूरक अनुदान लेने से परहेज करना चाहिए जो अप्रयुक्त रहते है।

आकस्मिक निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 के दौरान आकस्मिक निधि से 45 अवसरों पर ₹ 336.33 करोड़ अग्रिम के रूप में वैसे व्यय के लिए निकाले गए जो न तो अप्रत्याशित और न ही आकस्मिक प्रवृति के थे।

आकस्मिक निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृति के व्यय को पूरा करने के लिए ही की जानी चाहिए।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से परे ₹ 694.05 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावे, वर्ष 2001-2013 के दौरान की गई अधिक व्यय को अभी भी विनियमित किया जाना बाकी है।

  वर्तमान वर्ष के अधिक व्यय के साथ-साथ पूर्व के वर्षों में किए गए अधिक व्यय के विनियमितिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2013-14 के दौरान नियंत्रक अधिकारियों ने महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ विभागों के कुल व्यय के 59 *प्रतिशत* तथा कुल प्राप्तियों के 41 *प्रतिशत* का समाशोधन नही किया।

  नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार के बही के साथ अपने व्यय तथा प्राप्तियों के आँकड़ों का प्रत्येक माह समाशोधन करना चाहिए।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव हुआ।

  स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को विभाग में बजट अनुवीक्षण प्रणाली को अपनाते हुए बजट नियमावली के प्रावधानों का सर्वथा अनुसरण करना चाहिए।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान (स.अ.) सहायता, दान या अंशदान के रूप में भुगतान का तरीका है जो कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। स.अ. संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों, निकायों और संस्थानों को दिया जाता है। उसी प्रकार, राज्य सरकार भी स.अ. का संवितरण अभिकरणों, निकायों और संस्थानों यथा विश्वविद्यालय, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य को करती है। इस तरह निर्गत अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों और संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन के व्यय की प्रतिपूर्ति और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वित्त नियमावली (झा.वि.नि.) का नियम 341 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतना ही स.अ. दिया जाना चाहिए जिनके व्यय होने की संभावना उस वर्ष के दौरान हो, स.अ. के लिए विपत्र को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को यह देखना चाहिए कि राशि की निकासी आवश्यकता से पूर्व नहीं की जाये।

झा.वि.नि. का नियम 342 बतलाता है कि यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हैं तो विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्रपत्र जी.एफ.आर. 19ए में उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

झारखण्ड में, वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान आहरित स.अ. विपत्रों के विरूद्ध, ₹ 6,543.82 करोड़ के कुल 5,264 उ.प्र.प. विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2014 को बकाये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

अधिक संख्या में उ.प्र.प. के बकाया रहने के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक अनुपालन लेखापरीक्षा माह जून और अगस्त 2014 के बीच किया गया। तदनुसार, पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग (पं.रा. एवं रा.ग्रा.रो.का.वि.) और शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) जिसमें ₹ 3,321.89 करोड़ के 4,105 उ.प्र.प. बकाये थे जो कि कुल बकाये राशि के 50 *प्रतिशत* से अधिक थे, को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। आगे, दोनों विभागों से संबंधित ₹ 601.23 करोड़[1] के 25 बकाये उ.प्र.प. के विस्तृत जाँच के लिए तीन जिलों[2] का चयन किया गया था।

3.1.2 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग और शहरी विकास विभाग में बकाये उ.प्र.प. की स्थिति

31 मार्च 2014 को पं.रा. एवं रा.ग्रा.रो.का.वि. एवं श.वि.वि. से संबंधित ₹ 3,321.89 करोड़ के बकाये उ.प्र.प. की वर्षवार स्थिति **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2014 को चयनित विभागों द्वारा वर्ष 2006-13 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के बकाये उ.प्र.प. को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान के संवितरण का वर्ष	पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का (विशेष प्रमण्डल)		शहरी विकास	
	बकाये उ.प्र.प.की संख्या	राशि	बकाये उ.प्र.प. की संख्या	राशि
2006-07	72	140.95	186	24.21
2007-08	26	48.13	189	45.49
2008-09	55	251.03	352	114.12
2009-10	38	156.86	585	194.00
2010-11	99	250.84	522	142.12
2011-12	64	259.97	390	146.64
2012-13	566	1031.57	961	515.96
कुल	**920**	**2139.35**	**3185**	**1182.54**

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि, पं.रा. एवं रा.ग्रा.रो.का.वि. का ₹ 2,139.35 करोड़ (920 उ.प्र.प.) एवं श.वि.वि. का ₹ 1,182.54 करोड़ (3,185 उ.प्र.प.) जो वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक संबंधित थे, 31 मार्च 2014 को बकाया था। झा.वि.नि. के नियम 342 के अनुसार, उ.प्र.प. को सहायता अनुदान स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन, उ.प्र.प. का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा अप्रस्तुतीकरण की अवधि एक से छः वर्ष थी।

---

[1] पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग -14 मामले - ₹ 379.43 करोड़ एवं शहरी विकास विभाग -11 मामले - ₹ 221.80 करोड़।

[2] देवघर, पूर्वी सिंहभूम और राँची।

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा उ.प्र.प्र. को जमा नहीं करने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि क्या यह अनुदान वास्तव में उपयोग किए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में लंबित उ.प्र.प. का प्रस्तुतीकरण, विभाग के अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है।

25 नमूना-जाँचित मामलों के विस्तृत परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि अनुदान का अनुपयोग, अनुदान को बैंक खातों में अवरूद्ध रखना, कोषागार से अनुदान का निकासी नहीं करना, अनुदान के निर्गत करने में विलंब, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उ.प्र.प. का गलत प्रस्तुतीकरण इत्यादि उ.प्र.प. के बकाये रहने के कारण थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण अनियमिततायें विस्तृत रूप से नीचे दर्शाये गये हैं:

3.1.3 अनुदानों को निर्गत करने में विलम्ब

शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) (₹ 53.51 करोड़) एवं जल आपूर्ति योजना (डब्लू.एस.एस.) (₹ 21.63 करोड़) के लिए राँची जिले में जवाहरलाल नेहरू शहरी ग्रामीण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अन्तर्गत कुल ₹ 75.14 करोड़ अनुदान के रूप में स्वीकृत किया (मार्च 2010)। श.वि.वि. के अवर सचिव अनुदान की निकासी के लिए डी.डी.ओ. थे। सारे अनुदान कोषागार से आहरित कर, वृहत राँची विकास अभिकरण (जी.आर.डी.ए.), जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. का राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण है, को कार्यान्वयन अभिकरणों को अग्रेतर सम्प्रेषण के लिए हस्तांतरित किया गया (मार्च 2010)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि जी.आर.डी.ए. ने अनुदान कार्यान्वयन अभिकरण, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) राँची नगर निगम को अनुदान प्राप्ति के 12 से 23 माह के विलम्ब से निर्गत किया जैसा कि **तालिका 3.2** में विस्तृत है।

तालिका 3.2: कार्यान्वयन अभिकरण को अनुदान निर्गत करने में विलम्ब को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

अनुदान की स्वीकृति		जी.आर.डी.ए. के द्वारा अनुदान की प्राप्ति		जी.आर.डी.ए. द्वारा निर्गत किया गया अनुदान		विलम्ब माह में	अभिकरण
आदेश/दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		
195/25.3.2010	53.51	31.3.2010	53.51	11.2.2012	53.51	23	सी.ई.ओ., राँची नगर निगम को बी.एस.यू.पी. योजना के लिए
147/3.3.2010	21.63	23.3.2010	21.63	29.3.2011	21.63	12	सी.ई.ओ., राँची नगर निगम को डब्ल्यू.एस.एस. के लिए
कुल	**75.14**		**75.14**		**75.14**		

जवाब में, जी.आर.डी.ए. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2014) कि बी.एस.यू.पी. योजना के लिए अनुदान निर्गत करने में विलंब पूर्ववर्ती अनुदानों का अनुपयोग किया जाना था और डब्ल्यू.एस.एस. के संबंध में, विलम्ब का कारण कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उ.प्र.प. एवं कार्य योजनाओं का अप्रस्तुतीकरण था।

कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्ववर्ती अनुदानों के वास्तविक उपयोग के बिना श.वि.वि. के द्वारा अनुदान का निर्गत किया जाना यह दर्शाता है कि अनुदान शीघ्र उपयोग के लिए नहीं था, जो कि झा.वि.नि. के नियम 341 के विरूद्ध था। आगे, जी.आर.डी.ए. के द्वारा उ.प्र.प. एवं कार्य योजना को प्राप्त करने में असफल रहना, जी.आर.डी.ए. के द्वारा कार्यों के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है, फलस्वरूप उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके लिए अनुदान निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अनुदान को विलम्ब से निर्गत करना इसके वास्तविक उपयोग एवं उ.प्र.प. के प्रस्तुतीकरण को और विलंबित किया।

आगे, सी.ई.ओ., राँची नगर निगम को निर्गत अनुदान राशि ₹ 53.51 करोड़ के जाँच से यह पता चला कि केवल ₹ 7.16 करोड़ का ही उपयोग हुआ और शेष ₹ 46.35 करोड़ का उपयोग, या तो चालू परियोजनाओं के अपूर्ण रहने अथवा बी.एस.यू.पी. योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले योजनाओं को राजीव आवास योजना में शामिल किये जाने, जिनका पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) को भेजा जाना था, के कारण नहीं किया जा सका। अतः, ₹ 46.35 करोड़ अवरूद्ध रहा और उ.प्र.प. जमा नहीं किया जा सका (अगस्त 2014)। जबकि, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत राँची जल आपूर्ति योजना के लिए ₹ 21.63 करोड़ पूर्ण रूप से राँची नगर निगम द्वारा उपयोग कर लिया गया था (अगस्त 2014)।

3.1.4 अनुदान का अनुचित संवितरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण

पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का. (विशेष प्रमंडल) विभाग ने तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कार्य[3] करने के लिए ₹ 57.41 करोड़ का सामान्य बुनियादी अनुदान स्वीकृत किया (सितम्बर 2012)। अवर सचिव ने कोषागार से अनुदान की निकासी (अक्टूबर 2012) कर इसको झारखण्ड के सभी 24 जिलों को रियल टाईम ग्रौस सेंटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) के द्वारा स्थानान्तरित किया, जिसमें से ₹ 3.93 करोड़ सचिव, जिला परिषद, राँची को स्थानान्तरित किया गया था (अक्टूबर 2012)।

[3] पंचायतो के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर एंव कम्प्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था, पंचायत भवनों में जेनरेटर/इन्वर्टर/ सोलर पैनल की व्यवस्था, पंचायत भवनों में उपस्करों की आपूर्ति तथा पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था।

स्वीकृति आदेश के अनुसार, जिला परिषद के द्वारा इन अनुदानों को तत्काल संबंधित ग्राम पंचायतों को उस योजना के लिए खोले गए बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्थानान्तरित करना था। आगे, किये गये व्ययों के उ.प्र.प. को जी.एफ.आर. 19ए के विनिर्दिष्ट प्रपत्र में महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड सहित एक प्रति सचिव, पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का. (विशेष प्रमंडल) विभाग को भेजा जाना था।

सचिव, जिला परिषद, राँची ने अनुदान को ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित करने के बदले उस अनुदान को राँची जिले के 18 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों[4] (बी.डी.ओ.) को ₹ 1,29,794 की दर से 303 ग्राम पंचायतों को अग्रेतर संवितरण के लिए स्थानांतरित किया (नवम्बर 2012)। जिला परिषद के द्वारा आगे उपलब्ध कराई गई सूचना से ज्ञात हुआ कि अन्ततः राशियों को ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में 9 फरवरी 2013 को, अनुमोदित कार्यों को करने के लिए आवंटन की तिथि से चार माह के विलंब से जमा किया गया था।

सचिव ने स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2014) कि भविष्य में अनुदानों का स्थानांतरण ग्राम पंचायतों को सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा।

इन अनुदानों के द्वारा किए गए कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में पूछने पर, सचिव, जिला परिषद ने बताया (जुलाई 2014) कि इन्हें संबंधित प्रखण्डों से प्राप्त कर उपलब्ध कराई जायगी। जबकि, सचिव, जिला परिषद ने ₹ 3.93 करोड़ के सम्पूर्ण अनुदान को वास्तविक रूप में उपयोग दर्शाते हुए उ.प्र.प. विनिर्दिष्ट प्रपत्र जी.एफ.आर. 19ए में पहले ही भेज दिया था (मार्च 2013)।

इस प्रकार, सचिव ने किए गए कार्य और उस पर किए गए व्यय की वास्तविक स्थिति को प्राप्त किए बिना ही महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को गलत उ.प्र.प. प्रस्तुत किया।

ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अनुदान स्थानान्तरित करने के बजाय बी.डी.ओ. को अनुदान अनुचित रूप से निर्गत करने के फलस्वरूप, संवितरण में विलम्ब हुआ और अन्ततः वास्तविक उपयोग को दर्शाते हुए उ.प्र.प. का प्रस्तुतीकरण भी विलंबित हुआ। जिला परिषद के द्वारा त्रुटिपूर्ण उ.प्र.प. का प्रस्तुतीकरण न केवल उनके कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है, बल्कि उ.प्र.प. के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है।

3.1.5 अनुदान का अवरूद्धिकरण एवं अनुपयोग

जैसा कि कंडिका 3.1.1 में पहले ही कहा जा चुका है, किसी राशि की निकासी आवश्यकता के पूर्व नहीं की जानी चाहिए (झा.वि.नि. का नियम 341)। आगे, विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोषागार से आहरित की गई राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के अंदर कर दिया जाना चाहिए। पुनः झारखण्ड कोषागार

[4] अनगड़ा, बेड़ो, बुंडू, बुड़मू, चान्हो, इटकी, काँके, खेलारी, लापूंग, माण्डर, नगड़ी, नामकुम, ओरमांझी, राहे, रातू, सोनाहातू, सिल्ली और तमाड़।

संहिता (झा.को.सं.) के नियम 300 के अनुसार राशि की निकासी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक उसका तुरंत भुगतान आवश्यक नहीं हो। कोषागार से प्रत्याशित माँगों के लिए आहरण, चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए, जिसको करने में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है, या विनियोगों को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनुमान्य नहीं है। नियम आगे यह भी बतलाता है कि यदि राशि की अग्रिम निकासी की गई है तो आहरित की गई राशि के अव्ययित शेष को अगले विपत्र में कम निकासी करते हुए या चालान के द्वारा यथाशीघ्र परन्तु किसी हाल में उस वित्तीय वर्ष के अंत होने से पहले, जिसमें राशि की निकासी की गई थी, कोषागार को वापस कर देना चाहिए।

बकाया उ.प्र.प. के नमूना जाँच के दौरान अनुदान अवरूद्धिकरण के निम्नलिखित मामले पाये गए :

- राज्य विशेष आवश्यकता के अन्तर्गत बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर भारी अभियांत्रिकी निगम (एच.ई.सी.) लिमिटेड, राँची के पुनरुद्धार के लिये कुल स्वीकृत अनुदान की राशि ₹ 275.51 करोड़ के विरूद्ध शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) ने एच.ई.सी. लिमिटेड को भुगतान के लिये ₹ 36 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी (मार्च 2010)। एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा गैर-अतिक्रमित 354.25 एकड़[5] की भूमि एवं मकान राज्य सरकार को सुपुर्दगी के बाद एच.ई.सी. लिमिटेड को अनुदान का भुगतान किया जाना था। अवर सचिव ने कोषागार से अनुदान की निकासी (मार्च 2010) की और इसे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एच.ई.सी. लिमिटेड के पक्ष में निर्गत 30 सितम्बर 2010 तक वैध बैंकर्स चेक के रूप में सचिव, उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया। चूँकि 354.25 एकड़ की भूमि जो अतिक्रमणाधीन थी, एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को सुपुर्द नहीं किया गया था, उक्त बैंकर्स चेक, व्यपगत बैंकर्स चेक (जून 2014) के रूप में सचिव, उद्योग विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ा रहा।

  चूँकि अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका, इसलिए श.वि.वि. द्वारा इसके विरूद्ध उ.प्र.प. नहीं जमा किया जा सका।

- श.वि.वि. ने देवघर नगर निगम को क्लब मैदान, देवघर में एक पार्क के निर्माण के लिए ₹ 1.41 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं आवंटन दिया (मार्च 2011)। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.), देवघर नगर निगम ने ₹ 1.41 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को कोषागार से निकासी कर अपने व्यक्तिगत बही (पी.एल) खाते में जमा (मार्च 2011) किया।

[5] कुल 2,342 एकड़ भूमि एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा ₹ 275.51 करोड़ का भुगतान प्राप्त करने के उपरांत हस्तगत कराना था, इसमें से 1,987.75 एकड़ पहले ही राज्य सरकार को हस्तगत करा दी गई थी।

पार्क के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका (जुलाई 2014) क्योंकि निर्माण के लिये चयनित भूमि माननीय उच्च-न्यायालय झारखण्ड में वर्ष 2005 से ही न्यायाधीन थी। सी.ई.ओ. ने विभाग से चिल्ड्रेन्स पार्क, जलसार के उन्नयन पर अनुदान का उपयोग करने की अनुमति के लिए आग्रह (मार्च 2013 एवं जनवरी 2014) किया। विभाग द्वारा इसकी अनुमति अभी तक (जुलाई 2014) नहीं दिया गया एवं पार्क निर्माण के लिए आवंटित कुल ₹ 1.41 करोड़ की राशि तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अवरूद्ध रहा।

अव्यवहृत अनुदान की राशि को झा.वि.नि. के नियम 341 एवं झा.को.सं के नियम 300 के विरूद्ध पी.एल. खाते में अवरूद्ध रखने के परिणामस्वरूप उ.प्र.प. नहीं जमा किया जा सका। इसके अतिरिक्त, विवादित भूमि पर पार्क निर्माण की स्वीकृति कार्यों के अनुचित चयन को दर्शाया, जो अनुदान के स्वीकृति की दोषपूर्ण प्रक्रिया को प्रतिबिंबित किया।

- ग्रेटर राँची विकास अभिकरण (जी.आर.डी.ए.) जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य का नोडल अभिकरण है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. से संबंधित अनुदान श.वि.वि. के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा आहरित किया जाता है एवं जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जी.आर.डी.ए. को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

  जी.आर.डी.ए. से प्राप्त सूचना के जाँच से पता चला कि श.वि.वि. ने जी.आर.डी.ए., राँची को दो स्वीकृत आदेश के द्वारा ₹ 1.02 करोड़ का अनुदान निर्गत किया (अप्रैल 2010) जिसको कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा नगरपालिका तथा हजारीबाग नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर संवितरित करना था। किन्तु, यह राशि जुलाई 2014 तक दोनों कार्यपालक पदाधिकारियों को संवितरित नहीं किया गया था। अतएव, उक्त राशि जी.आर.डी.ए. के पास चार वर्षों से अधिक समय तक अवरूद्ध रहा जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ एवं तदनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रस्तुत नहीं हुआ।

  जवाब में, जी.आर.डी.ए. ने इसे स्वीकार किया एवं कहा (अगस्त 2014) कि लोहरदगा नगरपालिका तथा हजारीबाग नगर परिषद को उनके विरूद्ध चल रहे जाँच के पूर्ण नहीं होने के कारण अनुदान निर्गत नहीं किया गया।

  संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा किये जा रहे जाँच के पूर्ण होने में हो रहे विलंब एवं उक्त अनुदानों को जी.आर.डी.ए. से वापस लेकर किसी अन्य योजना में उपयोग नहीं किया जाना विभाग के अप्रभावी अनुश्रवण को दर्शाता है।

- पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का. (विशेष प्रमण्डल) विभाग ने राँची जिला के 2,052 ग्राम सभाओं के विकासात्मक कार्यों के लिए ₹ 11.29 करोड़ का

अनुदान स्वीकृत (दिसम्बर 2006) किया। अनुदान को ₹ 55,000 प्रति ग्राम सभा के दर से सभी ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित किया जाना था। उक्त अनुदान जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डी.पी.आर.ओ.), राँची द्वारा कोषागार से आहरित (मार्च 2007) किया गया, जिसमें से ₹ 10.54 करोड़ 1,916 ग्राम सभाओं को निर्गत किया गया (अप्रैल 2007 से अगस्त 2008 तक) एवं ₹ 74.80 लाख अनिर्गत रहा क्योंकि कुछ ग्राम सभाओं के बैंक खाते नहीं खोले गए थे एवं कुछ ग्राम सभा अन्य जिलों (खूँटी) के क्षेत्राधिकार में पड़ते थे। उपायुक्त (डी.सी.), राँची ने ₹ 74.80 लाख के अव्यवहृत अनुदान को राँची जिला के ग्राम सभाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु खर्च करने के लिए विभाग से अनुरोध (जून 2010) किया, किन्तु, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2014)। इसके बाद, उपायुक्त द्वारा न तो विभाग से कोई पत्राचार किया गया और न ही अनुदान की शेष राशि सरकारी खाते में जमा करायी गयी। अतएव, ₹ 74.80 लाख की अनिर्गत अनुदान डी.पी.आर.ओ. द्वारा सात वर्षों से अधिक अवधि तक अपने चालू बैंक खाते में अवरूद्ध कर रखा गया।

विभाग द्वारा अव्यवहृत अनुदान के उपयोग के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करने की विफलता तथा उपायुक्त एवं डी.पी.आर.ओ. द्वारा उस राशि का सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना, अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

इस प्रकार, ग्राम सभाओं के विकासात्मक कार्यों को अनुदान के अनुपयोग रहने के कारण संपन्न नहीं कराया जा सका, जिसके कारण अन्ततः उ.प्र.प. अप्रस्तुत रहा।

- श.वि.वि. ने देवघर नगर निगम को सभागार के निर्माण कार्य एवं रंगीन इंटरलॉकिंग पेभर्स बिछाने के लिए ₹ 7.24 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2011) और ₹ 5.76 करोड़[6] निर्गत किया (मार्च 2011)। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.), देवघर नगर निगम ने उपलब्ध अनुदान ₹ 5.76 करोड़ के विरूद्ध कार्य में केवल ₹ 1.35 करोड़[7] ही व्यय किए और संवेदक द्वारा सभागार के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण एवं रंगीन इंटरलॉकिंग पेभर्स बिछाने के कार्य को विलंब से प्रारम्भ किये जाने के कारण, ₹ 4.41 करोड़ अव्यवहृत रहे (जुलाई 2014)।

  जवाब में, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2014) कि तथ्य की जाँच की

[6] शिल्पग्राम में सभागार निर्माण कार्य - अनुमोदित प्राक्कलित राशि: ₹ 2.76 करोड़; निर्गत राशि: ₹ 2.76 करोड़ (ii) रंगीन इंटरलॉकिंग पेभर्स का बिछाना - अनुमोदित प्राक्कलित राशि: ₹ 4.48 करोड़; निर्गत राशि: ₹ 3.00 करोड़।

[7] सभागार निर्माण: ₹ 85.78 लाख एवं इंटरलॉकिंग पेभर्स: ₹ 48.73 लाख।

जायेगी, कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं अनुदानों का शीघ्र उपयोग किया जायेगा।

आवंटन की तिथि के तीन वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य पूर्ण होने में विलम्ब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है जिससे उ.प्र.प. का अप्रस्तुतीकरण हुआ।

इस प्रकार, बिना किसी तात्कालिक उपयोग के लिए अनुदान की निकासी तथा इसे अवरूद्ध एवं अव्यवहृत रखना, विनियोग अधिनियम, वित्तीय नियमों एवं कोषागार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। यह विभाग द्वारा कमजोर योजना एवं अनुश्रवण को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप अनुदान का अनुपयोग और अंततः उ.प्र.प. का अप्रस्तुतीकरण हुआ।

3.2 कल्याण विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा

पृष्ठभूमि

झारखण्ड में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों के द्वारा कोषागार से अग्रिम निधि का आहरण असामान्य तौर पर ज्यादा रहा है। वर्ष 2000-14 के दौरान 54,563 ए.सी. विपत्रों पर कुल ₹ 15,135 करोड़ की राशि का आहरण किया गया था, जिसमें से 17,778 विपत्रों से संबंधित ₹ 5,162 करोड़ 30 जून 2014 तक बकाया रहा। अग्रिम तब तक बकाया रहता है जब तक कि नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) सहायक अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंप नहीं देता है। ए.सी. विपत्रों पर आहरित बकाया राशि के लिए डी.सी. विपत्र नहीं सौंपने की स्थिति में हम लोग लेखापरीक्षा के अंतर्गत यह आश्वासन उपलब्ध करने में असमर्थ है कि क्या आहरित अग्रिम उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हुए जिन उद्देश्यों के लिए यह स्वीकृत किया गया था।

3.2.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) का नियम 290 आकस्मिक व्यय को "सभी आकस्मिक एवं अन्य व्यय जो किसी कार्यालय को कार्यालय के रूप में रखने के लिए प्रबंधन या विभागों के तकनीकि कार्यों के लिए खर्च होते हैं" के रूप में परिभाषित करती है। आकस्मिक व्यय जिस पर भुगतान के बाद नि.अ. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है, को बिना कोई सहायक अभिश्रव (झा.को.सं. का नियम 318) के कोषागार से ए.सी. विपत्रों (टी.सी. प्रपत्र-38) के माध्यम से अग्रिम के रूप में आहरित किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा-शीर्षों के अंतर्गत विकलित किया जाता है और नि.अ.[8] द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सहायक उप-अभिश्रव के साथ डी.सी. विपत्र

[8] झा.को.सं. का नियम 320 ।

(टी.सी. प्रपत्र 39 में)[9] संबंधित माह के अगले माह[10] के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु उपस्थापित प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि पिछले माह आहरित ए.सी. विपत्र के लिए विस्तृत विपत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रक अधिकारी को सौंप दी गई है (झा.को.सं. का नियम 319)।

आगे, झा.को.सं. का नियम 300 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषागार में आकस्मिक विपत्र जमा करने के समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डी.डी.ओ.) को यह प्रमाणित करना होता है कि विपत्र राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के भीतर कर ली जाएगी और संवितरित नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के कार्यालय में डी.सी. विपत्र प्राप्त होने पर उप-अभिश्रव की संवीक्षा के पश्चात् इसे ए.सी. विपत्रों के साथ समायोजित की जाती है और अंतर या नामंजूरी को वसूली हेतु चिन्हित की जाती है, और गलत वर्गीकरण होने पर इसे समायोजित किया जाता है। इसके बावजूद, आकस्मिक व्यय पर कारगर नियंत्रण की जवाबदेही मुख्यत: कार्यालय प्रधान पर एवं ए.सी. विपत्र के मामलों में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर है।

कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011-14 के दौरान ए.सी. विपत्रों पर आहरित निधियों की एक अनुपालन लेखापरीक्षा सितम्बर-अक्टूबर 2014 में की गई। झारखण्ड में वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 3,192 करोड़ की राशि आहरित की गई थी जिसमें से ₹ 1,383 करोड़ की राशि बकाया (जून 2014) थी जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है। कल्याण विभाग ने इस अवधि में ₹ 164.60 करोड़ का आहरण किया जिसमें से ₹ 161.54 करोड़ बकाया रहा (***परिशिष्ट 3.2***)। राँची जिला में वर्ष 2011-14 के दौरान कल्याण विभाग के तीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी[11] द्वारा 11 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित ₹ 89.71 करोड़ का विस्तृत परीक्षण किया गया।

3.2.2 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण की प्रवृति

ए.सी. विपत्र के माध्यम से निधि के आहरण के समय व्यय को संबंधित सेवा-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। अत: ऐसे निधियों के विशिष्ट उद्देश्यों के

---

[9] यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर कर सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जा सकता है।

[10] झा.को.सं. का नियम 322 ।

[11] (i) उप निदेशक, आदिवासी कल्याण, कल्याण विभाग (ii) जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची एवं (iii) परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची।

लिये उपयोगिता, निर्धारित समय सीमा[12] के अंदर, लेकिन उस वित्तीय वर्ष[13] के 31 मार्च या उससे पहले सुनिश्चित करना आवश्यक है। डी.सी. विपत्रों को समय पर नहीं जमा करना वित्तीय अनुशासनों का उल्लंघन है और यह दुर्विनियोग के जोखिम को उत्पन्न करती है। वर्ष 2000-14 के दौरान ए.सी. विपत्रों से आहरित निधियों का विवरण, जमा किया हुआ डी.सी. विपत्रों एवं इन विपत्रों के विरूद्ध 30 जून 2014 तक बकाया राशि का विस्तृत विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: 30 जून 2014 को बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		जमा किया गया डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2000-2011	52489	11943	35892	8164	16597	3779	32
2011-2012	1059	1600	333	1208	726	392	25
2012-2013	547	925	498	494	49	431	47
2013-2014	468	667	62	107	406	560	84
योग **(2011-2014):**	**2074**	**3192**	**893**	**1809**	**1181**	**1383**	**43**
सकल योग	**54563**	**15135**	**36785**	**9973**	**17778**	**5162**	**34**

स्रोत : वित्त लेखा में लेखा टिप्पणी

तालिका 3.3 से यह देखा जा सकता है कि कुल बकाया राशि ₹ 5,162 करोड़ (जून 2014) में से ₹ 3,779 करोड़ (73 *प्रतिशत*) तीन वर्षों से भी अधिक पुराना है। वर्ष 2000-11 के दौरान आहरित ए.सी. विपत्रों की बकाया राशि कुल आहरित राशि का 32 *प्रतिशत* था। वर्ष 2011-12 के दौरान आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए लंबित मामलों में 25 *प्रतिशत* की कमी आई, जबकि उस वर्ष के दौरान ए.सी. विपत्रों पर आहरित की गई कुल राशि वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लिए क्रमश: 47 *प्रतिशत* एवं 84 *प्रतिशत* बढ़ा।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि ए.सी. विपत्रों के द्वारा राशि के आहरण में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 (₹ 1,059 करोड़ से ₹ 547 करोड़) एवं वर्ष 2013-14 (₹ 547 करोड़ से 468 करोड़) में लगातार कमी आई।

कल्याण विभाग में, ए.सी. विपत्रों से आहरित राशि वर्ष 2011-12 में ₹ 42.96 करोड़ (70 विपत्र) से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 107.06 करोड़ (25 विपत्र) हो गई और फिर घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 14.58 करोड़ (दो विपत्र) हो गई। अगस्त 2014 तक इन ए.सी. विपत्रों की बकाया राशि वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 39.90 करोड़ (66 विपत्र), वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 107.06 करोड़ (25 विपत्र) एवं वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 14.58 करोड़ (दो विपत्र) थी (***परिशिष्ट 3.2***)।

---

[12] किसी माह के एक तारीख से अगले माह के 10 तारीख तक विस्तृत विपत्र नि.अ. को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपस्थापन (झा.को.सं. का नियम 319)।

[13] झा.को.सं. का नियम 300 ।

3.2.3 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के जमा करने में विलम्ब

झा.को.सं. के नियम 322 के अनुसार डी.सी. विपत्र संबंधित माह के अगले माह के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को भेज दी जाएगी।

कल्याण विभाग से संबंधित नमूना-जाँचित 11 ए.सी. विपत्रों की संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.प.) राँची द्वारा ₹ 53.52 लाख की राशि दो ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित (मार्च 2012) किया गया। जिसके ब्यौरे **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के जमा करने में विलम्ब

क्र. सं.	विपत्र संख्या	कोषागार से निकासी की तिथि	राशि (₹ लाख में)	डी.सी. विपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि	डी.सी. विपत्र जमा करने की तिथि	विलम्ब माह में
1	285/11-12	31.03.2012	24.33	25.04.2012	20.06.2014 और 04.07.2014	26
2	288/11-12	31.03.2012	29.19	25.04.2012	20.06.2014 और 04.07.2014	26
कुल			**53.52**			

स्रोत : जिला कल्याण पदाधिकारी राँची द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

झा.को.सं. के नियमानुसार डी.सी. विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड राँची को 25 अप्रैल 2012 तक जमा कर दिया जाना था। लेकिन **तालिका 3.4** से यह स्पष्ट होता है कि डी.सी. विपत्र लगभग 26 माह के विलम्ब के साथ जून और जुलाई 2014 में जमा किया गया।

जवाब में जि.क.प., राँची ने स्वीकार किया एवं कहा (सितम्बर 2014) कि डी.सी. विपत्र जमा करने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से विलम्ब से मापी-पुस्तिका एवं अभिश्रवों की प्राप्ति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2012 से मार्च 2013 के दौरान नमूना-जाँचित शेष नौ विपत्रों से संबंधित ₹ 89.17 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्रों के माध्यम से समायोजन अभी भी (अगस्त 2014) बाकी था।

परियोजना निदेशक (प.नि.), समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (स.ज.वि.अ.) ने इसे स्वीकार किया एवं जवाब दिया (अक्टूबर 2014) कि डी.सी. विपत्रों को जमा नहीं करने का कारण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं करना था। आदिवासी कल्याण आयुक्त (आ.क.आ.), कल्याण विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.2.4 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से योजना निधि का आहरण

ए.सी. विपत्रों के माध्यम से योजना निधि का आहरण अनुमान्य नहीं है क्योंकि यह आकस्मिक प्रकृति का नहीं होता है।

- हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2011-14 के दौरान 97 ए.सी. विपत्रों पर आहरित कुल ₹ 164.60 करोड़ में से ₹ 160.01 करोड़ (97 *प्रतिशत*) योजना निधि की थी। इन योजना निधियों के विरूद्ध महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को मात्र ₹ 3.06 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्र जमा किया गया और अगस्त 2014 तक ₹ 156.95 करोड़ बकाया रहा।

- नमूना-जाँचित ए.सी. विपत्रों के संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कल्याण विभाग ने दो डी.डी.ओ.[14] को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 77.18 करोड़ की राशि आवंटित (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012) किया एवं एक मुश्त अग्रिम के रूप में आहरण की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण निधि ₹ 77.18 करोड़ का आहरण (जनवरी 2013 एवं मार्च 2013) कोषागार से अग्रिम के रूप में दो ए.सी. विपत्रों के माध्यम से कर लिया गया। चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आवंटित राशि अनुदान है, इसलिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका निर्गमन 'सहायता अनुदान' (जी.आइ.ए.) के रूप में किया जाना था। तथापि, हमलोगों ने देखा कि चूँकि राज्य बजट में विस्तृत शीर्ष 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत लघु (कार्यक्रम) शीर्ष (796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना) - उप-शीर्ष (08-सविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता) नहीं था, इसलिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा निधियों का आहरण जी.आई.ए. विपत्रों पर नहीं किया जा सका।

  ए.सी. विपत्रों पर जी.आई.ए. निधियों का आहरण, झारखण्ड में अधिक बकाया ए.सी. विपत्रों की राशि के कारणों में से एक था।

  आगे, हमलोगों ने अवलोकन किया कि निधियों के एक मुश्त अग्रिम के आहरण की अनुमति विभाग द्वारा बिहार वित्त विभाग के दिनांक 17 अप्रैल 1998 के आदेश की कंडिका 15 के प्रावधान, यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत, का उद्धरण देकर दिया गया जिसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग के सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निधियों के अग्रिम आहरण की अनुमति केवल वैसे वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए कर सकता है जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता है।

---

[14] आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची (₹ 69.96 करोड़) एवं परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची (₹ 7.22 करोड़)।

उपरोक्त सरकारी आदेश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सम्पूर्ण निधियों के एक मुश्त अग्रिम आहरण की स्वीकृति अनियमित थी, क्योंकि अग्रिम का आहरण केवल वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए नहीं किया गया।

विभाग से जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.2.5 वित्तीय वर्ष के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से आहरित राशि का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना चाहिए। आगे, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से कोई भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसका तुरंत भुगतान आवश्यक न हो। कोषागार से प्रत्याशित मांगों के लिए अग्रिम आहरण चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिसका सम्पादन में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है, या विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए, अनुमान्य नहीं है। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से निधि का आहरण करते समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रमाणित करना पड़ता है कि वित्तीय वर्ष के भीतर समस्त निधियों का भुगतान कर दिया जाएगा।

वर्ष 2011-14 के दौरान कल्याण विभाग एवं राँची जिला के नमूना-जाँचित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी[15] द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित राशि **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्रों का आहरण

(₹ *करोड़ में*)

	कुल आहरण		मार्च में आहरित		मार्च के अंतिम सप्ताह में आहरित		31 मार्च को आहरित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कल्याण विभाग	97	164.60	79	59.12(36)	74	55.27(34)	55	35.12(21)
नमूना-जाँचित ए.सी. विपत्र	11	89.71	10	19.75(22)	9	16.67(18.58)	8	14.63(16)

स्रोत : अभिश्रव स्तर कम्प्यूट्राईजेशन (वी.एल.सी.) डाटाबेस

कोष्टक के आँकड़े ए.सी. विपत्र से आहरित राशि का कुल राशि से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2011-14 के दौरान विभाग द्वारा ए.सी. विपत्रों पर आहरित ₹ 164.60 करोड़ में से ₹ 59.12 करोड़ (36 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च माह में किया गया था। इनमें से, ₹ 55.27 करोड़ (34 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च के अन्तिम सप्ताह में किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की आहरित राशि ₹ 35.12 करोड़ थी। मार्च माह में, विशेषकर माह के अंतिम सप्ताह में आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना प्रतीत नहीं होता था।

[15] (i) उपनिदेशक, आदिवासी कल्याण, कल्याण विभाग (ii) जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची एवं (iii) परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., राँची ।

आगे, विभाग के तीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के अभिलेखों के नमूना-जाँच से स्पष्ट हुआ कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ने 10 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 19.75 करोड़ का आहरण (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) किया। इनमें से ₹ 11.20 करोड़ भुगतित/संवितरित या कोषागार में वापस कर दिया गया एवं ₹ 8.55 करोड़ अगस्त 2014 तक अप्रयुक्त रहा। तथापि, ₹ 11.20 करोड़ में से, केवल ₹ 0.22 करोड़ का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष (मार्च 2013) में किया गया एवं ₹ 10.98 करोड़ का भुगतान/संवितरण या कोषागार में वापसी अगले वित्तीय वर्ष में किया गया।

इस प्रकार, ₹ 19.53 करोड़[16] के ए.सी. विपत्रों पर आहरण, जिसका शीघ्र भुगतान करना आवश्यक नहीं था, विनियोग अधिनियम एवं झा.को.सं. के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.2.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से बार-बार निधियों का आहरण

हमलोगों के संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि झा.को.सं. के नियम 319 एवं 320 का उल्लंघन करते हुए दो नमूना-जाँचित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने वर्ष 2011-13 के दौरान पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्रों को जमा किए बगैर बार-बार ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 89.17 करोड़ की राशि का आहरण किया। विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर बार-बार निधियों के आहरण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विपत्रों का आहरण	आहरित विपत्रों की संख्या	राशि
1	उप निदेशक, आदिवासी कल्याण	29 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के बीच	07	81.72
2	परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची	31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के बीच	02	7.45
	कुल		**09**	**89.17**

स्रोत : अभिश्रव स्तर कम्पूयट्राईजेशन (वी.एल.सी.) डाटाबेस

ए.सी. विपत्रों के आहरण के माह के अगले माह के 10 तारीख के बाद कोषागार से ए.सी. विपत्रों के माध्यम से निधियों के आहरण के समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी टी.सी. प्रपत्र 38 में एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है कि चालू माह के पहली तारीख के पहले सभी आकस्मिक व्ययों के लिए डी.सी. विपत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरण एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषण हेतु अग्रसारित कर दी गई है।

[16] ₹ 19.75 करोड़ - ₹ 0.22 करोड़

तालिका 3.6 से देखा जा सकता है कि दोनों निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने तदन्तर ए.सी. विपत्रों के माध्यम से कोषागार से निधियों का ए.सी. विपत्रों पर आहरण, आवश्यक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके किया। अत: निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये क्योंकि पूर्व में जारी किए गए ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र बकाया था।

3.2.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खाते में रखना

झा.को.सं. के नियम 300 के अनुसार निधियों का आहरण तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इसका शीघ्र भुगतान आवश्यक न हो। आगे, वित्तीय नियम सरकारी पैसों को गैर-सरकारी खातों में रखने को निषेध करती है। हमलोगों ने अवलोकन किया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया और यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में पड़ा रहा जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- परियोजना निदेशक (प.नि.), समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची ने जनजातीय कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए दो ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 7.45 करोड़ का आहरण (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) किया। उनमें से 24 सितम्बर 2014 तक केवल ₹ 4.20 करोड़ व्यय हुआ एवं शेष ₹ 3.25 करोड़ सितम्बर 2014 तक आई.टी.डी.ए. के बचत खाते में अप्रयुक्त पड़ा था।

  प.नि., आई.टी.डी.ए., राँची ने इसे स्वीकार किया और जवाब (अक्टूबर 2014) दिया कि योजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

- उप निदेशक, आदिवासी कल्याण, कल्याण विभाग ने विभिन्न जनजातीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोषागार से सात ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 81.72 करोड़ की राशि का आहरण (मार्च 2012 से मार्च 2013) किया जिसमें से ₹ 75.33 करोड़ का भुगतान/संवितरण विभिन्न योजनाओं के लिये किया गया एवं शेष राशि ₹ 6.39 करोड़ सितम्बर 2014 तक आदिवासी कल्याण आयुक्त के बैंक खातों में पड़ा हुआ था।

  जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

- आदिवासी कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प.नि., आई.टी.डी.ए. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची को ₹ 2.96 करोड़ की राशि निर्गत (फरवरी 2013 से अगस्त 2014) किया जिसमें से मात्र ₹ 0.77 करोड़ का उपयोग किया जा सका एवं शेष ₹ 2.19 करोड़ सितम्बर 2014 तक संबंधित अभिकरणों के बैंक खातों में पड़ा हुआ था।

प.नि., आई.टी.डी.ए., राँची ने इसे स्वीकार किया और जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एवं आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं करने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। जिला .कल्याण पदाधिकारी, राँची ने भी स्वीकार किया और जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.8 लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव

ए.सी. विपत्रों की विशाल बकाया राशि का मुद्दा हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, राँची ने भी सरकार के मुख्य सचिव को ए.सी. विपत्रों के आहरण से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं को नियमित अंतराल पर इंगित किया था। उन्होंने योजना शीर्षों के अंतर्गत ए.सी. विपत्रों का आहरण एवं राज्य के संचित निधि से राशि का बैंक खातों में अंतरण को बंद करने की भी सिफारिश किए थे। यद्यपि यह देखा गया कि वर्ष 2012-14 के दौरान ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण में कमी आई तथापि वर्ष 2012-14 के दौरान जारी विपत्रों के लिए दीर्घ अवधि तक डी.सी. विपत्र नहीं जमा किए जाने की प्रवृति फिर भी जारी रहा।

3.3 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा

3.3.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. का डी.पी.सी. अधिनियम) की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 बतलाता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष, जो संस्थाओं/प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को सौंपेगें। अक्टूबर 2014 तक, सरकार के किसी विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, राज्य के वार्षिक लेखों से एकत्रित सूचना के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु पहचान किये गये 71 निकायों/संस्थानों में से 59 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों में की गई (16 निकायों के

लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 एवं एक निकाय के लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्ष 2013-14 की अवधि तक की गई), जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के अप्रस्तुतीकरण के कारण विधानमंडल/सरकार को उन तरीकों जिनमें उनके द्वारा स्वीकृत/भुगतित अनुदानों का उपयोग किया गया, के बारे आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को विरल बनाता है।

3.3.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे तीन स्वायत्त निकाय[17] है जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं का परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित, के वर्ष 2008-09 के लिये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) 8 अप्रैल 2013 को जारी किये गये। विधानमंडल में इसके उपस्थापन को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया गया एवं 22 नवम्बर 2013 में एस.ए.आर. मसौदा सदस्य सचिव, झालसा को जारी किया गया। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2014)।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया जा चुका है एवं वर्ष 2011-12 तक का एस.ए.आर निर्गत किया गया है। तथापि, वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. के राज्य विधान सभा में उपस्थापन की स्थिति की सूचना अप्राप्त है। वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2014)।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 के अनुसार रिम्स का लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा किया जाना है। तदनुसार, रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौपा गया जिसे अक्टूबर 2009 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वीकार किया गया था।

---

[17] (i) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) एवं (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञांन सस्थान (रिम्स)।

तथापि, सक्रिय अनुनय के बावजूद अक्टूबर 2014 तक वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु नहीं सौपें गए।

3.4 दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, इस क्षति के लिए जिम्मेदार दलों द्वारा क्षतिपूर्ति कर लिये जाने की स्थिति में भी, कार्यालय द्वारा उच्चतर पदाधिकारियों, वित्त विभाग सहित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए; जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जानी चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा हेतु सूचना उपलब्ध कराने (28 अप्रैल 2014 एवं 26 जून 2014) के जवाब में वित्त विभाग से कोई सूचना अक्टूबर 2014 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

3.5 निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने का निषेध करती है।

वर्ष 2013-14 के लेखा के मुख्य शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देन से संबंधित व्हाउचर स्तरीय कम्प्युटरीकृत आँकड़े एवं वित्त लेखे के समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2014 तक राज्य में 101 व्यक्तिगत बही खाते थे।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान पी.एल. खाते के अधीन अंत शेष सतत रूप से बढ़ा जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान इसमें कमी आयी, जैसा कि **तालिका 3.7** में दिखाया गया है।

तालिका 3.7: व्यक्तिगत बही खाते निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2010-11	1457.58	1940.34	1670.78	1727.14
2011-12	1727.14	2248.95	1782.95	2193.14
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43
2013-14	2954.43	2613.93	2970.86	2597.50

तालिका 3.7 से देखा जा सकता है कि ₹ 2,597.50 करोड़ की अत्यधिक निधि को मार्च 2014 के अंत में पी.एल. खाते में रखा गया।

अतएव, सरकारी धनराशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया।

3.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान आहरित किये गये जी.आई.ए. विपत्र के विरूद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 6,543.82 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया था। जी.आई.ए. विपत्र की बड़ी राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की अप्राप्ति, विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

  यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करें।

- उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बकाया रहने का कारण, अनुदानों के अनुचित विमोचन एवं विलम्बन, अनुदानों के आहरण का असमाशोधन एवं अवरोधन, अनुदानों के आंशिक उपयोग या अनुपयोग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का उपस्थापन नहीं होना था।

यह अनुशंसा की जाती है कि अनुदानों के विमोचन में विलम्ब होने से बचाने तथा उसके कार्यों के भौतिक और वित्तीय प्रगति की देख-रेख एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर मोनिटरिंग की जानी चाहिए। यह भी अनुशंसा की जाती है कि विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानों के अनुपयोग और अवरोधन से बचाने के लिये दृढ़तापूर्वक वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना चाहिए। जमा करने के बावजूद उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनावश्यक अप्राप्ति/विलम्ब दिखाये जाने से बचने के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बीच नियमित अन्तराल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का समाशोधन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलावे, यह भी अनुशंसा की जाती है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कोषागार से अनुदानों के वास्तविक आहरण एवं समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु विभागों द्वारा सहायता अनुदान संस्वीकृति की प्रक्रिया, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय द्वारा जी.आई.ए. के निकासी की अनुमति तथा अनुदानग्राही द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाना चाहिये।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा निधियों की निकासी

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा नहीं करने के कारण वर्ष 2000-14 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित किये गये ₹ 5,162 करोड़ की राशि जून 2014 तक बकाया थी।

  यह अनुशंसा की जाती है कि लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को ससमय जमा करना सुनिश्चित करें।

- केन्द्र सरकार से अनुदानों के रूप में आवंटित निधियों के लिये, राज्य बजट में सहायता अनुदान का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप इसका आहरण ए.सी. विपत्रों के माध्यम से किया गया। ए.सी. विपत्रों को उन उद्देश्यों के लिये आहरित की गई जिसके लिये अग्रिम आहरण की अनुमति नहीं थी। विभागों द्वारा योजना व्यय के लिए ए.सी. विपत्रों पर आहरण किया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि केन्द्र सरकार से अनुदानों के रूप में आवंटित निधियों के लिये राज्य बजट में सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिये तथा ऐसे निधियों को ए.सी. विपत्रों पर आहरित न करके जी.आई.ए. विपत्रों पर ही आहरित किया जाना चाहिये।

- बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से योजना निधि का, बगैर शीघ्र भुगतान की आवश्यकता के, बार-बार आहरण किया गया। आगे, ए.सी. विपत्रों से आहरित अप्रयुक्त निधियों को सरकारी खाते में नहीं रखकर बैंक खाते में रखा गया।

  यह सिफारिश की जाती है कि बिना आकस्मिक प्रकृति के व्यय के लिए ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण को प्रतिषेध किया जाना चाहिए एवं ए.सी. विपत्रों से आहरित अप्रयुक्त राशि को शीघ्र सरकारी खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए।

- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिये डी.सी. विपत्रों के उपस्थापन संबंधी गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बार-बार ए.सी. विपत्रों का आहरण किया गया।

  यह अनुशंसा की जाती है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों *द्वारा नये ए.सी. विपत्र जारी करने से पहले, पूर्व में निर्गत ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्रों के वास्तविक उपस्थापन को सत्यापित करने के लिए कोषागार में एक उपयुक्त तंत्र का गठन किया जाना चाहिए।*

लेखे तथा स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उपस्थापन

- सरकारी विभागों द्वारा अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय उपस्थापित नहीं किये गये है। विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानमंडल में उपस्थापन की स्थिति की सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नहीं दी गयी है।

  यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

व्यक्तिगत बही खाते में जमा निधि

- व्यक्तिगत बही खाते में मार्च 2014 के अंत तक ₹ 2,597.50 करोड़ की विशाल राशि शेष थी। विधानमंडल द्वारा चालू वर्ष के लिए पारित की गई बजटीय निधियों को आगामी वर्षों में व्यय के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण, वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

  यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्तिगत बही खाते में निधियों को पार्क करने से बचना चाहिए एवं निधियों को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर व्यय कर लिया जाना चाहिए जिस वर्ष के लिए यह बजट में उपलब्ध कराया गया था।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - ए

(संदर्भ कंडिका - झारखण्ड की रूपरेखा पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय				
ए	**सामान्य आँकड़ा**			
क्र.सं.	**विवरण**			**आँकड़ा**
1	क्षेत्रफल			79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार		2.69 करोड़
	(बी)	2010-11		3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय धनत्व=325 व्यक्ति प्रति कि.मी.)		338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व= 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या[1] (आखिल भारतीय अनुपात 21.92 प्रतिशत)			40.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 प्रतिशत)		44 *प्रतिशत*
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 74.04 प्रतिशत)		67.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)			42
7	गिनी गुणांक[3]			
	(ए)	ग्रामीण(अखिल भारत-0.29)		0.24
	(बी)	शहरी (अखिल भारत-0.38)		0.36
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2013-14			₹ 172773 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14)		झारखण्ड	10.93 प्रतिशत
			सामान्य श्रेणी राज्य	14.88 प्रतिशत
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14)		झारखण्ड	12.52 प्रतिशत
			सामान्य श्रेणी राज्य	15.49 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि (2004-05 से 2013-14)		झारखण्ड	13.69 प्रतिशत
			सामान्य श्रेणी राज्य	12.94 प्रतिशत

ब. वित्तीय आँकड़ा[4]

क्र.सं.	**विवरण**		**आँकड़ा (प्रतिशत में)**		
	सी.ए.जी.आर.		**2004-05 से 2012-13**		**2004-05 से 2013-14**
			सामान्य श्रेणी राज्य	**झारखण्ड**	**झारखण्ड**
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	17.84	18.58
2.	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	16.42	16.75	18.83
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	12.49	16.35	14.54
4.	डी.	कुल व्यय का	15.37	15.54	17.78
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	17.01	15.49	19.14
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	15.97	15.91
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	9.58	17.90
8	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	14.73	@	@
9.	आई.	पेंशन का	18.34	21.43	22.52

---

[1] तेन्दुलकर प्रक्रिया विज्ञान द्वारा योजना आयोग बी.पी.एल. 2011-12 का प्रेस नोट जुलाई 2013

[2] एस.आर.एस. बुलेटिन सितम्बर 2013

[3] वर्ष 2009-10 के योजना आयोग के आँकड़े

[4] वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित

गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा का अनौपचारिक आकलन, 61वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.), गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय के असमानता की माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आंका जाता है, शून्य के नजदीक होने पर असमानता कम तथा एक के नजदीक होने पर असमानता अधिक होगी।

@ वर्ष 2003-04 के लिए वेत्तन एवं भत्ते के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.1 भाग-बी

सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिक निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग-2: आकस्मिक निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग-3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - सी: वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्राय: वित्तीय सम्पतियाँ होती है जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियों ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं.2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं.3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं.4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं.5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं.6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं.7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी 1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं.8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्त्ता संस्थान के ग्रुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.12	लघु शीर्षों द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं.13	वर्ष 2013-14 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.14	वर्ष 2013-14 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाईल को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2014 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.17	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्पलावकता को-एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद *(₹ करोड़ में)*	100621	127281	135618	151655	172773
स.रा.घ.उ. की विकास दर	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9
स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार					

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा **घटाव** सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, शीर्ष 2048 के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्तियाँ **घटाव** बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्तियाँ

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े

(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 13 एवं 42)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**15118(82)**	**18781(88)**	**22420(89)**	**24770(83)**	**26137(85)**
(i) कर राजस्व	**4500(30)**	**5717(30)**	**6954(31)**	**8224(33)**	**9380(36)**
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3597(80)	4473(78)	5522(79)	6422(78)	7305(78)
राजस्व उत्पाद	323(7)	388(7)	457(7)	578(7)	628(7)
वाहनों पर कर	234(5)	312(6)	392(6)	465(6)	495(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	238(5)	328(6)	401(6)	492(6)	502(5)
भू-राजस्व	41(1)	131(2)	53(1)	96(1)	230(3)
माल एवं यात्रियों पर कर	13	21	41(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	54(2)	64(1)	88(1)	170(2)	219(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	**2254(15)**	**2803(15)**	**3038(14)**	**3536(14)**	**3753(14)**
(iii)संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	**5547(37)**	**6154(33)**	**7170(32)**	**8188(33)**	**8939(34)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**2817(18)**	**4107(22)**	**5258(23)**	**4822(20)**	**4065(16)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**22**	**24**	**24**	**43**	**23**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**15140**	**18805**	**22444**	**24813**	**26160**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**3369(18)**	**2447(12)**	**2671(11)**	**5199(17)**	**4703(15)**
आंतरिक ऋण(अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	3379	2315	2409	4591	4281
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	229	369	316
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	-10	132	33	239	106
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**18509**	**21252**	**25115**	**30012**	**30863**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**8242**	**7721**	**10813**	**14495**	**14275**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**26751**	**28973**	**35928**	**44507**	**45138**
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**15128(83)**	**17945(86)**	**20992(86)**	**23400(83)**	**23472(83)**
योजना	3758(25)	6004(33)	7646(36)	7743(33)	6288(27)
गैर योजना	11370(75)	11941(67)	13346(64)	15657(67)	17184(73)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6605(44)	6991(39)	7846(37)	8696(37)	9960(42)
सामाजिक सेवाएँ	5610(37)	6707(37)	7287(35)	8309(36)	8215(35)
आर्थिक सेवाएँ	2913(19)	4247(24)	5859(28)	6395(27)	5297(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	-	-	-	शून्य	शून्य

11. पूँजीगत व्यय	**2703(15)**	**2664(13)**	**3159(13)**	**4218(15)**	**4722(17)**
योजना	2682(99)	2621(98)	3111(98)	4151(98)	4706(100)
गैर योजना	21(1)	43(2)	48(2)	67(2)	16(0)
सामान्य सेवाएँ	112(4)	120(4)	156(5)	176(4)	168(3)
सामाजिक सेवाएँ	825(31)	682(26)	866(27)	1030(25)	924(20)
आर्थिक सेवाएँ	1766(65)	1862(70)	2137(68)	3012(71)	3630(77)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	**320(2)**	**308(1)**	**217(1)**	**601(2)**	**222(1)**
13. कुल (10+11+12)	**18151**	**20917**	**24368**	**28219**	**28416**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**1190**	**1299**	**1639**	**2183**	**1997**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1068(90)	1063(82)	1406(86)	1525(70)	1542(77)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	78(5)	520(24)	316(16)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	123(10)	236(18)	155(9)	138(6)	139(7)
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	**-**	**-**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**19341**	**22216**	**26007**	**30402**	**30413**
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. लोक लेखा संवितरण	**7290**	**7400**	**9728**	**13417**	**14094**
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	**26631**	**29616**	**35735**	**43819**	**44507**
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	**(-)10**	**(+)836**	**(+)1428**	**(+)1370**	**(+)2665**
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	**(-)3011**	**(-)2112**	**(-)1924**	**(-)3406**	**(-)2256**
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (21-23)	**(-)704**	**(+) 116**	**(+)343**	**(-)1015**	**(+)358**
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान(राजस्व व्यय में सन्निहित)	**2307**	**2228**	**2267**	**2391**	**2614**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**2333**	**3122**	**4530**	**6950**	**6422**
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	**-**	**-**	**6**	**13**	**8**
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	-	6	13	8
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**0.03**	**0.32**	**0.21**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	**100621**	**127281**	**135618**	**151655**	**172773**
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	**27165**	**28655**	**30664**	**34869**	**37594**
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹एक करोड़ तथा उससे अधिक)	**262**	**167**	**182**	**189**	**328**
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**1466**	**1503**	**573**	**1972**	**760**

भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.5	4.5	5.1	5.4	5.4
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2
केंद्रीय अंतरण/ स.रा.घ.उ.	8.3	8.1	9.2	8.6	7.5
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	18.0	16.4	18.0	18.6	16.4
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	120.1	111.4	108.7	113.9	108.7
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.3	85.8	86.1	82.9	82.6
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	35.8	35.4	33.5	33.2	32.2
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	27.2	30.6	33.6	35.3	32.1
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.9	12.7	13.0	14.9	16.6
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.3	12.2	12.3	14.3	16.0
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	0.0	0.7	1.1	0.9	1.5
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-3.0	-1.7	-1.4	-2.2	-1.3
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.7	0.1	0.3	-0.7	0.2
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.3	-39.6	-74.2	-40.2	-118.1
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.रा.घ.उ.	2.3	2.4	2.7	2.5	3.1
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	27.0	22.5	22.6	23.0	21.8
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	179.7	152.6	136.8	140.8	143.8
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)647	(+)5145	(+)30	(+)1388	(+)2698
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	3.1	4.3	3.9	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	0.4	1.17	15.00	18.00
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2077	4014	6855	5782	6208
वित्तीय परिसम्पति/दायित्व	85	89	95	98	100

@ स.रा.घ.उ. के आँकड़े, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट से प्राप्त।

कोष्ठक में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 1.4 भाग - ए
वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2012-13			2013-14	2012-13		गैर योजना	योजना	कुल	2013-14
अनुभाग क: राजस्व									
24769.56	I राजस्व प्राप्तियाँ		**26136.80**	23399.87	I राजस्व व्यय	17184.41	6287.48	23471.89	23471.89
8223.67	कर राजस्व	9379.79		8696.49	सामान्य सेवाएँ	9691.69	267.67	9959.36	
				8308.59	सामाजिक सेवाएँ	4299.54	3915.80	8215.34	
3535.63	कर भिन्न राजस्व	3752.71		4411.28	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2876.19	1045.97	3922.16	
				808.74	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	604.47	372.63	977.10	
8188.05	संघीय करों में राज्य के हिस्से	8939.32		642.06	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	300.97	409.43	710.40	
				46.27	सूचना एवं प्रसारण	40.51	12.61	53.12	
1483.41	गैर योजना अनुदान	1319.91		563.88	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	92.51	532.33	624.84	
2393.94	राज्य योजना हेतु अनुदान	1565.83		150.43	श्रम एवं श्रम कल्याण	45.61	82.13	127.74	
				1668.48	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	318.72	1460.70	1779.42	
944.86	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1179.24		17.45	अन्य	20.56	0.00	20.56	
				6394.79	आर्थिक सेवाएँ	3193.18	2104.01	5297.19	
				992.44	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	418.62	556.40	975.02	
				1768.17	ग्रामीण विकास	610.13	819.44	1429.57	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				281.40	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	303.39	0.69	304.08	
				1560.20	ऊर्जा	1502.36	18.41	1520.77	
				220.11	उद्योग एवं खनिज	44.00	142.09	186.09	
				725.86	परिवहन	244.32	7.31	251.63	
					विज्ञान, तकनीकि एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				846.61	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	70.36	559.67	630.03	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				23399.87	**कुल**	17184.41	6287.48	23471.89	
	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			1369.79	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				**2664.91**
24769.56	**कुल**	**26136.80**		**24769.56**	**कुल**				**26136.80**

अनुभाग ख									
116.85	**III** आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	704.75			**III** रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV विविध पूँजीगत **प्राप्तियाँ**			4218.43	**IV** पूँजीगत परिव्यय	15.81	4706.69	4722.50	**4722.50**
				175.91	सामान्य सेवाएँ	15.81	152.28	168.09	
				1029.78	सामाजिक सेवाएँ	0.00	924.12	924.12	
				90.76	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		145.21	145.21	
				146.84	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		166.18	166.18	
				487.42	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास		342.07	342.07	
					सूचना एवं प्रसारण		0.00	0.00	
				194.39	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		168.03	168.03	
अनुभाग ख अन्य (क्रमश:)									
				110.37	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार		102.63	102.63	
					अन्य				
				3012.74	आर्थिक सेवाएँ		3630.29	3630.09	
				16.39	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		15.26	15.26	
				886.85	ग्रामीण विकास		1148.93	1148.93	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00	0.00	
				591.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		454.01	454.01	
					ऊर्जा		0.00	0.00	
				1.00	उद्योग एवं खनिज		2.00	2.00	
				1503.45	परिवहन		1994.65	1994.65	
				13.97	सामान्य आर्थिक सेवाएँ		15.44	15.44	
				4218.43	**कुल**	15.81	4706.69	4722.50	
43.11	**V** ऋण एवं अग्रिम का वसूली		**23.32**	600.81	**V** ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	29.92	191.99	221.91	
	विद्युत परियोजना से	0.00		541.70	विद्युत परियोजना को	0.00	175.34	175.34	
22.07	सरकारी सेवकों से	22.31		18.74	सरकारी सेवकों को	12.76	0.00	12.76	
21.04	अन्य से	1.01		40.37	अन्य को	17.16	16.65	33.81	
1369.69	**VI** नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		**2664.91**		**VI** नीचे लाया गया राजस्व घाटा				
5199.00	**VII** लोक ऋण प्राप्तियाँ		**4702.90**	2183.06	**VII** लोक ऋण पुर्नभुगतान			1996.92	**1996.92**
	बाह्य ऋण	-	-		बाह्य ऋण				

4591.56	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	4281.17		1524.50	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1542.59	
368.79	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	315.58		520.04	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन			315.58	
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-			ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन				
238.65	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	106.15		138.52	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुर्नभुगतान			138.95	
	VIII आकस्मिक निधि विनियोग				**VIII** आकस्मिक निधि विनियोग				0.00
	IX आकस्मिक निधि विनियोग				**IX** आकस्मिक निधि विनियोग				0.00
14494.71	**X** लोक लेखा प्राप्ति		**14275.26**	13416.31	**X** लोक लेखा संवितरण				**14094.33**
667.69	लघु बचत एवं भविष्य निधि	760.20		645.53	लघु बचत एवं भविष्य निधि			751.47	
279.80	रक्षित निधि	293.18		403.23	रक्षित निधि			21.29	
199.00	उचन्त एवं विविध	-58.77		167.60	उचन्त एवं विविध			-57.13	
4642.57	प्रेषण	6076.81		4784.27	प्रेषण			5920.48	
8705.65	जमा एवं अग्रिम	7203.84		7415.68	जमा एवं अग्रिम			7458.22	
	अन्तर्रा-ज्यीय समायोजन			100.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन			50.00	50.00
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			704.75	**XI** वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			1285.48	1285.48
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				-56.50	रिजर्व बैंक में जमा			428.20	
				14.68	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			5.44	
					चिन्हित निधि का निवेश				
				746.57	रोकड़ का निवेश			851.84	
45992.92	**कुल**		**48507.94**	**45992.92**	**कुल**				**48507.94**

परिशिष्ट 1.4 भाग - बी

31 मार्च 2014 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

31.03.13 को	दायित्व		31.03.14 को
25201.59	**आन्तरिक ऋण**		**27940.16**
11775.40	ब्याज वाले बाजार ऋण	14311.11	
0.18	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.00	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3635.54	अन्य संस्थाओं से ऋण	3968.24	
शून्य	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
9784.16	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियॉ	9654.51	
शून्य	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	0.00	
2124.55	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2091.95**
	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण		
6.38	गैर योजना ऋण	4.09	
2118.17	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2087.86	
150.00	**आकस्मिक निधि**		**150.00**
1549.86	**लघु बचत भविष्य निधि**		**1558.59**
5673.32	**जमा**		**5411.58**
319.67	**रक्षित निधि**		**591.56**
शून्य	**अंतरण शेष**	0.00	
109.87	**उचंत एवं विविध शेष**		**117.72**
	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		**2153.09**
35128.85	**कुल**		**40014.65**
	सम्पत्ति		
25749.35	**अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**30471.85**
107.11	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	140.35	
25642.24	अन्य पूँजीगत परिव्यय	30331.50	
100.00	**अन्तर्राज्यीय समायोजन**		**50.00**
7747.85	**ऋण एवं अग्रिम**		**7946.44**
7125.21	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	7300.55	
631.50	अन्य विकास ऋण	664.29	
(-)8.86	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-18.40	
12.72	**अग्रिम**		**5.35**
	उचंत एवं विविध शेष		
704.75	**नगद**		**1285.48**
शून्य	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0.00	
(-)56.50	रिजर्व बैंक में जमा	428.20	
शून्य	जमा निधि का निवेश	0.00	

14.68	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	5.44	
746.57	नगद शेष निवेश	851.84	
411.86	**प्रेषण शेष**		**255.53**
402.32	**सरकारी लेखे में घाटा**		**0.00**
1369.69	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
1772.01	वर्ष के शुरूआत में संचय घाटा/आधिक्य		
35128.85	**कुल**		**40014.65**

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

***परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4* से संबंधित विस्तार टिप्पणी**

पूर्ववर्त्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणयिों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यत: रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि ***परिशिष्ट 1.4 भाग बी*** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरित रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतेय या प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार आँकड़ों में विचलन या ह्रास वाली मदें इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। ₹ 68.34 करोड़ (निवल विकलन) के अंतर का समायोजन कर लिया गया है एवं अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ का समायोजन प्रक्रियाधीन है (अगस्त 2014)

परिशिष्ट 1.5

तेरहवें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे

(संदर्भ कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
19 वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-105-38	13वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	24.28	16.78	7.5
	2406-01-796-38	13वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	23.84	13.60	10.24
	उप योग		**48.12**	**30.38**	**17.74**
22 गृह विभाग	2055-00-796-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	11.00	11.00	शून्य
	2055-00-800-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	63.50	63.50	शून्य
	उप योग		**74.50**	**74.50**	**शून्य**
26 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-003-43	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 20 आई.आई.टी. का निर्माण	34.50	25.30	9.20
	2230-03-796-43	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 20 आई.आई.टी. के लिए भवनो का निर्माण	18.25	18.25	शून्य
	उप योग		**52.75**	**43.55**	**9.20**
27 विधि विभाग	2014-00-105-04	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत जिला न्यायधीश की सहायता हेतु न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति	1.58	1.06	0.52
	2014-00-105-05	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रात:/सांयकालीन न्यायालय का गठन	0.32	0.07	0.25
	2014-00-105-06	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत धरोहर न्यायालय भवन	2.97	शून्य	2.97
	2014-00-114-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचो का प्रशिक्षण	5.97	शून्य	5.97
	2014-00-114-09	न्यायिक अकादमी को आधारभूत संरचना	5.97	5.94	0.03
	2014-00-114-10	न्यायिक अकादमियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना	2.64	शून्य	2.64
	2014-00-114-11	वृहत लोक अदालत एवं विधिक सहायता	1.98	शून्य	1.98
	उप योग		**21.43**	**7.07**	**14.36**
35 योजना एवं विकास विभाग	3454-02-205-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिशों के प्रकाश में राज्य के सांख्यिकी तंत्र के लिए अनुदान	4.80	शून्य	4.80
	उप योग		**4.80**	**शून्य**	**4.80**

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-80-789-02	आपदा प्रबंधन विकास	2.00	शून्य	2.00
	2245-80-789-02	आपदा प्रबंधन विकास का सुदृढ़ीकरण	0.50	शून्य	0.50
	2245-80-796-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	2.50	शून्य	2.50
	उप योग		**5.00**	**शून्य**	**5.00**
42 ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-21	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर भवनों का निर्माण	30.37	25.63	4.74
	4515-00-796-21	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर भवनों का निर्माण	37.12	37.12	शून्य
	उप योग		**67.49**	**62.75**	**4.74**
45 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-001-61	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में विशिष्ट पहचान पत्र के अंतर्गत बी.पी.एल के पंजीकरण की सुविधा	57.91	57.90	0.01
	उप योग		**57.91**	**57.90**	**0.01**
48 शहरी विकास विभाग	2217-80-191-29	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर निगम को अनुदान	14.21	7.58	6.63
	2217-80-191-30	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामान्य निष्पादन के अन्तर्गत नगर निगम को अनुदान	12.00	शून्य	12.00
	2217-80-191-52	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	2.00	शून्य	2.00
	2217-80-192-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर परिषद को सामान्य आधारभूत अनुदान के लिए अनुदान	27.00	3.79	23.21
	2217-80-192-09	नगर परिषद को अनुदान	18.00	15.00	3.00
	2217-80-192-52	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर परिषद/नगरपालिका को विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	3.00	शून्य	3.00
	2217-80-192-53	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर परिषद/नगरपालिका को विशिष्ट क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	3.00	शून्य	3.00

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
48 शहरी विकास विभाग	2217-80-193-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर पंचायत को अनुदान	22.43	17.34	5.09
	2217-80-193-09	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर पंचायत को अनुदान	13.48	1.74	11.74
	2217-80-193-52	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	2.37	1.98	0.39
	2217-80-193-53	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	2.37	शून्य	2.37
	उप योग		**121.86**	**47.43**	**74.45**
49 जल संसाधन विभाग	2701-03-001-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रमुख सिंचाई योजना के लिए पोषण	24.67	शून्य	24.67
	उप योग		**24.67**	**शून्य**	**24.67**
50 लघु सिंचाईं विभाग	2702-02-005-05	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के लिए पोषण	2.33	शून्य	2.33
	उप योग		**2.33**	**शून्य**	**2.33**
51 कल्याण विभाग	2525-02-796-13	पी.टी.सी. व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं छात्रावास	31.25	शून्य	31.25
	उप योग		**31.25**	**शून्य**	**31.25**
52 कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	2205-00-106-29	13वें वित्त आयोग से संबंधित	9.00	8.00	1.00
	2205-00-796-29	13वें वित्त आयोग से संबंधित	16.00	14.00	2.00
	उप योग		**25.00**	**22.00**	**3.00**
55 ग्रामीण कार्य विभाग	2515-04-105-01	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत गैर पी.एम.जी.एस. वाई. सड़क के रख-रखाव एवं मरम्मत	28.09	17.41	10.67
	3054-04-105-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत गैर पी.एम.जी.एस. वाई. सड़क के रख-रखाव एवं मरम्मत	56.00	शून्य	56.00
	उप योग		**84.09**	**17.41**	**66.68**

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-196-02	जिला परिषद को विशेष क्षेत्र अनुदान	5.47	3.50	1.97
	2515-00-196-03	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत जिला परिषद को सामान्य क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	30.99	3.05	27.94
	2515-00-196-04	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत जिला परिषद को विशेष क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	5.47	शून्य	5.47
	2515-00-197-01	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	45.36	45.01	0.35
	2515-00-197-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र आधारभूत अनुदान	5.47	3.50	1.97
	2515-00-197-03	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	30.99	2.88	28.11
	2515-00-197-04	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को विशेष क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	5.47	शून्य	5.47
	2515-00-198-01	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	1.36	1.33	0.03
	2515-00-198-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को विशेष क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	16.39	10.5	5.89
	2515-00-198-03	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	92.97	9.17	88.80
	2515-00-198-04	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	16.39	शून्य	16.39
	उप योग		**256.33**	**78.94**	**177.39**
59 प्राथमिक व लोक शिक्षा विभाग	2202-01-111-33	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	1.43	शून्य	1.43
	2202-01-789-33	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	61.03	शून्य	61.03

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
59 प्राथमिक व लोक शिक्षा विभाग	2202-01-796-33	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	154.37	शून्य	154.37
	उप योग		**216.83**	**शून्य**	**216.83**
60 सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	4235-02-103-59	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण	54.00	48.62	5.38
	उप योग		**54.00**	**48.62**	**5.38**
	कुल		**1148.36**	**490.55**	**657.83**

परिशिष्ट *1.6 भाग - ए*

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 1.6.6; पृष्ठ 31)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औधोगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी. वातावरण का संरक्षण और परिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षाणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; शमशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.6 भाग - बी

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 1.6.6; पृष्ठ 33)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	हाँ
2	भूसुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक विकास	आंशिक
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यतायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विधुतिकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत ऊर्जा श्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नहीं
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समेत शिक्षा	आंशिक
18	तकनिकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विक्षिप्रों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषत: अ.जा.एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी

(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		राजस्व			
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	982.75	566.53	57.65
2	2	पशुपालन विभाग	162.13	35.53	21.91
3	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	33.37	15.84	47.47
4	8	नागर विमानन विभाग	23.23	22.20	95.57
5	10	ऊर्जा विभाग	2254.96	718.15	31.85
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1144.20	570.55	49.86
7	21	उच्च शिक्षा विभाग	662.98	171.20	25.82
8	23	उद्योग विभाग	291.98	120.80	41.37
9	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1018.25	308.12	30.26
10	35	योजना एवं विकास विभाग	642.89	533.61	83.00
11	39	आपदा प्रबंधन विभाग	464.06	147.99	31.89
12	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	397.45	125.67	31.62
13	41	पथ निर्माण विभाग	278.44	58.73	21.09
14	42	ग्रामीण विकास विभाग	756.87	218.12	28.82
15	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	73.19	18.45	25.21
16	47	परिवहन विभाग	117.78	95.49	81.07
17	48	शहरी विकास विभाग	1395.01	901.17	64.60
18	49	जल संसाधन विभाग	331.96	85.14	25.65
19	50	लघु सिंचाई विभाग	82.43	19.40	23.54
20	51	कल्याण विभाग	875.88	247.96	28.31
21	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	84.38	35.04	41.53
22	53	मत्स्य विभाग	53.81	18.07	33.59
23	54	डेयरी	117.78	48.97	41.58
24	55	ग्रामीण कार्य विभाग	205.88	78.30	38.03
25	56	पंचायती राज एवं एन0 आर0 ई0 पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग	2337.93	1468.05	62.79
26	58	माध्यमिक शिक्षा विभाग	799.93	217.04	27.13
27	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	4369.24	1740.27	39.83
28	60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	1236.38	395.33	31.97

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		पूँजीगत			
29	3	भवन निर्माण विभाग	185.90	72.95	39.24
30	8	नागर विमानन विभाग	279.99	169.99	60.71
31	9	सहकारिता विभाग	20.66	10.01	48.45
32	10	ऊर्जा विभाग	766.88	591.54	72.14
33	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	10.00	10.00	100.00
34	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	318.55	152.37	47.83
35	22	गृह विभाग	99.55	23.49	23.60
36	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	175.45	88.04	50.18
37	42	ग्रामीण विकास विभाग	599.00	349.58	58.36
38	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	170.15	117.59	69.11
39	45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	32.46	30.28	93.28
40	47	परिवहन विभाग	19.40	12.01	61.91
41	48	शहरी विकास विभाग	25.13	10.56	42.02
42	49	जल संसाधन विभाग	1660.00	1130.96	68.13
43	50	लघु सिंचाई विभाग	318.90	192.85	60.47
44	51	कल्याण विभाग	152.72	72.10	47.21
45	58	माध्यमिक शिक्षा विभाग	94.63	21.56	22.78
कुल			**26124.51**	**12037.60**	**46.08**

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2013-14 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण

(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1.	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-109-01	71.61	31.18	₹ 20 करोड़ के बचत का श्रेय कम संख्यायों में जनसेवक के कार्यग्रहण को बताया गया एवं ₹ 11.18 करोड़ के अंतिम बचत का कारण की सूचना अप्राप्त है।
2.		2401-00-796-91	130.00	73.05	कारण नहीं बताये गये हैं ।
3.		2401-00-800-91	102.74	45.29	कारण नहीं बताये गये हैं ।
4.		2401-00-796-78	27.00	27.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
5.		2401-00-796-85	21.60	21.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
6.	8-नागर विमानन विभाग	5053-80-800-01	169.99	169.99	कारण नहीं बताये गये हैं ।
7.	10-ऊर्जा विभाग	2801-01-800-02	31.00	27.19	कारण नहीं बताये गये हैं ।
8.		2801-80-800-07	115.00	115.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
9.		6801-00-789-03	67.91	46.86	कारण नहीं बताये गये हैं ।
10.		6801-00-796-03	147.13	101.54	कारण नहीं बताये गये हैं ।
11.		6801-00-800-03	350.85	242.13	कारण नहीं बताये गये हैं ।
12.		6801-00-201-09	93.00	93.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
13.		6801-00-201-24	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
14.		6801-00-796-09	39.00	39.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
15.	13-ब्याज संदाय	2049-01-123-01	1084.24	158.48	कारण नहीं बताये गये हैं ।
16.		2049-01-200-02	200.00	35.95	कारण नहीं बताये गये हैं ।
17.		2049-04-109-01	102.33	102.33	कारण नहीं बताये गये हैं ।
18.	14-ऋणकी वापसी/अदायगी	6003-00-105-01	350.00	48.75	कारण नहीं बताये गये हैं ।
19.		6003-00-109-01	150.00	85.18	₹ 8.22 करोड़ का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य को बताया गया एवं ₹ 76.96 करोड़ के अंतिम बचत का कारण की सूचना अप्राप्त है।
20.	15-पेंशन	2071-01-101-08	155.82	59.47	कारण नहीं बताये गये हैं ।
21.		2071-01-101-09	510.00	210.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
22.		2071-01-104-03	162.00	130.17	कारण नहीं बताये गये हैं ।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
23.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-13	126.23	22.03	कारण नहीं बताये गये हैं ।
24.		3456-00-102-27	34.86	34.61	₹ 19.05 करोड़ की बचत का श्रेय सिस्टम इंडीग्रेटर के लिए उचित निविदा की प्राप्ति नहीं होना बताया गया एवं ₹15.56 करोड़ की अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
25.		3456-00-102-31	77.01	46.75	कुल ₹ 46.75 करोड़ में से ₹ 1.46 करोड़ के बचत का श्रेय खाद्यानों के वितरण में बिलंब को बताया गया एवं ₹ 20 करोड़ एवं ₹ 25.29 करोड़ की सूचना अप्राप्त है।
26.		3456-00-789-31	33.00	27.94	₹ 2.55 करोड़ के बचत का श्रेय़ खाद्यानों के आपूर्ति में विलम्ब को बताया गया एवं आशंवित एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
27.		3456-00-796-13	206.06	41.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।
28.		3456-00-796-31	110.01	84.50	₹ 2.59 करोड़ के बचत का श्रेय़ खाद्यानों के आपूर्ति में विलम्ब को बताया गया एवं आशान्वित एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
29.		3456-00-102-28	59.08	59.08	कारण नहीं बताये गये हैं ।
30.		3456-00-102-29	31.00	31.00	आचार संहिता के कारण।
31.		3456-00-796-28	37.20	37.20	कारण नहीं बताये गये हैं ।
32.		3456-00-796-29	45.00	45.00	आचार संहिता के कारण।
33.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2211-00-101-01	94.18	41.04	कारण नहीं बताये गये हैं ।
34.		4210-02-796-29	36.00	29.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।
35.		4210-02-796-48	40.00	30.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
36.	21- उच्च शिक्षा	2202-03-796-34	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
37.	22-गृह विभाग	2055-00-110-01	188.27	43.76	कारण नहीं बताये गये हैं ।
38.		2055-00-115-43	131.74	52.77	कारण नहीं बताये गये हैं ।
39.	30- अल्पसंख्यक कल्याण	4225-80-796-12	94.97	52.72	कारण नहीं बताये गये हैं ।
40.	35- योजना एवं विकास विभाग	2235-02-102-01	75.63	39.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
41.		2235-02-796-01	75.71	42.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
42.		2053-00-094-31	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
43.		2053-00-796-24	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
44.		2053-00-796-25	200.00	200.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
45.		2053-00-796-31	77.35	77.35	कारण नहीं बताये गये हैं ।
46.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-01	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
47.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-796-04	22.12	22.12	कारण नहीं बताये गये हैं ।
48.		2029-00-796-04	22.12	22.12	कारण नहीं बताये गये हैं ।
49.	41-पथ निर्माण विभाग	3054-03-337-01	150.00	35.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
50.		5054-03-337-01	615.00	110.03	कारण नहीं बताये गये हैं ।
51.		5054-03-337-08	70.00	51.07	कारण नहीं बताये गये हैं ।
52.		5054-03-796-03	104.00	38.55	कारण नहीं बताये गये हैं ।
53.		5054-03-796-08	404.40	223.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
54.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-800-05	39.20	21.24	कारण नहीं बताये गये हैं ।
55.		2505-01-702-02	80.85	38.77	कारण नहीं बताये गये हैं ।
56.		4515-00-103-10	149.70	149.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
57.		4515-00-789-10	45.83	45.83	कारण नहीं बताये गये हैं ।
58.		4515-00-796-07	41.00	41.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
59.		4515-00-796-10	109.98	109.98	कारण नहीं बताये गये हैं ।
60.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-06	82.55	58.12	कारण नहीं बताये गये हैं ।
61.		4202-02-105-06 (सी.पी.एस)	55.00	55.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
62.	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-01	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
63.		3075-60-796-01	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
64.	48- शहरी विकास विभाग	2215-01-796-01	45.00	21.91	कारण नहीं बताये गये हैं ।
65.		2217-80-191-47	234.33	219.30	₹ 20 करोड़ के बचत का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
66.		2217-80-191-56	22.00	20.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
67.		2217-80-192-08	27.00	23.21	कारण नहीं बताये गये हैं ।
68.		2217-80-796-47	234.33	150.14	₹ 20 करोड़ के बचत का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
69.		2217-80-796-51	31.10	23.89	कारण नहीं बताये गये हैं ।
70.		2217-80-001-48	76.01	76.01	कारण नहीं बताये गये हैं ।
71.		2217-80-789-47	117.16	117.16	₹ 10 करोड़ के बचत का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
72.		2217-80-796-54	50.00	50.00	केन्द्र सरकार से निधि का विमोचन नही होना।
73.	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	139.47	20.79	कारण नहीं बताये गये हैं ।
74.		2701-03-001-18	24.67	24.67	कारण नहीं बताये गये हैं ।
75.		4700-80-796-10	800.00	426.69	कारण नहीं बताये गये हैं ।
76.		4700-80-796-11	130.00	129.98	कारण नहीं बताये गये हैं ।
77.		4700-80-789-09	35.00	35.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
78.		4700-80-789-10	400.00	400.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
79.		4700-80-796-09	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
80.	50- लघु सिचाई विभाग	4702-00-101-33	120.00	105.57	कारण नहीं बताये गये हैं ।
81.	51-कल्याण वभाग	2225-02-796-04	71.32	61.42	कारण नहीं बताये गये हैं ।
82.		2225-02-796-73	31.25	31.25	कारण नहीं बताये गये हैं ।
83.		4225-02-796-08	115.00	41.31	कारण नहीं बताये गये हैं ।
84.	55-ग्रामीण कार्य विभाग	3054-04-105-01	56.00	56.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
85.		4515-00-103-04	245.52	25.61	कारण नहीं बताये गये हैं ।
86.		4515-00-103-19	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
87.		4515-00-796-19	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
88.	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-15	145.40	100.93	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
89.		2515-00-001-38	200.00	132.00	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
90.		2515-00-196-03	30.99	27.93	केन्द्र सरकर से निधि का विमोचन नही होना।
91.		2515-00-197-03	30.99	28.11	केन्द्र सरकर से निधि का विमोचन नही होना।
92.		2515-00-198-03	92.97	83.79	केन्द्र सरकर से निधि का विमोचन नही होना।
93.		2515-00-789-15	85.00	76.51	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
94.		2515-00-789-38	80.00	63.00	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
95.		2515-00-796-15	195.00	175.39	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
96.		2515-00-796-38	230.00	145.00	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
97.		2515-00-001-29	200.00	200.00	एल.डबल्यू.ई. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए निधि उपलब्ध कराना।
98.		2515-00-789-29	80.00	80.00	एल.डबल्यू.ई. हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराना।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
99.		2515-00-796-29	230.00	230.00	एल.डबल्यू.ई. हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराना।
100.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	421.39	135.45	कारण नहीं बताये गये हैं ।
101.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2413.21	732.92	₹ 600 करोड़ का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं ₹ 132.82 के अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
102.		2202-01-101-03	174.00	51.54	कारण नहीं बताये गये हैं ।
103.		2202-01-101-27	36.00	21.05	कारण नहीं बताये गये हैं ।
104.		2202-01-111-25	206.00	109.18	कारण नहीं बताये गये हैं ।
105.		2202-01-789-03	74.00	29.88	कारण नहीं बताये गये हैं ।
106.		2202-01-789-25	87.55	46.40	कारण नहीं बताये गये हैं ।
107.		2202-01-796-03	187.00	50.26	कारण नहीं बताये गये हैं ।
108.		2202-01-796-25	221.45	117.37	कारण नहीं बताये गये हैं ।
109.		2202-01-796-27	38.70	23.80	कारण नहीं बताये गये हैं ।
110.		2202-01-111-33	143.60	143.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
111.		2202-01-789-33	61.03	61.03	कारण नहीं बताये गये हैं ।
112.		2202-01-796-33	154.37	154.37	कारण नहीं बताये गये हैं ।
113.	60- समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	194.40	69.92	कारण नहीं बताये गये हैं ।
114.		2235-02-103-71	20.50	20.44	कारण नहीं बताये गये हैं ।
115.		2235-02-796-51	210.60	66.18	कारण नहीं बताये गये हैं ।
116.		2235-02-796-71	24.00	23.90	कारण नहीं बताये गये हैं ।
117.		2236-02-101-02	92.25	22.69	कारण नहीं बताये गये हैं ।
कुल			**17531.83**	**9527.28**	

परिशिष्ट - 2.3

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ कंडिका : 2.4.5; पृष्ठ 61)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	आपदा प्रबंधन विभाग	61.33
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उधोग विभाग	7.49
2004-05	39	आपदा प्रबंधन विभाग	69.34
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2006-07	38	निबंधन विभाग	$
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
कुल			**9803.97**

स्रोत: संगत वर्षों के विनियोग लेखे :

** अतिरिक्त राशि केवल ₹ 8,807 थी।*

@ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 1,072 थी।

अतिरिक्त राशि केवल ₹ 49,670 थी।

$ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट - 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ कंडिका : 2.4.6; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (भारित)				
1	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	4618.20	4316.07	302.13	201.70
	कुल राजस्व भारित	**4618.20**	**4316.07**	**302.13**	**201.70**
	राजस्व (दत्तमत)				
2	1.कृषि गन्ना विकास विभाग	93941.03	41622.02	52319.01	4333.56
3	2-पशुपालन विभाग	15944.96	12659.60	3285.36	267.57
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	3160.61	1752.82	1407.79	175.99
5	7-निगरानी	1351.70	1261.05	90.65	40.43
6	8-नागर विमानन विभाग	2301.01	103.54	2197.47	22.22
7	9-सहकारिता विभाग	8294.45	7182.71	1111.74	101.02
8	10-ऊर्जा विभाग	175364.91	153681.89	21683.02	50131.53
9	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	5708.94	5291.84	417.10	400.50
10	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	99433.04	57365.26	42067.78	14987.20
11	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	30775.97	27105.74	3670.23	2379.43
12	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	113319.72	96662.82	16656.9	455.79
13	22-गृह विभाग	278670.68	268479.88	10190.8	9966.75
14	23-उद्योग विभाग	29093.82	17117.56	11976.26	104.19
15	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	99620.28	71012.95	28607.33	2204.91
16	27-विधि विभाग	20914.10	18393.82	2520.28	282.68
17	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	2697.40	1853.42	843.98	57.88
18	30-अल्पसंख्यक कल्याण	173.99	128.92	45.07	17.70
19	31-संसदीय कार्य	41.09	34.40	6.69	28.84
20	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1736.38	1720.24	16.14	314.92
21	35-योजना एवं विकास विभाग	64246.41	10928.17	53318.24	42.54
22	38-निबंधन विभाग	1977.20	1876.65	100.55	312.00
23	39-आपदा प्रबंधन विभाग	45876.26	31607.21	14269.05	529.91
24	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	39716.56	27177.94	12538.62	28.32

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (दत्तमत)				
25	41-पथ निर्माण विभाग	27711.40	21970.82	5740.58	132.22
26	42-ग्रामीण विकास विभाग	75660.37	53875.89	21784.48	27.04
27	43-विज्ञान एवं प्राद्यौगिक विभाग	7218.72	5473.40	1745.32	99.80
28	46-पर्यटन विभाग	931.45	841.60	89.85	62.95
29	48-शहरी विकास विभाग	128735.01	49383.94	79351.07	10766.19
30	49- जल संसाधन विभाग	33080.76	24682.19	8398.57	115.10
31	50- लघु सिचाई विभाग	8222.97	6302.58	1920.39	20.10
32	51- कल्याण विभाग	81063.80	62791.63	18272.17	6524.30
33	52- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	7859.07	4933.82	2925.25	578.89
34	54- डेयरी	11740.48	6881.19	4859.29	37.80
35	55-ग्रामीण कार्य विभाग	20136.54	12758.52	7378.02	451.59
36	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी.(विशेष प्रमंडल)	167228.33	86988.66	80239.67	66565.15
37	57-आवास विभाग	1039.18	132.66	906.52	47.00
38	58-माध्यमिक शिक्षा	74097.74	58289.35	15808.39	5895.65
39	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	123396.52	84104.99	39291.53	241.93
कुल राजस्व (दत्तमत)		**1902482.85**	**1334431.69**	**568051.16**	**178751.59**
कुल राजस्व		**1907101.05**	**1338747.76**	**568353.29**	**178953.29**
पूँजीगत (दत्तमत)					
40	3-भवन निर्माण विभाग	14600.00	11294.87	3305.13	3990.00
41	9-सहकारिता विभाग	1650.00	1065.00	585.00	416.00
42	20- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	29180.28	16617.96	12562.32	2675.00
43	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	36000.00	32101.76	3898.24	350.00
44	48-नगर विकास विभाग	2221.72	1457.68	764.04	291.47
45	49-जल संसाधन विभाग	164000.00	52904.44	111095.56	2000.00
46	50-लघु सिचाई विभाग	29860.00	12605.30	17254.70	2030.00
47	53-मत्स्य	700.00	376.20	323.80	36.80
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		**278212.00**	**128423.21**	**149788.79**	**11789.27**
सकल योग		**2185313.05**	**1467170.97**	**718142.08**	**190742.56**

परिशिष्ट 2.5

निधि का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(संदर्भ काकंडि : 2.4.7; पृष्ठ 62)

(₹ *लाख में*)

क्र सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचज (-)/ अधिक्य (+)
1.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-001-01	45.00	---	(-)16.71
2.		2403-00-103-03	15.00	---	(-)6.97
3.		2403-00-113-01	17.00	---	(-)0.73
4.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-05	52.87	---	(-)13.84
5.	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-105-01	0.44	---	(-)3.02
6.	7-निगरानी	2070-00-104-02	11.64	---	(-)4.50
7.		2070-00-104-03	0.39	---	(-)11.87
8.	12-वित्त विभाग	2052-00-090-08	4.13	---	(-)112.21
9.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3451-00-090-11	4.80	---	(-)9.86
10.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-13	200.00	---	(-)199.12
11.		2210-03-103-01	200.00	---	(-)585.28
12.	22-गृह विभाग	2055-00-001-04	35.00	---	(-)50.40
13.		2055-00-101-06	275.00	---	(-)5.89
14.		2055-00-104-04	400.00	---	(-)2.45
15.		2055-00-104-05	524.00	---	(-)285.59
16.	23-उद्योग विभाग	2851-00-103-01	4.59	---	(-)1.94
17.	27-विधि विभाग	2014-00-114-02	22.00	---	(-)146.20
18.	32-विधान मंडल	2011-02-103-01	38.50	---	(-)27.58
19.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2052-00-099-01	8.50	---	(-)3.74
20.	42-ग्रामीण विकास विभाग	3451-00-090-10	38.00	---	(-)19.04
21.	44-मानव संसाधन विकास विभाग	2251-00-090-01	27.28	---	(-)8.82
22.		2251-00-090-03	1.00	---	(-)5.90
23.	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-796-85	1.00	---	(-)41.00
24.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-001-01	10.00	---	(-)7.45
कुल			**1936.14**	**---**	**(-)1570.11**
25.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-102-05	---	3.15	(+)28.45
26.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-13	---	52.87	(+)537.40
कुल			**---**	**56.02**	**(+)565.85**

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी

(संदर्भ कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
	राजस्व			
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	566.53	55.38	511.15
2	2-पशुपालन विभाग	35.53	31.77	3.76
3	3-भवन निर्माण विभाग	11.39	0.00	11.39
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	15.84	0.23	15.61
5	7-निगरानी	1.31	0.02	1.29
6	8-नागर विमानन विभाग	22.20	0.00	22.2
7	9-सहकारिता विभाग	12.13	10.38	1.75
8	10- ऊर्जा विभाग	718.15	502.54	215.61
9	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	5.48	0.00	5.48
10	12-वित्त विभाग	9.77	0.00	9.77
11	18- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	570.55	274.29	296.26
12	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	60.50	4.96	55.54
13	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	171.13	10.53	160.60
14	21-उच्च शिक्षा	171.20	8.50	162.70
15	22-गृह विभाग	201.58	26.05	175.53
16	23-उद्योग विभाग	120.80	0.36	120.44
17	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	6.82	1.15	5.67
18	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	308.12	9.35	298.77
19	27-विधि विभाग	28.03	0.00	28.03
20	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	5.04	0.00	5.04
21	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	9.02	0.20	8.82
22	35-योजना एवं विकास विभाग	533.61	190.63	342.98
23	38-निबंधन विभाग	4.13	0.00	4.13
24	39-आपदा प्रबंधन विभाग	147.99	0.00	147.99
25	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	125.67	6.57	119.10

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
26	41-पथ निर्माण विभाग	58.73	1.00	57.73
27	42-ग्रामीण विकास विभाग	218.12	8.54	209.58
28	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	18.45	10.00	8.45
29	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	19.24	8.36	10.88
30	47-परिवहन विभाग	95.49	75.00	20.49
31	48-शहरी विकास विभाग	901.17	139.95	761.22
32	49-जल संसाधन विभाग	85.14	0.60	84.54
33	50-लघु सिचाई विभाग	19.40	0.00	19.4
34	51-कल्याण विभाग	247.96	19.77	228.19
35	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	35.04	2.03	33.01
36	53-मत्स्य	18.07	13.30	4.77
37	55- ग्रामीण कार्य विभाग	78.30	0.00	78.30
38	58-माध्यमिक शिक्षा	217.04	37.40	179.64
39	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	1740.27	600.00	1140.27
40	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	395.33	0.41	394.92
पूँजीगत				
41	3-भवन निर्माण विभाग	72.95	39.90	33.05
42	8-नागर विमानन विभाग	169.99	0.00	169.99
43	10- ऊर्जा विभाग	591.54	0.00	591.54
44	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	10.00	0.00	10.00
45	12-वित्त विभाग	12.64	0.00	12.64
46	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	152.37	24.97	127.40
47	30-अल्पसंख्यक कल्याण	88.04	3.90	84.14
48	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	42.48	22.00	20.48
49	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1.44	0.00	1.44
50	41-पथ निर्माण विभाग	348.68	250.00	98.68
51	42-ग्रामीण विकास विभाग	349.58	137.74	211.84
52	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	117.59	92.60	24.99
53	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	30.28	28.00	2.28
54	47-परिवहन विभाग	12.01	0.00	12.01
55	48-शहरी विकास विभाग	10.56	5.00	5.56

क्रं सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
56	49-जल संसाधन विभाग	1130.96	73.60	1057.36
57	50-लघु सिचाई विभाग	192.85	6.10	186.75
58	51-कल्याण विभाग	72.10	41.30	30.80
59	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	4.33	0.00	4.33
60	55-ग्रामीण कार्य विभाग	77.14	0.00	77.14
61	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2.73	0.00	2.73
62	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	5.37	0.00	5.37
कुल		**11505.90**	**2774.38**	**8731.52**

परिशिष्ट - 2.7

30 और 31 मार्च 2013 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि

(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1	2-पशुपालन विभाग	2403-00-106-12	10.58
2	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-101-12	500.00
3	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	6.76
4		2215-01-102-03	5.89
5	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-01	20.00
6		3075-60-101-03	10.00
7		3075-60-796-01	30.00
8		3075-60-796-03	15.00
9	49-जल संसाधन विभाग	4701-80-800-46	5.00
10	54-डेयरी	2404-00-796-27	8.28
11		2404-00-102-27	12.46
12	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष मंडल) विभाग	2515-00-001-38	132.00
13		2515-00-001-15	100.93
14		2515-00-789-15	76.51
15		2515-00-796-15	175.39
16		2515-00-796-38	145.00
17		2515-00-789-38	63.00
18		2515-00-198-02	5.89
19		2515-00-198-03	83.79
20		2515-00-198-04	16.39
21		2515-00-197-03	27.93
22		2515-00-197-04	5.47
23		2515-00-196-04	5.47
24		2515-00-196-03	27.93
25		2515-00-001-03	25.22
26	57-आवास विभाग	2216-02-796-06	5.00
कुल अनुदान			**1519.89**

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के अंत में व्यय का वेग

(संदर्भ: कंडिका 2.5 पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2014 के दौरान किया गया खर्च	मार्च 2014 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2014	मार्च 2014
1	कल्याण विभाग	4225	159.69	83.98	168.03	95.04	49.98
2	मानव संसाधन विभाग	2205	24.93	24.10	27.21	91.60	88.58
3	उद्योग विभाग	2852	44.82	42.65	58.48	76.63	72.93
4	कल्याण विभाग	2225	475.96	390.30	624.84	76.17	62.46
5	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401	208.52	168.51	275.14	75.78	61.24
6	ग्रामीण कार्य विभाग	2501	37.47	35.73	51.86	72.25	68.89
7	भवन निर्माण विभाग	4059	64.06	42.92	92.03	69.61	46.64
8	जल संसाधन विभाग	4701	97.03	69.93	146.71	66.14	47.67
9	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2015	25.51	22.35	39.06	65.32	57.23
10	गृह विभाग	4055	45.23	41.40	72.70	62.22	56.95
11	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2402	30.23	23.80	49.55	61.02	48.04
12	ग्रामीण कार्य विभाग	2515	685.93	626.53	1127.97	60.81	55.54
13	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	77.30	59.80	127.74	60.51	46.81
14	कल्याण विभाग	4235	59.99	38.25	102.63	58.45	37.27
15	पथ निर्माण विभाग	5054	1058.69	774.44	1877.26	56.40	41.25
16	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	93.63	67.55	166.18	56.34	40.65
17	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2415	45.43	23.49	82.06	55.37	28.63
18	शहरी विकास विभाग	2217	213.55	202.24	397.61	53.71	50.86
19	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203	72.72	64.49	137.09	53.05	47.04
20	उद्योग विभाग	2851	58.32	43.07	110.09	52.98	39.12

परिशिष्ट - 2.9

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2013-14 के दौरान असंशोधित रह गई

(प्रत्येक मामले मे ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग	29.12
2	सचिव, प्रशासन, वित्त विभाग	14.88
3	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग सेक्शन-iv ग्रामीण पुलिस आयुक्त, उत्तर छो. ना. प्रमंडल, हजारीबाग	2509.83
4	वित्त आयुक्त	52.62
5	सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	247.97
6	वाणिज्यिक कर आयुक्त, राँची	34.58
7	चुनाव आयोग, चुनाव विभाग	39.05
8	सचिव, ऊर्जा विभाग	1508.90
9	निदेशक, ऊर्जा विभाग	11.87
10	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनन विभाग	158.07
11	पंजीयक, उद्योग विभाग	21.08
12	म.नि. (कारा) गृह विभाग	18.48
13	पंजीयन के म.नि., पंजीयन विभाग राँची	13.38
14	अपर सचिव भवन निर्माण एवं आवास (पी.डब्ल्यू.डी. प्रमंडल) विभाग मुख्य अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग	
15	मुख्य अभियंता सड़क निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी.) विभाग	85.67
16	सचिव, पी.एच.ई.डी., झारखण्ड, राँची	224.59
17	सचिव, आवास विभाग, राँची मुख्य अभियंता, आवास विभाग	291.99
18	उप सचिव, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा उप सचिव, उच्च शिक्षा	39.12
19	उप सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	3810.65
20	निदेशक, खनन एवं भूगर्भ विभाग	14.83
21	सचिव, मंडल राजस्व विभाग	10.74
22	आयुक्त-सह-सचिव राजस्व विभाग, उप निदेशक सर्वेक्षण बंदोबस्त, झारखण्ड राँची	197.75
23	उत्पाद कर आयुक्त झारखण्ड राँची	13.79
24	अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा कल्याण विभाग	14.61
25	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड राँची	78.39

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
26	पंजीयक, सहकारी समिति, सहकारी विभाग	1055.06
27	सुयंक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	29.75
28	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग	189.53
29	सचिव, खाद्य एवं पोषण/खाद्य आपूर्ति विभाग	118.65
30	योजना एवं मूल्यांकन विभाग	911.42
31	निदेशक, परिवीक्षाधीन सेवा, झारखण्ड राँची	13.15
32	सचिव कल्याण विभाग	102.62
33	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	623.79
34	सचिव शहरी विकास विभाग	178.02
35	सचिव कल्याण विभाग । निदेशक, सामाजिक सुरक्षा विभाग	523.65
36	श्रम आयुक्त	1075.48
37	निदेशक, मृदा एवं जल संरक्षण	122.53
38	सचिव लघु सिंचाई, राँची	49.51
39	सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	34.14
40	निदेशक दुग्ध विकास विभाग	261.60
41	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	29.43
42	मत्स्य निदेशक झारखण्ड राँची	13.99
43	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	26.95
44	निदेशक पंचायती राज विभाग	249.73
45	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जे.एस.आर.टी.सी. झारखण्ड	2265.66
46	सचिव झारखण्ड विधान सभा	15.39
	कुल	**17380.93**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

परिशिष्ट - 2.10

बढा हुआ बजट आकलन

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 65)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आबंटन				बचत
		मूल आबंटन	अनुपूरक आबंटन	अभ्यर्पण	अंतिम आबंटन	
1	2210-01-001-06	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
2	2210-01-001-18	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3	2210-01-001-21	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	2210-01-001-37	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00
5	2210-01-109-17	105.56	0.00	0.00	105.56	105.56
6	2210-01-110-25	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7	2210-01-110-28	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00
8	2210-01-110-30	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
9	2210-02-200-04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
10	2210-02-200-05	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
11	2210-02-200-13	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
12	2210-02-200-17	5.57	0.00	0.00	5.57	5.57
13	2210-02-200-21	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00
14	2210-02-200-22	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00
15	2210-02-796-18	108.06	0.00	0.00	108.06	108.06
16	2210-02-796-19	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00
17	2210-02-796-20	2.94	0.00	0.00	2.94	2.94
18	2210-03-796-19	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	2210-03-800-16	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	2210-03-800-17	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
21	2210-03-800-18	670.00	0.00	27.80	642.20	642.20
22	2210-05-796-13	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
23	2210-05-796-14	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00
24	2211-00-001-01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
25	4210-01-110-07	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
26	4210-01-110-08	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
27	4210-01-110-10	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आबंटन				बचत
		मूल आबंटन	अनुपूरक आबंटन	अभ्यर्पण	अंतिम आबंटन	
28	4210-01-110-11	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00
29	4210-02-101-62	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
30	4210-02-110-13	287.40	0.00	0.00	287.40	287.40
31	4210-02-110-26	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
32	4210-02-110-36	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00
33	4210-02-796-61	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
34	4210-03-105-04	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00
कुल		**4804.04**	**0.00**	**27.80**	**4776.24**	**4776.24**

परिशिष्ट - 2.11

सतत् बचत

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशतता
2010-11	राजस्व	800.45	42.21	842.66	664.26	178.40	
	पूँजीगत	218.82	10.47	229.29	142.68	86.61	
	कुल	**1019.27**	**52.68**	**1071.95**	**806.94**	**265.01**	**24.72**
2011-12	राजस्व	1086.02	8.21	1094.23	816.30	277.93	
	पूँजीगत	341.25	0.00	341.25	163.54	177.72	
	कुल	**1427.27**	**8.21**	**1435.48**	**979.84**	**455.65**	**31.74**
2012-13	राजस्व	1105.87	19.66	1125.53	799.40	326.13	
	पूँजीगत	352.56	54.80	407.36	146.84	260.52	
	कुल	**1458.43**	**74.46**	**1532.89**	**946.24**	**586.65**	**38.27**

स्रोत: विनियोग लेखे 2010-2013

परिशिष्ट 2.12

रिक्त पदों के लिए परिहार्य बजट प्रावधान

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 65)

कार्यालय का नाम	शीर्ष	रिक्त पदों की संख्या	माँग की गई राशि *(₹ लाख में)*
रिनपास, काँके, राँची	गैर-योजना	179	498.53
	योजना	27	204.16
रिम्स, राँची	गैर-योजना	01	12.15
सदर अस्पताल, हजारीबाग	गैर-योजना	13	16.63
ए.सी.एम.ओ.,हजारीबाग	(सी.पी.एस)	02	9.26
ए.सी.एम.ओ.,जमशेदपुर	(सी.पी.एस)	03	6.64

परिशिष्ट 2.13

अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान

(संदर्भ: कंडिका 2.7.3 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	अंतिम	व्यय	मूल अनुदान से बचत
1	2210-01-001-02	1176.40	56.25	0.00	1232.65	1062.83	113.57
2	2210-01-001-04	749.77	4.15	0.00	753.92	732.39	17.38
3	2210-01-110-12	1787.05	56.00	0.00	1843.05	1471.18	315.87
4	2210-02-101-01	924.08	0.24	0.00	924.32	832.74	91.34
5	2210-03-101-02	4388.53	3.08	0.00	4391.61	3979.23	409.30
6	2210-03-103-01	12801.59	200.00	100.00	12901.59	12316.31	385.28
7	2210-03-103-03	7067.66	0.91	400.00	6668.57	5828.78	838.88
8	2210-03-110-04	3044.71	0.89	0.00	3045.60	2755.92	288.79
9	2210-04-102-01	306.18	0.43	28.73	277.88	225.89	51.56
10	2210-06-001-02	228.61	0.51	0.00	229.12	191.36	37.25
11	2210-06-101-01	870.88	34.37	0.00	905.25	844.91	25.97
12	2210-06-101-05	1503.84	82.10	0.00	1585.94	1503.43	0.41
13	2210-06-101-06	299.87	0.35	0.00	300.22	253.44	46.43
14	4210-01-110-04	150.00	200.00	0.00	350.00	126.22	23.78
15	4210-02-103-09	4690.00	500.00	0.00	5190.00	3888.07	801.93
16	4210-02-110-24	1220.00	300.00	0.00	1520.00	1180.96	39.04
कुल		**41209.17**	**1439.28**	**528.73**	**42119.72**	**37193.66**	**3486.78**

परिशिष्ट 2.14

व्यय का वेग (राज्य स्तरीय)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.5 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	आबंटन				व्यय		मार्च में प्रतिशत
		मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	अंतिम	मार्च में	कुल	
1	2210-01-001-13	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00
2	2210-01-001-20	50.00	0.00	0.00	50.00	30.00	30.00	100.00
3	2210-01-110-02	2.00	0.00	0.00	2.00	1.72	1.72	100.00
4	2210-01-110-10	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100.00
5	2210-01-110-11	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100.00
6	2210-01-110-16	2236.23	0.00	0.00	2236.23	2236.23	2236.23	100.00
7	2210-01-110-18	10.00	0.00	0.00	10.00	6.83	6.83	100.00
8	2210-01-110-26	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00
9	2210-01-110-36	200.00	0.00	0.00	200.00	105.26	105.26	100.00
10	2210-01-796-05	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	100.00
11	2210-06-104-02	3.00	0.00	0.00	3.00	0.09	0.09	100.00
12	4210-01-110-12	300.00	0.00	180.00	120.00	120.00	120.00	100.00
13	4210-02-103-07	450.00	0.00	0.00	450.00	223.59	223.59	100.00
14	4210-02-110-33	200.00	0.00	0.00	200.00	71.68	71.68	100.00
15	4210-02-796-33	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00
16	4210-02-796-48	4000.00	0.00	742.40	3257.60	930.49	930.49	100.00
17	4210-02-796-01	1265.21	0.00	0.00	1265.21	343.91	395.09	87.05
18	2210-01-110-24	1775.00	0.00	0.00	1775.00	706.23	817.00	86.44
19	2210-03-110-01	3.00	0.00	0.00	3.00	1.52	2.03	74.88
20	4210-02-110-34	220.00	0.00	0.00	220.00	101.14	149.79	67.52
21	4210-02-103-09	4690.00	500.00	0.00	5190.00	2616.28	3888.07	67.29
22	2210-01-001-05	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2027.61	3392.08	59.77
23	4210-02-796-39	1000.00	0.00	0.00	1000.00	422.11	714.05	59.11
24	4210-02-110-24	1220.00	300.00	0.00	1520.00	670.52	1180.96	56.78
25	4210-02-110-17	1348.56	0.00	0.00	1348.56	450.93	801.46	56.26
26	4210-02-103-08	2600.00	0.00	0.00	2600.00	660.03	1287.14	51.28
	कुल	**28021.00**	**800.00**	**922.40**	**27898.60**	**14124.17**	**18751.56**	

परिशिष्ट 2.15

व्यय का वेग (क्षेत्र इकाईयों)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.5 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत
1	का.अभि., दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	2153.86	574.86	26.69
2	का. अभि., उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	2003.00	533.00	26.61
3	का. अभि., कोल्हान प्रमंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	3210.00	1709.00	53.24
4	रिनपास,काँके	योजना	1795.31	512.11	28.52
5	अधीक्षक सदर अस्पताल, राँची	सामग्री एवं आपूर्ती	2.98	2.00	67.11
		मशीनी उपकरण	0.50	0.50	100.00
		यात्रा भ्त्ता	0.87	0.87	100.00
6	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची	दवाई	63.00	36.68	58.22
		वाह्य श्रोत	102.44	40.02	39.02
7	रिम्स	अनुवांशिक स्कन्द	105.26	105.26	100.00
8	अधीक्षक सदर अस्पताल, हजारीबाग	दवाई	19.99	10.19	51.00
		सामग्री एवं आपूर्ती	5.93	3.09	52.00
9	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर	दवाई	4.86	4.86	100.00
		वाह्य श्रोत	205.88	205.88	100.00
10	महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर	दवाई	146.19	67.82	46.00
11	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चायबासा	मशीनी उपकरण	1.10	1.10	100.00
	कुल		**9821.17**	**3807.24**	

परिशिष्ट 2.16

विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

(संदर्भ: कंडिका 2.7.6 पृष्ठ 68)

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	म.ले. (लेखा एवं हक.) के बही के अनुसार व्यय	समाशोधित व्यय	असमाशोधित व्यय
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	88599.70	980.75	87618.95
2211- परिवार कल्याण	7839.34	शून्य	7839.34
2251- सचिवालय सामाजिक सेवाऐं	223.78	शून्य	223.78
4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्ययय	16617.96	शून्य	16617.96
कुल	**113280.78**	**980.75**	**112300.03**

परिशिष्ट 2.17

डी.सी.विपत्र का अप्रस्तुतीकरण

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 69)

(₹ में)

मुख्य शीर्ष : 2210							
वित्तीय वर्ष 2013-2014							
कोषागार	मासिक अभिश्रव संख्या		डी.डी.ओ.	ए. सी. विपत्र संख्या	आहरित ए.सी. विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	शेष ए.सी. विपत्र
चतरा	3	00014	सी.टी.आर.एम.ई.डी.013	01/2013-14	13666666	0	13666666
देवघर	3	00023	डी.जी.आर.एम.ई.डी.डी.5	104/13-14	11702765	0	11702765
धनबाद	3	00011	डी.एच.एन.एम.ई.डी.072	55/2013-14	18413266	0	18413266
दुमका	3	00008	डी.एम.के.एम.ई.डी.079	72/13-14	12464166	0	12464166
डोरन्डा	2	00005	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	02/13-14	15000000	0	15000000
डोरन्डा	3	00034	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	29/13-14	1000000	0	1000000
डोरन्डा	3	00119	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	27/13-14	20000000	0	20000000
गोडा	3	00003	जी.डी.डी.एम.ई.डी.010	53/2013-14	12104966	0	12104966
गुमला	3	00009	जी.एम.एल.एम.ई.डी.010	66/2013-20	13416666	0	13416666
गढ़वा	3	00142	जी.आर.एच.एम.ई.डी.052	32/13-14	102675	0	102675
हजारीबाग	11	00010	एच.जेड.बी.एम.ई.डी.069	63/13-14	15000000	0	15000000
जामतारा	2	00004	जे.एम.टी.एम.ई.डी.058	27/13-14	2000000	0	2000000
जमशेदपुर	3	00013	जे.एस.आर.एम.ई.डी.031	89/13-14	4166666	0	4166666
खूँटी (उप कोषागार)	3	00005	के.एच.एन.एम.ई.डी.एल.05	23/13-14	11666682	0	11666682
लेहरदगा	3	00007	एल.डी.जी.एम.ई.डी.008	50/13-14	8018166	0	8018166
लातेहार	3	00009	एल.टी.आर.एम.ई.डी.047	38/13-14	5804164	0	5804164
पाकुड़	3	00009	पी.के.आर.एम.ई.डी.009	37/13-14	13666666	0	13666666
रामगढ़ (उप कोषागार)	3	00016	आर.जी.एच.एम.ई.डी.013	03/13-14	15166666	0	15166666
राँची	3	00014	आर.एन.सी.एम.ई.डी.013	7/13-14	15699276	0	15699276
राँची	3	00127	आर.एन.सी.एम.ई.डी.020	85/13-14	12000000	0	12000000
राँची	3	00159	आर.एन.सी.एम.ई.डी.020	84/13-14	600000	0	600000
साहिबगंज	3	00014	एस.बी.जे.एम.ई.डी.001	38/13-14	10081666	0	10081666
सिमडेगा	3	00011	एस.डी.जी.एफ.एम.डब्ल्यू.020	44/13-14	11561666	0	11561666
सिंहभूम	5	00008	एस.जी.एच.एम.ई.डी.075	01/2013-20	13000000	1217891	11782109
सरायकेला	3	00006	एस.के.एल.एम.ई.डी.112	32/2013-14	6000000	0	6000000
सरायकेला	7	00001	एस.के.एल.एम.ई.डी.112	04/2013	5000000	5000000	0
कुल					**267302788**	**6217891**	**261084897**

मुख्य शीर्ष : 2251							
वित्तीय वर्ष 2013-2014							
कोषागार	मासिक	अभिश्रव संख्या	डी.डी.ओ.	ए.सी. विपत्र संख्या	आहरित ए.सी. विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	शेष ए.सी. विपत्र
रॉची सचिवालय	3	00071	पी.आर.जे.एस.एस.एस.006	325/13-14	50000	0	50000
कुल					**50000**	**0**	**50000**

मुख्य शीर्ष : 4210							
वित्तीय वर्ष 2013-2014							
कोषागार	मासिक	अभिश्रव संख्या	डी.डी.ओ.	ए.सी. विपत्र संख्या	आहरित ए.सी.विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	शेष ए.सी. विपत्र
डोरन्डा	3	00001	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	28/13-14	12000000	0	12000000
डोरन्डा	3	00002	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	12/13-14	100000000	0	100000000
डोरन्डा	3	00003	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	05/13-14	7000000	0	7000000
डोरन्डा	3	00004	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	10/13-14	3000000	0	3000000
डोरन्डा	3	00005	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	11/13-14	1000000	0	1000000
डोरन्डा	3	00006	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	04/13-14	48000000	0	48000000
डोरन्डा	3	00007	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	07/13-14	5000000	0	5000000
डोरन्डा	3	00008	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	09/13-14	4000000	0	4000000
डोरन्डा	3	00009	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	08/13-14	5000000	0	5000000
डोरन्डा	12	00001	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	01/13-14	50000000	0	50000000
कुल					**235000000**	**0**	**235000000**

डीसी विपत्र के अप्रस्तुतीकरण का सारांश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	आहरित ए.सी.विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	बकाया ए.सी. विपत्र
1	2210	2673.03	62.18	2610.85
2	2251	0.50	0.00	0.50
3	4210	2350.00	0.00	2350.00
कुल		**5023.53**	**62.18**	**4961.35**

परिशिष्ट 3.1

वर्ष 2006-13 के दौरान आवंटित सहायता अनुदान के संदर्भ में 31 मार्च 2014 तक बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1 पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	वर्ष	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
	विभाग	उ.प्र प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि
1	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी.	72	140.95	26	48.13	55	251.03	38	156.86	99	250.84	64	259.97	566	1031.57	920	2139.35
2	नगर विकास	186	24.21	189	45.49	352	114.12	585	194	522	142.12	390	146.64	961	515.96	3185	1182.54
3	मानव संसाधन	4	16.17	3	1.72	3	4.29	5	1.55	5	5.47	4	27.20	8	792.65	32	849.05
4	परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	452.25	3	301.98	16	754.23
5	कल्याण	19	12.40	18	6.55	13	5.36	20	6.02	29	98.83	137	13.63	99	167.11	335	309.90
6	ग्रामीण विकास	2	20.00	0	0	0	0	1	0.16	1	2.00	0	0	13	215.00	17	237.16
7	योजना एवं विकास	5	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	11	152.26	14	1.40	30	191.16
8	पेयजल एवं स्वच्छता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	190.05	8	190.05
9	सहकारिता	10	5.79	12	4.08	6	7.71	8	9.23	34	97.53	9	5.48	50	17.75	129	147.57
10	नागर विमानन	0	0	0	0	1	1.06	0	0	1	7.29	2	65.41	3	40.00	7	113.76
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	110.09	4	110.09
12	ऊर्जा	2	17.38	0	0	1	1.50	1	30.00	4	24.66	0	0	0	0	8	73.54
13	उद्योग	0	0	0	0	0	0	30	42.61	22	18.31	2	1.81	1	1.00	55	63.73
14	कृषि एवं गन्ना	4	3.10	4	2.50	0	0	0	0	0	0	2	11.50	13	35.47	23	52.57
15	डेयरी विकास	6	0.19	21	4.29	2	6.00	2	4.00	0	0	0	0	23	16.05	54	30.53
16	गृह	22	1.51	21	2.56	55	5.33	76	7.45	134	7.49	37	2.47	2	2.08	347	28.89
17	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	0	0	0	0	2	6.78	0	0	0	0	0	0	8	11.28	10	18.06
18	वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.70	0	0	2	14.70
19	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	9.21	28	9.21
20	पर्यटन	1	0.50	1	0.50	15	7.45	0	0	0	0	1	0.50	0	0	18	8.95
21	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.00	0	0	2	5.00

क्रम. सं.	वर्ष	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
	विभाग	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि
22	पशुपालन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.85	4	3.07	6	4.92
23	आवास	0	0	3	1.80	0	0	0	0	3	0.80	4	1.50	0	0	10	4.10
24	कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	1	0.07	3	1.42	1	0.20	0	0	0	0	0	0	4	0.91	9	2.60
25	विधि	0	0	0	0	1	0.60	1	0.50	1	0.60	0	0	0	0	3	1.70
26	मत्स्य	0	0	0	0	0	0	5	0.25	0	0	0	0	0	0	5	0.25
27	भूमि राजस्व	1	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.21
	कुल	**335**	**279.98**	**301**	**119.04**	**507**	**411.43**	**772**	**452.63**	**855**	**655.94**	**682**	**1162.17**	**1812**	**3462.63**	**5264**	**6543.82**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, राँची का कार्यालय, द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

परिशिष्ट 3.2

कल्याण विभाग में बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.2.1 एवं 3.2.2 पृष्ठ 82 एवं 83)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी विपत्र		जमा किये गये डी.सी. विपत्र		बकाये डी.सी. विपत्र		अभियुक्ति
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2011-12	70	42.96	04	3.06	66	39.90	आठ ए.सी. विपत्र से संबंधित डी.सी. सौपा गया जिसमें से ₹ 1.90 करोड़ के चार ए.सी विपत्रों का पूर्णत: समायोजन किया गया एवं शेष ₹ 1.16 करोड़ का आंशिक समायोजन किया गया
2012-13	25	107.06	00	0.00	25	107.06	
2013-14	02	14.58	00	0.00	02	14.58	
कुल	**97**	**164.60**	**04**	**3.06**	**93**	**161.54**	

परिशिष्ट 3.3

नि.म.ले.प. डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1 पृष्ठ 90)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति (एन.जी.ओ.सी.), मोराबादी, राँची	राँची	2008-09
2	शिक्षा	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् , राँची	राँची	2006-07
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	बोकारो	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	चतरा	शून्य
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	देवघर	2012-13
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	धनबाद	2010-11
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	दुमका	2011-12
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पूर्वी सिंहभूम	2012-13
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गढ़वा	2011-12
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गिरिडीह	2012-13
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गोड्डा	2010-11
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गुमला	2010-11
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	हजारीबाग	2012-13
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	जामताड़ा	शून्य
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	खूँटी	2011-12
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	कोडरमा	शून्य
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लातेहार	शून्य
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लोहरदगा	2012-13
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पाकुड़	शून्य

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पलामू	शून्य
21	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	रामगढ़	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति, नामकुम)	राँची	2011-12
23	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	2011-12
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सरायकेला खरसावॉ	शून्य
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सिमडेगा	शून्य
26	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पश्चिम सिंहभूम	शून्य
27	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति))	साहेबगंज	शून्य
28	स्वास्थ्य	निदेशक, रिनपास कांके	राँची	2008-09
29	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	शून्य
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2011-12
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2012-13
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2012-13
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2011-12
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2011-12
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2012-13
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2012-13
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2012-13
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2004-05
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2011-12
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	09/2010

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
53	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
54	उद्योग	भारत- डेनमार्क यंत्र कक्ष, आदित्यपुर, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2012-13
55	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	बिरला तकनीकि संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2012-13
56	नागर विमानन	नागरिक विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2012-13
57	सूचना प्रौद्योगिकी	जैप. आई. टी.	राँची	2011-12
58	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
59	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2005-06
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2012-13
62	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2013-14
63	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	सूचना एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	10/2007
64	वन	लाख प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
65	वन	वन में लाख की फसल की कृषि, डोरण्डा	राँची	2008-09
66	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2009-10 2. 2011-12 3. 2011.12 4. 2008-09
67	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
68	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन फार्म, राँची	राँची	2008-09
69	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09
70	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
71	उच्च शिक्षा	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियॉ विविध पूँजीगत प्राप्तियॉ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियॉ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयाविधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिरूपनी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रयाप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियॉ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुऐ ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमश:

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरूद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणत: पंजीकृत समितियों एवं संविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यो को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते है।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्त्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ठ कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरनार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियॉ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियॉ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियॉ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के

परिशिष्ट 4.1 क्रमश:

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
	परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्राहित ऋण भी कहा जाता है। यह सामेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्र्यपण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तिय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्त्तमान वित्तिय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अप्रयाप्त पाया जाता है या वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियॉ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियॉ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तिय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जॉच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिशिष्ट - 4.1 क्रमश:

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी.बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी.बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी. ओ. आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नितिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर. ई.	राजस्व व्यय
आर. आर.	राजस्व प्राप्तियॉ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरियों
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी. ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर